Polity and Governance

1. CJI Ranjan Gogoi को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, पूर्व महिला कर्मी की शिकायत खारिज (Relevant for GS Prelims & GS Mains Paper II; Polity & Governance)

अमर्यादित आचरण के आरोपों के मामले में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई को सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कमेटी से क्लीनचिट मिल गई है। कमेटी ने महिला की शिकायत खारिज कर दी है। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने कहा है कि महिला की शिकायत में कोई ठोस तत्व नहीं मिला है।

सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की ओर से वेबसाइट पर जारी नोट में इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2003 के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

यह है मामला

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 22 न्यायाधीशों को हलफनामा भेजकर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर अमर्यादित आचरण के आरोप लगाए थे। महिला का आरोप था कि जब वह प्रधान न्यायाधीश के आवास स्थित दफ्तर में तैनात थी, उस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने उसके साथ अमर्यादित व्यवहार किया था। महिला ने अपनी शिकायत में दो घटनाओं का जिक्र किया था। आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट (सभी न्यायाधीशों की बैठक) में प्रस्ताव पारित कर आंतरिक जांच कमेटी गठित की गई थी।

कमेटी के बारे में

कमेटी का मुखिया प्रधान न्यायाधीश के बाद दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे को बनाया गया था और दो महिला न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस इंदू मल्होत्रा इसकी सदस्य थीं। पहले कमेटी में जस्टिस एनवी रमना शामिल थे जो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों में वरिष्ठता में तीसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन शिकायतकर्ता महिला की ओर से जस्टिस रमना को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद उन्होंने स्वयं को कमेटी से अलग कर लिया था। इसके बाद जस्टिस इंदू मल्होत्रा कमेटी में शामिल हुई थीं।

कमेटी ने जस्टिस अरुण मिश्रा को सौंपी रिपोर्ट

माना जा रहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जस्टिस अरुण मिश्रा को सौंपी है जो कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के वरिष्ठताक्रम में चौथे नंबर पर आते हैं। इसका कारण यह है कि आरोप स्वयं प्रधान न्यायाधीश पर लगे हैं। दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे आंतरिक जांच कमेटी के मुखिया थे। तीसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने स्वयं को कमेटी से अलग कर लिया था। इसलिए रिपोर्ट चौथे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश को सौंपी गई है। रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित न्यायाधीश यानी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को भी दी गई है।

शिकायतकर्ता के भाग नहीं लेने पर की एकतरफा सुनवाई

शिकायतकर्ता महिला ने जांच कमेटी की तीन कार्यवाहियों में हिस्सा लेने के बाद 30 अप्रैल को प्रेस रिलीज जारी कर कमेटी की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए उसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया था। महिला ने कहा था कि उसे वकील या सहयोगी को साथ रखने की इजाजत नहीं दी जा रही है। न ही कमेटी ने उसके बयान की प्रति उसे मुहैया कराई है। कमेटी की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकार्डिंग भी नहीं हो रही है।

महिला का कहना था कि कमेटी उसकी मांग नही मान रही है ऐसे में उसे कमेटी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। कमेटी ने महिला को पहले ही बता दिया था कि अगर वह भाग नहीं लेगी तो कमेटी एकतरफा सुनवाई करेगी। लिहाजा इसके बाद कमेटी ने एकतरफा सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया था।

सीजेआइ भी कमेटी में हुए थे पेश

कमेटी ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को कमेटी से मिलने के लिए लैटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था। जिस पर प्रधान न्यायाधीश कमेटी में पेश हुए थे और उन्होंने कमेटी के सवालों का जवाब भी दिया था।

सीजेआइ के खिलाफ आरोपों का यह मामला कुछ न्यूज वेबपोर्टलों की रिपोर्टो से 20 अप्रैल को सार्वजनिक हुआ था। आरोप सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटे बाद सीजेआइ ने शनिवार, 20 अप्रैल को जस्टिस अरुण मिश्रा और संजीव खन्ना के साथ एक अभूतपूर्व सुनवाई की थी।

हालांकि सीजेआइ ने सुनवाई के बीच में खुद को पीठ से अलग कर लिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने आरोपों को 'अविश्वसनीय' करार देते हुए कहा था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और वह आरोपों का खंडन करने के लिए भी उतने नीचे तक नहीं जा सकते।

2. सुप्रीम कोर्ट ने 31 जजों की पूर्ण स्वीकृत न्यायिक शक्ति को पूरा करने का लक्ष्य रखा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय में दो और न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की और सरकार द्वारा दो अन्य की पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया गया। इन दोनों नामों को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के लिए पहले भेजा गया था।

यदि चार न्यायाधीशों को बिना देरी के पदोन्नति दी जाती है, तो गोगोई अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद, जुलाई में फिर से खुलने तक, 31 न्यायाधीशों की पूर्ण स्वीकृत न्यायिक शक्ति तक पहुंच जाएगी। स्वीकृत न्यायिक शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है।

सरकार ने पहले भेजे गए 2 जजों के नाम खारिज कर दिए

सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, क्रमशः अनिरुद्ध बोस और ए.एस. बोपन्ना के नाम खारिज कर दिए। कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 12 अप्रैल को इन नामों की सिफारिश की थी।

नामों की अस्वीकृति पर कॉलेजियम की प्रतिक्रिया

कॉलेजियम ने कहा कि सरकार द्वारा अस्वीकृति अनुचित है। दो न्यायाधीशों के आचरण, क्षमता या ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। सरकार जस्टिस बोस और बोपन्ना को अदालत में नियुक्त करने के लिए बाध्य है।

2 और न्यायाधीशों ने पदोन्नति के लिए प्रस्ताव दिया

कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की भी सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए सिफारिश की।

जस्टिस गवई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन जजों को अतिष्ठित किया। कॉलेजियम ने कहा कि, हालांकि वरिष्ठता को उचित भारिता दी गई थी, लेकिन योग्यता "प्रमुख कारण" होना चाहिए। जस्टिस गवई अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं। उनकी नियुक्ति के बाद, सुप्रीम कोर्ट में एक दशक के बाद अनुसूचित जाति न्यायाधीश होगा।

सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया

न्यायाधीशों का कॉलेजियम राष्ट्रपति को उन नामों की सिफारिश करता है जो सरकार की ओर से नाम प्राप्त करते हैं। सरकार नामों को मंजूरी देती है। यदि वह असहमत होते हैं, तो नामों को समीक्षा के लिए कॉलेजियम को वापस भेज दिया जाता है।

(**Source:** https://www.thehindu.com/news/national/sc-collegium-recommends-justices-gavai-surya-kants-names-for-elevation/article27076939.ece)

3. चुनाव आयोग कैसे विकसित हुआ, असहमति के मामले में यह किन नियमों का पालन करता है (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

जहाँ तक चुनाव आयोग अपने काम को सर्वसम्मति से करना चाहता है, कमिश्नर अशोक लवासा ने हाल के कुछ मामलों में अपने सहयोगियों की राय से असहमति जताई है। किन परिस्थितियों में चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय बन गया? जब आयुक्त असहमत हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या है?

भारत का चुनाव आयोग (ECI) तीन सदस्यीय निकाय कब और किन परिस्थितियों में बना?

26 जनवरी 1950 से 1989 तक, संविधान के प्रारंभ से, ईसीआई एक एकल सदस्यीय निकाय था, जिसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) था। चुनाव आयोग ने नौवीं लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले विस्तार किया और तीन सदस्यीय निकाय बनाया।

भारत के चुनाव आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के निपटान की प्रक्रिया क्या है?

फाइलें आम तौर पर आयोग के सचिवालय में संबंधित अनुभागों / प्रभागों के स्तर पर शुरू की जाती हैं, और वे प्रासंगिक प्रभागों के उप चुनाव आयुक्तों (डीईसी) या निदेशकों के जनरल (डीजी) तक जाती हैं। DEC / DGs तब अपनी वरिष्ठता के क्रम में आयोग के निर्णयों या चुनाव आयोग को निर्देश की जरूरत वाली फाइलों को चिह्नित करते हैं। चुनाव आयोग की टिप्पणियों के साथ, फाइल अंततः सीईसी के पास जाती है।

कुछ मामलों में, जहां ईसी या सीईसी में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से चर्चा किए जाने की इच्छा रखता है, उस मामले को पूर्ण आयोग की बैठकों में जानबूझकर किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से संबंधित डीईसी और डीजी भी शामिल होते हैं। फिर उन बैठकों में लिए गए निर्णय औपचारिक रूप से संबंधित फाइल में दर्ज किए जाते हैं।

अगर चुनाव आयुक्तों में कोई असंतोष होता है, तो क्या होता है?

यदि मौखिक विचार-विमर्श और चर्चा के बाद भी कुछ मतभेद बने रहते हैं, तो ऐसी असहमति फ़ाइल में दर्ज की जाती है। सभी राय समान भारिता रखते हैं, जिसका अर्थ है कि सीईसी को दो ईसी द्वारा अधिभूत किया जा सकता है। सामान्य व्यवहार में, आयोग के निर्णय को संप्रेषित करते समय, बहुमत के दृष्टिकोण से संबंधित पक्षों को अवगत कराया जाता है। असहमति फ़ाइल में दर्ज रहती है।

हालांकि, 1993 के बाद से बहुमत से निर्णय लेने के प्रावधान के अस्तित्व के बावजूद, बहुत कम ही असंतोष दर्ज किया गया है। जब एक आयोग की बैठक में तीन आयुक्तों द्वारा किसी मामले पर विचार-विमर्श किया जाता है, तो वे आम तौर पर एक सामान्य कार्रवाई के लिए सहमत होते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आयुक्तों के बीच कोई असहमति नहीं है - अतीत में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां बैठक में भी सहमति नहीं बन पाई।

(**Source:** https://indianexpress.com/article/explained/an-expert-explains-how-election-commission-evolved-what-rules-it-follows-in-case-of-disagreement-5720029/)

4. तमिलनाडु में विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला क्या है? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल द्वारा सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के तीन विधायकों- ई.रथिनासाबापति (अरन्थांगी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए),वी.टी.कालिसेलवन (विरुधचलम) और ए.प्रभु (कल्लुकुरिची) को विरोधी दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के लिए शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी।

यह कैसे घटित हुआ?

यह आरोप लगाया गया कि विधायक टी.टी.वी. धिनकरन, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के महासचिव से जुड़े हुए थे। तीन दिन बाद, अध्यक्ष ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

विधायकों द्वारा दिया गया औचित्य क्या है?

बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दो तर्क दिए।

एक, उन्होंने स्पीकर पर "पक्षपातपूर्ण और पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने" का आरोप लगाया।

दो, उन्होंने तर्क दिया कि श्री धनपाल को अयोग्य मामले पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित था।

क्या विधायकों ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम छोड़ी है?

तीन विधायक इस बात से इनकार नहीं करते कि उनकी सहानुभूति श्री धिनकरन के साथ या, अधिक सटीकता के लिए, वी.के. शशिकला, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की विश्वासपात्र के साथ है और वह अब आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बेंगलुरु में जेल की सजा काट रही हैं। लेकिन तीनों का कहना है कि वे AMMK के सदस्य नहीं हैं। कुछ दिनों पहले, AMMK ने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग को आवेदन दिया था। AIADMK की योजना श्री धिनकरन को समर्थन देकर यह स्थापित करने की थी कि तीनों विधायकों ने पार्टी की "स्वेच्छा से सदस्यता" छोड़ दी थी। यह वही आधार था जिस पर सितंबर 2017 में 18 समर्थक धिनकरन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था।

इससे क्या फर्क पड़ता है?

वर्तमान में, तमिलनाडु विधानसभा में 22 रिक्तियां हैं। चुनाव खाली सीटों के लिए होने वाले हैं। AIADMK के अध्यक्ष सहित 114 विधायक हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई, तो विधानसभा की संख्या 231 हो जाएगी। उस स्थिति में, AIADMK को केवल 116 सदस्यों की आवश्यकता होगी, जो उसकी वर्तमान संख्या से सिर्फ दो अधिक है।

अयोग्यता पर क्या नियम हैं?

संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 के अनुसार, संसद या विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य को दो आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है:यदि सदस्य स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है; या, यदि सदस्य ऐसी पार्टी की किसी भी दिशा के विपरीत सदन में वोट देने से परहेज या वोट करता है। हालांकि, अयोग्य ठहराए जाने से बचा जा सकता है यदि पार्टी नेतृत्व 15 दिनों के भीतर वोट या मतदान में भाग नहीं लेता है। अयोग्यता के लिए प्रक्रिया (दल बदल के आधार पर नियम), 1986 तमिलनाडु विधान सभा के सदस्यों में रखी गई है। प्रत्येक राज्य के समान नियम हैं।

आगे क्या होगा?

विधानसभा अध्यक्ष और उनके कार्यालय पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद, सामान्य व्यवहार यह है कि विधानसभा सचिव जवाब दाखिल करेगा। 22 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के नतीजों का असर अब से होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। यदि सत्तारूढ़ AIADMK पर्याप्त संख्या में सीटें जीतती है, तो यह ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पहले लिया गया है या नहीं। यह विद्रोही विधायकों के तर्कों में से एक को प्रस्तुत करने का प्रभाव होगा:अपने स्वयं के निष्कासन के लिए प्रस्ताव का सामना करने वाले अध्यक्ष को अयोग्यता के मुद्दों को स्थगित नहीं करना चाहिए। कम से कम दो और विधायक हैं जिनके खिलाफ पार्टी AIADMK नेतृत्व के खिलाफ जाने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है।

यदि DMK सभी 22 सीटों पर जीत जाती है, तो एक शासन परिवर्तन हो सकता है, जो एक नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो सकता है। उस मामले में, अयोग्यता कार्यवाही को नहीं चलाया जा सकता है।

5. चुनाव आयोग ने कोलकाता में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को रोकने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान किया है। संविधान चुनाव आयोग को क्या शक्तियाँ देता है; SC ने अनुच्छेद 324 की व्याख्या कैसे की है? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

भारत के चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व आदेश पारित किया, जो 17 मई को शाम 5 बजे के बजाय पश्चिम बंगाल में अभियान को समाप्त करने के लिए 16 मई को शाम 10 बजे समाप्त हो गया, जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया था, और यह आदर्श है। इसने राज्य के गृह सचिव और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी हटा दिया।

ऐसा फैसला क्यों लिया गया?

कोलकाता में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क हिंसा के जवाब में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्णय लिए गए। एक महीने पहले, 15 अप्रैल को, ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले राजनेताओं को अनुशासित करने की उनकी शक्तियां "बहुत सीमित" थीं।

ECI की शक्तियाँ

अनुच्छेद 324 "चुनाव आयोग में" "चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" निहित करता है। संसद ने आयोग की शक्तियों को परिभाषित करने और विस्तार करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को लागू किया।

मोहिंदर सिंह गिल और अन्न बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और ओआरएस (1977) में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि अनुच्छेद 324 "कानून द्वारा अप्रभावित क्षेत्रों में संचालित होता है और शब्द 'अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' के साथ-साथ 'सभी चुनावों का संचालन' सबसे व्यापक शब्द हैं"। संविधान ने इन शब्दों को परिभाषित नहीं किया है। अनुच्छेद 324, अदालत ने कहा, "ईसीआई में राष्ट्रीय और राज्य के चुनावों के लिए पूरी ज़िम्मेदारी निभाने वाला एक पूर्ण प्रावधान है" और इसलिए, उस कार्य को करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ उसके पास हैं।"
महत्वपूर्ण रूप से, हालांकि, अदालत ने रेखांकित किया कि ईसीआई द्वारा शक्तियों को विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रयोग करना है।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/article-324-and-role-of-election-commission-india-5731889/)

6. चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल (Relevant for GS Mains Paper II; Polity & Governance)

1. 10 मार्च को 17वें आम चुनावों की चुनाव तारीखों की घोषणा की गई और 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 11 सप्ताह लगे; मतदान छह सप्ताह में फैल गया था। भारत के चुनाव आयोग की कवायद को लंबे समय तक खींचने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। इस तरह के लंबे समय के लिए एक औचित्य की अनुपस्थिति को देखते हुए, संदेह पैदा किया गया था कि क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक तरीके से अभियान में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

2. चुनाव आयोग ने श्री मोदी को अतीत में तय मानकों पर पकड़ बनाने में अनिच्छा दिखाई है। आरोप लगते रहे हैं कि श्री मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

3. तीन सदस्यीय आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही प्रश्न कहा गया था, जिसमें एक सदस्य ने दूसरों को सूचित किया था कि वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर बैठकों में भाग नहीं लेगा जब तक उसकी असहमति, जब तक न हो, अंतिम क्रम में दर्ज की जाती है।

चुनाव प्रचार की प्रकृति

कुछ स्व-परावर्तन के लिए कहा जाता है क्योंकि देश एक कड़वा लड़ा हुआ चुनाव संपन्न करता है जिसके दौरान नागरिक सार्वजनिक बहस की सीमाओं को पार किया गया है और मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। 2019 को क्या अभूतपूर्व बनाता है कि अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और गलत सूचना फैलाई गई थी। 2019 अभियान में, सरकार के नेताओं ने नौकरी सृजन और अन्य मापदंडों पर आधिकारिक डेटा को अवरुद्ध या दूषित करके, पांच साल के अपने प्रदर्शन पर एक तथ्य-आधारित बहस की शुरुआत की, और सफलतापूर्वक एक तथ्य-मुक्त क्षेत्र में भावनात्मकता और विभाजनकारी मुद्दों से भरे क्षेत्र में चुनावों को धकेल दिया। लोकतंत्र के लिए यह दोहरी मार थी। एक तरफ, सूचित चर्चा मुश्किल हो गई है, और दूसरी तरफ, सामाजिक तनाव बढ़ गया है।

(Source:https://www.thehindu.com/opinion/editorial/count-on-democracy/article27179337.ece)

7. विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं द्वारा मतदान (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

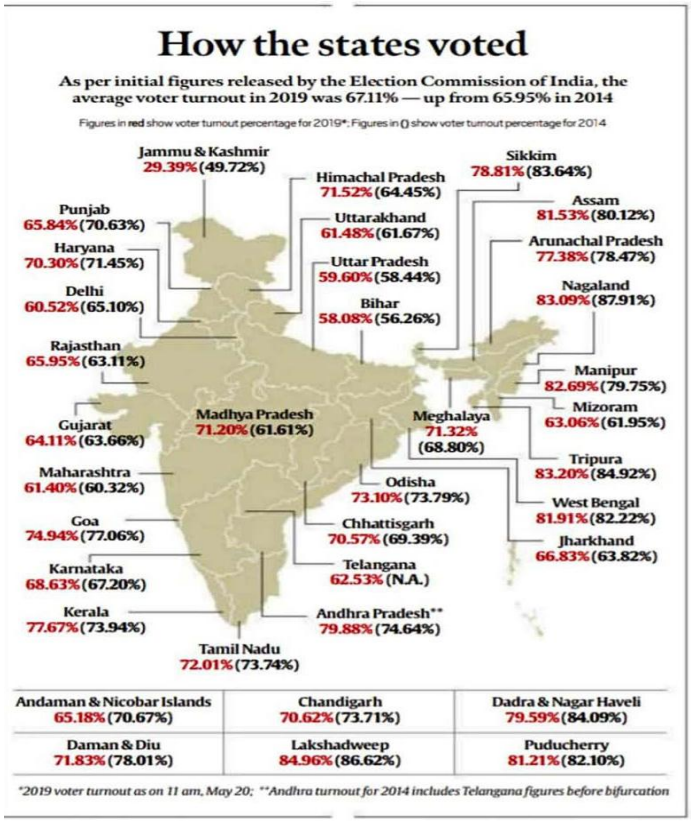

8. चुनाव परिणाम 2019: ईवीएम की गतिविधि पर विवाद, इन मशीनों को संग्रहीत करने के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर एक नज़र, उन्हें चुनावों के लिए कमीशन, और वे कैसे मजबूत कमरे से मतदान केंद्र और वापस यात्रा करते हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

22 विपक्षी दलों ने कथित रूप से संदिग्ध ईवीएम गतिविधि की रिपोर्टों को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, जबकि चुनाव आयोग ने ईवीएम के आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम की यात्रा को मजबूत कमरे से मतदान केंद्र और वापस यात्रा जाने के लिए किए गए प्रबंधों पर एक नज़र:

गैर-चुनाव अवधि के दौरान

जिले के सभी उपलब्ध ईवीएम सामान्य रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के सीधे नियंत्रण में एक कोषागार या गोदाम में संग्रहीत किए जाते हैं। अपवाद भंडारण स्थान की अनुपलब्धता के मामले में किए जा सकते हैं, लेकिन नामित खजाना या गोदाम तहसील के स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए। गोदाम को एक डबल लॉक, पुलिसकर्मियों या सुरक्षा गार्डों द्वारा चौबीसों घंटे सुरक्षित रखा जाता है, और सीसीटीवी निगरानी में भी रखा जाता है। एक गैर-चुनाव अवधि के दौरान, चुनाव आयोग के विशिष्ट निर्देशों के बिना ईवीएम को गोदाम से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। इंजीनियरों द्वारा ईवीएम की प्रथम-स्तरीय जाँच यहाँ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जाती है।

मतदान के दौरान

चुनाव की तारीख के करीब, ईवीएम को पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों (एक लोकसभा सीट में) को यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है। यदि प्रतिनिधि अनुपस्थित हैं, तो पार्टी कार्यालय के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की सूची साझा की जाती है। इस बिंदु से, विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) आवंटित मशीनों का प्रभार लेते हैं और उन्हें नामित मजबूत कमरों में संग्रहीत करते हैं।

यहां, अनियमितता का दूसरा दौर होता है। ईवीएम को पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विशिष्ट मतदान केंद्रों के लिए कमीशन किया जाता है। वास्तव में, उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित पोलिंग एजेंटों के साथ मशीन नंबर साझा करें ताकि वे मतदान शुरू होने से पहले इनका सत्यापन कर सकें।

सभी मशीनों को उम्मीदवारों की सेटिंग और बैलेट पेपर को ठीक करने के बाद तैयार किया जाता है, और फिर कमीशन किया जाता है, पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है, जो चाहें तो ताले पर अपनी मुहर भी लगा सकते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस

अधिकारी के पद पर एक उप-पुलिस अधीक्षक के रैंक के साथ स्ट्रांग रूम में चौबीसों घंटे पहरा दिया जाता है। यह केंद्रीय पुलिस बलों द्वारा भी, जहाँ भी संभव हो, पहरा दे सकता है।

एक बार सील हो जाने के बाद, स्ट्रांग रूम को एक निश्चित तिथि और समय पर ही खोला जा सकता है जब मशीनों को पोलिंग पार्टियों को उनके निर्दिष्ट मतदान केंद्रों तक पहुंचाना होता है। सभी उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों को पहले से ही स्ट्रांग रूम खोलने की तारीख और समय के बारे में सूचित कर दिया जाता है।

विशिष्ट मतदान केंद्रों को आवंटित मशीनों के अलावा, कुछ आरक्षित ईवीएम को भी स्ट्रांग रूम से लिया जाता है और विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय स्थान पर संग्रहीत किया जाता है, ताकि दोषपूर्ण मशीनों को यथासंभव कम देरी से बदला जा सके।

इस साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान अप्रयुक्त ईवीएम के संचलन और भंडारण पर पिछले साल के विवाद को देखते हुए, मतदान और अप्रयुक्त मशीनों को केवल जीपीएस-सक्षम वाहनों में ले जाया जा रहा है ताकि उनके आंदोलन को डीईओ और सीईओ द्वारा ट्रैक किया जा सके।

बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक

एक बार मतदान समाप्त हो जाने के बाद, EVM को तुरंत स्ट्रांग रूम में नहीं भेजा जाता है। मशीनों में दर्ज मतों का लेखा-जोखा तैयार करने के लिए पीठासीन अधिकारी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को इसकी एक सत्यापित प्रति प्रदान की जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को मुहरों पर अपने हस्ताक्षर लगाने की अनुमति है, जिसे वे छेड़छाड़ के किसी भी संकेत के लिए जांच सकते हैं। मतगणना केंद्र के करीब स्थित, मतदान केंद्र से ईवीएम ले जाने वाले वाहनों के पीछे उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान कक्ष से स्ट्रांग रूम तक जाते हैं।

रिजर्व ईवीएम को भी उसी समय लौटाया जाना चाहिए जब मतदान वाले ईवीएम वापस आ जाते हैं। एक बार सभी ईवीएम का उपयोग हो जाने के बाद, स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है और उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि को अपनी मुहरें या लॉक लगाने की अनुमति दी जाती है। उन्हें चौबीसों घंटे मजबूत कमरों पर नजर रखने की भी अनुमति है।

कुछ मामलों में, जहां ईसी या सीईसी में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से चर्चा किए जाने की इच्छा रखता है, उस मामले को पूर्ण आयोग की बैठकों में जानबूझकर किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से संबंधित डीईसी और डीजी भी शामिल होते हैं। फिर उन बैठकों में लिए गए निर्णय औपचारिक रूप से संबंधित फाइल में दर्ज किए जाते हैं।

अगर चुनाव आयुक्तों में कोई असंतोष होता है, तो क्या होता है?

यदि मौखिक विचार-विमर्श और चर्चा के बाद भी कुछ मतभेद बने रहते हैं, तो ऐसी असहमति फ़ाइल में दर्ज की जाती है। सभी राय समान भारिता रखते हैं, जिसका अर्थ है कि सीईसी को दो ईसी द्वारा अधिभूत किया जा सकता है। सामान्य व्यवहार में, आयोग के निर्णय को संप्रेषित करते समय, बहुमत के दृष्टिकोण से संबंधित पक्षों को अवगत कराया जाता है। असहमति फ़ाइल में दर्ज रहती है।

हालांकि, 1993 के बाद से बहुमत से निर्णय लेने के प्रावधान के अस्तित्व के बावजूद, बहुत कम ही असंतोष दर्ज किया गया है। जब एक आयोग की बैठक में तीन आयुक्तों द्वारा किसी मामले पर विचार-विमर्श किया जाता है, तो वे आम तौर पर एक सामान्य कार्रवाई के लिए सहमत होते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आयुक्तों के बीच कोई असहमति नहीं है - अतीत में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां बैठक में भी सहमति नहीं बन पाई।

(**Source:** https://indianexpress.com/article/explained/an-expert-explains-how-election-commission-evolved-what-rules-it-follows-in-case-of-disagreement-5720029/)

4. तमिलनाडु में विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला क्या है? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल द्वारा सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के तीन विधायकों- ई.रथिनासाबापति (अरन्थांगी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए),वी.टी.कालिसेलवन (विरुधचलम) और ए.प्रभु (कल्लुकुरिची) को विरोधी दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के लिए शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी।

यह कैसे घटित हुआ?

यह आरोप लगाया गया कि विधायक टी.टी.वी. धिनकरन, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के महासचिव से जुड़े हुए थे। तीन दिन बाद, अध्यक्ष ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

विधायकों द्वारा दिया गया औचित्य क्या है?

बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दो तर्क दिए।

एक, उन्होंने स्पीकर पर "पक्षपातपूर्ण और पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने" का आरोप लगाया।

दो, उन्होंने तर्क दिया कि श्री धनपाल को अयोग्य मामले पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित था।

क्या विधायकों ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम छोड़ी है?

तीन विधायक इस बात से इनकार नहीं करते कि उनकी सहानुभूति श्री धिनकरन के साथ या, अधिक सटीकता के लिए, वी.के. शशिकला, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की विश्वासपात्र के साथ है और वह अब आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बेंगलुरु में जेल की सजा काट रही हैं। लेकिन तीनों का कहना है कि वे AMMK के सदस्य नहीं हैं। कुछ दिनों पहले, AMMK ने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग को आवेदन दिया था। AIADMK की योजना श्री धिनकरन को समर्थन देकर यह स्थापित करने की थी कि तीनों विधायकों ने पार्टी की "स्वेच्छा से सदस्यता" छोड़ दी थी। यह वही आधार था जिस पर सितंबर 2017 में 18 समर्थक धिनकरन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था।

इससे क्या फर्क पड़ता है?

वर्तमान में, तमिलनाडु विधानसभा में 22 रिक्तियां हैं। चुनाव खाली सीटों के लिए होने वाले हैं। AIADMK के अध्यक्ष सहित 114 विधायक हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई, तो विधानसभा की संख्या 231 हो जाएगी। उस स्थिति में, AIADMK को केवल 116 सदस्यों की आवश्यकता होगी, जो उसकी वर्तमान संख्या से सिर्फ दो अधिक है।

अयोग्यता पर क्या नियम हैं?

संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 के अनुसार, संसद या विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य को दो आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है:यदि सदस्य स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है; या, यदि सदस्य ऐसी पार्टी की किसी भी दिशा के विपरीत सदन में वोट देने से परहेज या वोट करता है। हालांकि, अयोग्य ठहराए जाने से बचा जा सकता है यदि पार्टी नेतृत्व 15 दिनों के भीतर वोट या मतदान में भाग नहीं लेता है। अयोग्यता के लिए प्रक्रिया (दल बदल के आधार पर नियम), 1986 तमिलनाडु विधान सभा के सदस्यों में रखी गई है। प्रत्येक राज्य के समान नियम हैं।

आगे क्या होगा?

विधानसभा अध्यक्ष और उनके कार्यालय पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद, सामान्य व्यवहार यह है कि विधानसभा सचिव जवाब दाखिल करेगा। 22 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के नतीजों का असर अब से होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। यदि सत्तारूढ़ AIADMK पर्याप्त संख्या में सीटें जीतती है, तो यह ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पहले लिया गया है या नहीं। यह विद्रोही विधायकों के तर्कों में से एक को प्रस्तुत करने का प्रभाव होगा:अपने स्वयं के निष्कासन के लिए प्रस्ताव का सामना करने वाले अध्यक्ष को अयोग्यता के मुद्दों को स्थगित नहीं करना चाहिए। कम से कम दो और विधायक हैं जिनके खिलाफ पार्टी AIADMK नेतृत्व के खिलाफ जाने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है।

यदि DMK सभी 22 सीटों पर जीत जाती है, तो एक शासन परिवर्तन हो सकता है, जो एक नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो सकता है। उस मामले में, अयोग्यता कार्यवाही को नहीं चलाया जा सकता है।

(Source:https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-miscellaneous/tp-others/trial-in-the-assembly/article27106167.ece**)**

5. चुनाव आयोग ने कोलकाता में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को रोकने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान किया है। संविधान चुनाव आयोग को क्या शक्तियाँ देता है; SC ने अनुच्छेद 324 की व्याख्या कैसे की है? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

भारत के चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व आदेश पारित किया, जो 17 मई को शाम 5 बजे के बजाय पश्चिम बंगाल में अभियान को समाप्त करने के लिए 16 मई को शाम 10 बजे समाप्त हो गया, जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया था, और यह आदर्श है। इसने राज्य के गृह सचिव और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी हटा दिया।

ऐसा फैसला क्यों लिया गया?

कोलकाता में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क हिंसा के जवाब में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्णय लिए गए। एक महीने पहले, 15 अप्रैल को, ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले राजनेताओं को अनुशासित करने की उनकी शक्तियां "बहुत सीमित" थीं।

ECI की शक्तियाँ

अनुच्छेद 324 "चुनाव आयोग में" "चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" निहित करता है। संसद ने आयोग की शक्तियों को परिभाषित करने और विस्तार करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को लागू किया।

मोहिंदर सिंह गिल और अन्र बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और ओआरएस (1977) में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि अनुच्छेद 324 "कानून द्वारा अप्रभावित क्षेत्रों में संचालित होता है और शब्द 'अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' के साथ-साथ 'सभी चुनावों का संचालन' सबसे व्यापक शब्द हैं"। संविधान ने इन शब्दों को परिभाषित नहीं किया है। अनुच्छेद 324, अदालत ने कहा, "ईसीआई में राष्ट्रीय और राज्य के चुनावों के लिए पूरी ज़िम्मेदारी निभाने वाला एक पूर्ण प्रावधान है" और इसलिए, उस कार्य को करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ उसके पास हैं।"
महत्वपूर्ण रूप से, हालांकि, अदालत ने रेखांकित किया कि ईसीआई द्वारा शक्तियों को विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रयोग करना है।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/article-324-and-role-of-election-commission-india-5731889/)

6. चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल (Relevant for GS Mains Paper II; Polity & Governance)

1. 10 मार्च को 17वें आम चुनावों की चुनाव तारीखों की घोषणा की गई और 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 11 सप्ताह लगे; मतदान छह सप्ताह में फैल गया था। भारत के चुनाव आयोग की कवायद को लंबे समय तक खींचने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। इस तरह के लंबे समय के लिए एक औचित्य की अनुपस्थिति को देखते हुए, संदेह पैदा किया गया था कि क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक तरीके से अभियान में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
2. चुनाव आयोग ने श्री मोदी को अतीत में तय मानकों पर पकड़ बनाने में अनिच्छा दिखाई है। आरोप लगते रहे हैं कि श्री मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

3. तीन सदस्यीय आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही प्रश्न कहा गया था, जिसमें एक सदस्य ने दूसरों को सूचित किया था कि वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर बैठकों में भाग नहीं लेगा जब तक उसकी असहमति, जब तक न हो, अंतिम क्रम में दर्ज की जाती है।

चुनाव प्रचार की प्रकृति

कुछ स्व-परावर्तन के लिए कहा जाता है क्योंकि देश एक कड़वा लड़ा हुआ चुनाव संपन्न करता है जिसके दौरान नागरिक सार्वजनिक बहस की सीमाओं को पार किया गया है और मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। 2019 को क्या अभूतपूर्व बनाता है कि अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और गलत सूचना फैलाई गई थी। 2019 अभियान में, सरकार के नेताओं ने नौकरी सृजन और अन्य मापदंडों पर आधिकारिक डेटा को अवरुद्ध या दूषित करके, पांच साल के अपने प्रदर्शन पर एक तथ्य-आधारित बहस की शुरुआत की, और सफलतापूर्वक एक तथ्य-मुक्त क्षेत्र में भावनात्मकता और विभाजनकारी मुद्दों से भरे क्षेत्र में चुनावों को धकेल दिया। लोकतंत्र के लिए यह दोहरी मार थी। एक तरफ, सूचित चर्चा मुश्किल हो गई है, और दूसरी तरफ, सामाजिक तनाव बढ़ गया है।

7. विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं द्वारा मतदान (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

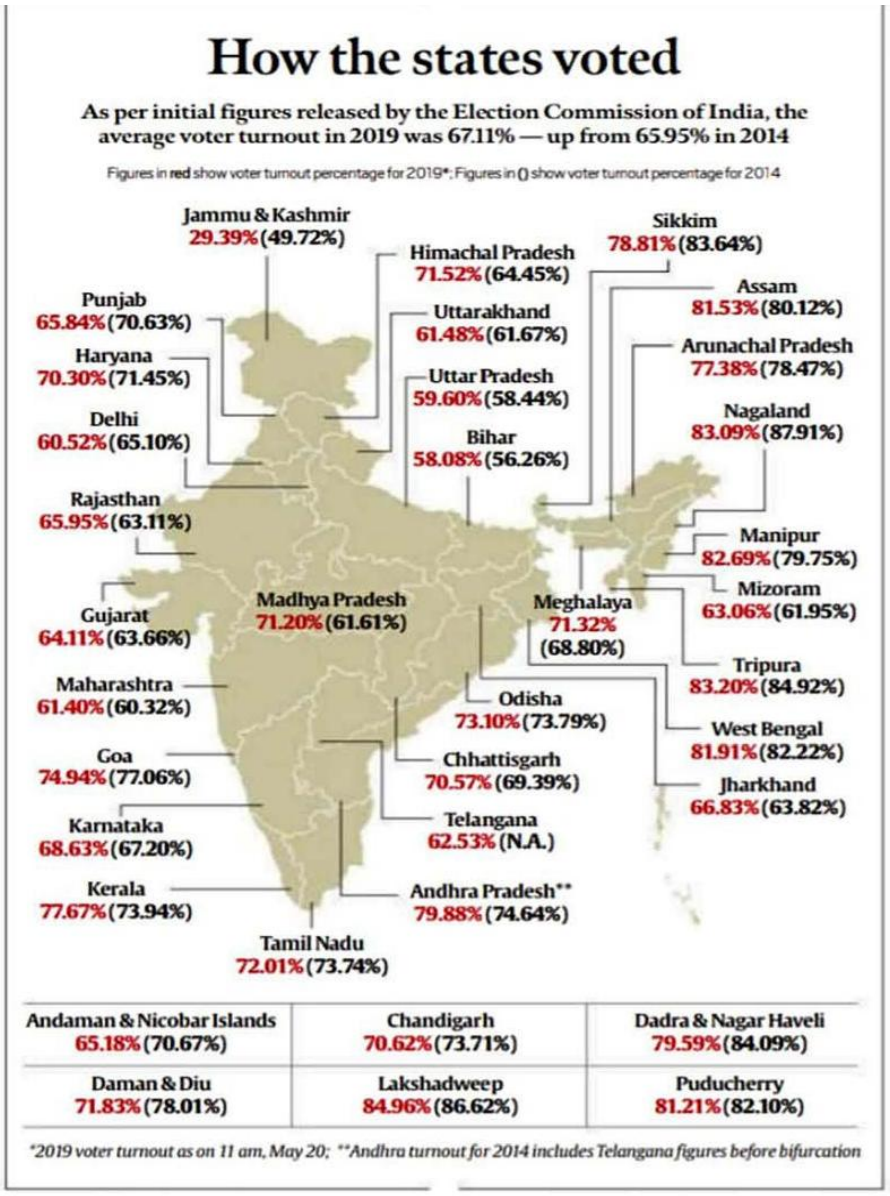

8. चुनाव परिणाम 2019: ईवीएम की गतिविधि पर विवाद, इन मशीनों को संग्रहीत करने के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर एक नज़र, उन्हें चुनावों के लिए कमीशन, और वे कैसे मजबूत कमरे से मतदान केंद्र और वापस यात्रा करते हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

22 विपक्षी दलों ने कथित रूप से संदिग्ध ईवीएम गतिविधि की रिपोर्टों को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, जबकि चुनाव आयोग ने ईवीएम के आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम की यात्रा को मजबूत कमरे से मतदान केंद्र और वापस यात्रा जाने के लिए किए गए प्रबंधों पर एक नज़र:

गैर-चुनाव अवधि के दौरान

जिले के सभी उपलब्ध ईवीएम सामान्य रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के सीधे नियंत्रण में एक कोषागार या गोदाम में संग्रहीत किए जाते हैं। अपवाद भंडारण स्थान की अनुपलब्धता के मामले में किए जा सकते हैं, लेकिन नामित खजाना या गोदाम तहसील के स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए। गोदाम को एक डबल लॉक, पुलिसकर्मियों या सुरक्षा गार्डों द्वारा चौबीसों घंटे सुरक्षित रखा जाता है, और सीसीटीवी निगरानी में भी रखा जाता है। एक गैर-चुनाव अवधि के दौरान, चुनाव आयोग के विशिष्ट निर्देशों के बिना ईवीएम को गोदाम से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। इंजीनियरों द्वारा ईवीएम की प्रथम-स्तरीय जाँच यहाँ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जाती है।

मतदान के दौरान

चुनाव की तारीख के करीब, ईवीएम को पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों (एक लोकसभा सीट में) को यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है। यदि प्रतिनिधि अनुपस्थित हैं, तो पार्टी कार्यालय के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की सूची साझा की जाती है। इस बिंदु से, विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) आवंटित मशीनों का प्रभार लेते हैं और उन्हें नामित मजबूत कमरों में संग्रहीत करते हैं।

यहां, अनियमितता का दूसरा दौर होता है। ईवीएम को पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विशिष्ट मतदान केंद्रों के लिए कमीशन किया जाता है। वास्तव में, उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित पोलिंग एजेंटों के साथ मशीन नंबर साझा करें ताकि वे मतदान शुरू होने से पहले इनका सत्यापन कर सकें।

सभी मशीनों को उम्मीदवारों की सेटिंग और बैलेट पेपर को ठीक करने के बाद तैयार किया जाता है, और फिर कमीशन किया जाता है, पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है, जो चाहें तो ताले पर अपनी मुहर भी लगा सकते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पद पर एक उप-पुलिस अधीक्षक के रैंक के साथ स्ट्रांग रूम में चौबीसों घंटे पहरा दिया जाता है। यह केंद्रीय पुलिस बलों द्वारा भी, जहाँ भी संभव हो, पहरा दे सकता है।

एक बार सील हो जाने के बाद, स्ट्रांग रूम को एक निश्चित तिथि और समय पर ही खोला जा सकता है जब मशीनों को पोलिंग पार्टियों को उनके निर्दिष्ट मतदान केंद्रों तक पहुंचाना होता है। सभी उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों को पहले से ही स्ट्रांग रूम खोलने की तारीख और समय के बारे में सूचित कर दिया जाता है।

विशिष्ट मतदान केंद्रों को आवंटित मशीनों के अलावा, कुछ आरक्षित ईवीएम को भी स्ट्रांग रूम से लिया जाता है और विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय स्थान पर संग्रहीत किया जाता है, ताकि दोषपूर्ण मशीनों को यथासंभव कम देरी से बदला जा सके।

इस साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान अप्रयुक्त ईवीएम के संचलन और भंडारण पर पिछले साल के विवाद को देखते हुए, मतदान और अप्रयुक्त मशीनों को केवल जीपीएस-सक्षम वाहनों में ले जाया जा रहा है ताकि उनके आंदोलन को डीईओ और सीईओ द्वारा ट्रैक किया जा सके।

बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक

एक बार मतदान समाप्त हो जाने के बाद, EVM को तुरंत स्ट्रांग रूम में नहीं भेजा जाता है। मशीनों में दर्ज मतों का लेखा-जोखा तैयार करने के लिए पीठासीन अधिकारी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को इसकी एक सत्यापित प्रति प्रदान की जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को मुहरों पर अपने हस्ताक्षर लगाने की अनुमति है, जिसे वे छेड़छाड़ के किसी भी संकेत के लिए जांच सकते हैं। मतगणना केंद्र के करीब स्थित, मतदान केंद्र से ईवीएम ले जाने वाले वाहनों के पीछे उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान कक्ष से स्ट्रांग रूम तक जाते हैं।

रिजर्व ईवीएम को भी उसी समय लौटाया जाना चाहिए जब मतदान वाले ईवीएम वापस आ जाते हैं। एक बार सभी ईवीएम का उपयोग हो जाने के बाद, स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है और उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि को अपनी मुहरें या लॉक लगाने की अनुमति दी जाती है। उन्हें चौबीसों घंटे मजबूत कमरों पर नजर रखने की भी अनुमति है।

एक बार सील होने के बाद, मजबूत कमरे को मतगणना के दिन सुबह तक नहीं खोला जा सकता है। यदि किसी अपरिहार्य कारण से पहले स्ट्रांग रूम को खोला जाना है, तो यह केवल उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जा सकता है, जिन्हें कमरे के बंद होने के बाद फिर से उनकी सील या ताले लगाने की अनुमति होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ आंतरिक कक्ष की सुरक्षा के लिए भंडारण कक्ष के आसपास तीन परतों में सुरक्षा बल तैनात हैं। परिणामों के दिन, उम्मीदवार या उसके पोलिंग एजेंट द्वारा मशीन नंबर की जांच की जाती है और क्या सील अखंड है, यह देखा जाता है, इसके बाद ही मतगणना शुरू होती है।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/evm-machine-tampering-hacking-election-commission-electronic-voting-machines-5741250/)

9. 2019 का चुनाव जीते मोदी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

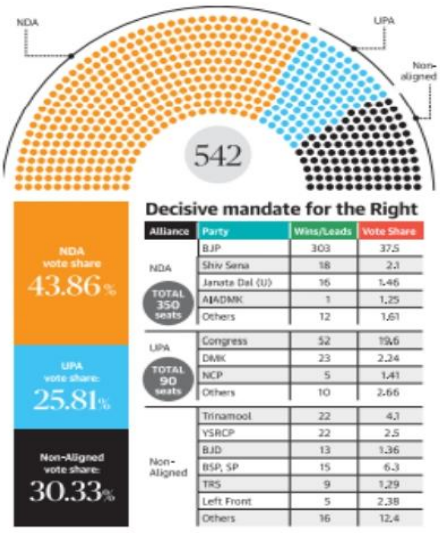

Decisive mandate for the Right

Alliance	Party	Wins/Leads	Vote Share
NDA (TOTAL 350 seats)	BJP	303	37.5
	Shiv Sena	18	2.1
	Janata Dal (U)	16	1.46
	AIADMK	1	1.25
	Others	12	1.61
UPA (TOTAL 90 seats)	Congress	52	19.6
	DMK	23	2.24
	NCP	5	1.41
	Others	10	2.66
Non-Aligned	Trinamool	22	4.1
	YSRCP	22	2.5
	BJD	13	1.36
	BSP, SP	15	6.3
	TRS	9	1.29
	Left Front	5	2.38
	Others	16	12.4

पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बढ़त बनाते हुए, उत्तर भारत में अपनी पकड़ बनाते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल में प्रवेश किया, सात चरण के लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतने के लिए भाजपा अकेले ही तैयार दिख रही थी।

विपक्ष बुरी तरह से हार गया

उत्तर प्रदेश और बिहार में विपक्ष के गठजोड़ की घोषणा करते हुए, भाजपा ने यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस, जो लगभग 50 की संख्या में बनी हुई है, दूसरी बार विपक्ष के नेता की आधिकारिक स्थिति का दावा करने में सक्षम नहीं होगी।

दक्षिणी राज्य: एक अपवाद

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने केरल में वाम दलों की कीमत पर प्रभावशाली संख्या में 20 में से 19 सीटें जीतीं, जबकि DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन ने तमिलनाडु में AIADMK-BJP गठबंधन को ध्वस्त कर दिया, 39 में से 37 में जीत हासिल की, जिसमें पुडुचेरी में अकेली सीट भी शामिल थी।

NDA द्वारा सुरक्षित सीटें

इसके प्रमुख NDA सहयोगी हैं - शिवसेना (18), जेडी (यू) 16, एलजेपी 6 और अकाली दल 2 ने गठबंधन को 345 पर पहुंचा दिया।

(Source:https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha-2019/india-gives-modi-a-high-five/article27227770.ece)

10. लोकसभा चुनाव परिणाम 2019: 17 से 22 करोड़ तक की वोटों की बढ़त से भाजपा की ऐतिहासिक जीत (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

भाजपा का वोट शेयर

वोट शेयर में उछाल और 2014 से अधिक वोटों का जोड़ बीजेपी की जीत की भयावहता को दर्शाता है। 2014 की तुलना में भाजपा के कुल वोट शेयर में 6.5 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस चुनाव में कुल 60.37 करोड़ मतों में से 22.6 करोड़ से अधिक भाजपा के लिए थे। पांच साल पहले मिले 17.1 करोड़ वोटों की तुलना में बीजेपी के लिए कुल वोटों में 32 फीसदी या 5.5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।

कांग्रेस का वोट शेयर

इसके विपरीत, कांग्रेस का वोट शेयर 19.3 से 19.6 प्रतिशत तक मामूली रूप से बढ़ा। कुल मिलाकर, पार्टी ने 2014 में अपने 10.69 करोड़ वोटों में से 1.17 करोड़ वोट जोड़े। जिन राज्यों में बीजेपी के सबसे ज्यादा वोट शेयर हुए, उनमें 17 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जहां पार्टी को इस बार कुल वोटों का 50 फीसदी से ज्यादा मिला। बीजेपी के वोटों में कमी का एकमात्र स्थान आंध्र प्रदेश में है जहां यह 7.5 प्रतिशत तक गिर गया।

जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए

विपक्ष के लिए भी, जीत आश्चर्यजनक थी। स्पष्ट रूप से, ग्रामीण संकट के बारे में इसकी कथा, विमुद्रीकरण के प्रभाव, वस्तुओं की कीमतें, बेरोजगारी, निजी निवेश में कमी और उपभोग के प्रतिमान में गिरावट जाति, वर्ग और भूगोल के मतदाताओं को रोकने में विफल रहे। इसके बजाय, भाजपा राष्ट्रीय गौरव बनाने में सफल रही और मोदी की लोकप्रियता चुनावी विकल्पों का मुद्दा बन गई। फैसले ने वाम दलों के लिए सबसे कम अंक को भी चिह्नित किया, जो उनके ऐतिहासिक निम्न स्तर तक गिर गया।

11. सुप्रीम कोर्ट 4 जजों के उन्नयन के बाद 31 जजों की अपनी पूर्ण स्वीकृत न्यायिक शक्ति तक पहुंच जाएगा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में उन्नयन के लिए सुझाए गए चार नामों को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति के साथ, सर्वोच्च न्यायालय 31 न्यायाधीशों की पूर्ण स्वीकृत न्यायिक शक्ति तक पहुंच जाएगा।

सरकार और कॉलेजियम के बीच प्रारंभिक असहमति

केंद्र ने झारखंड उच्च न्यायालय और गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, अनिरुद्ध बोस और ए.एस. बोपन्ना के नामों को मंजूरी दे दी है। 12 अप्रैल को कोलेजियम ने इन दोनों जजों के नाम की सिफारिश की। सरकार ने कॉलेजियम से इन जजों के नाम पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। 8 मई को, कॉलेजियम ने सरकार की सिफारिश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया।

कॉलेजियम ने सरकार की शुरुआती अनिच्छा के सामने जस्टिस बोस और बोपन्ना की अपनी सिफारिश दोहराई थी। इसने दो जजों की फाइलें सरकार को फिर से भेजीं, जिसमें कहा गया कि उनके आचरण, योग्यता या ईमानदारी में कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। इससे उनकी नियुक्तियों को मंजूरी देना सरकार के लिए बाध्यकारी हो गया था।

2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

सरकार ने कॉलेजियम की 8 मई की सिफारिश को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी आर गवई और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत के उन्नयन के लिए मंजूरी दी।

न्यायमूर्ति गवई के उन्नयन का आधार

कॉलेजियम ने जस्टिस गवई और कांत की अपनी सिफारिश को "यथोचित प्रतिनिधित्व" प्रदान करने, जितना संभव हो सके, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित सभी उच्च न्यायालयों और समाज के सभी वर्गों के के प्रयास के रूप में समझाया था।

जस्टिस गवई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन जजों को फटकार लगाई। कॉलेजियम ने तर्क दिया कि यद्यपि वरिष्ठता को उचित भारिता दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता "प्रमुख विचार" है। एससी/एसटी वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व कोलेजियम के दिमाग में उसकी उन्नयन की सिफारिश करते हुए प्रतीत होता है।

जस्टिस कांत की नियुक्ति पर विवाद

न्यायमूर्ति ए.के. गोयल (अब सेवानिवृत्त) द्वारा भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को लिखे गए एक पत्र पर जस्टिस कांत विवाद का विषय रहे थे। न्यायमूर्ति गोयल, तब शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कांत को पदोन्नत करने के प्रस्ताव से असहमति जताई थी। हालांकि, मिश्रा कॉलेजियम ने 3 अक्टूबर की एक अधिसूचना में, अपने उन्नयन के साथ आगे बढ़ गया।

12. चुनाव के बाद के सर्वेक्षण में क्या विधि है? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

नमूना लेने की अधिकता

यहां आम चुनाव 2019 का विश्लेषण देशव्यापी चुनाव के बाद के सर्वेक्षण (द नेशनल इलेक्शन स्टडी 2019) पर आधारित है, जो दिल्ली के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के लोकनीति कार्यक्रम द्वारा किया गया है। मतदान के प्रत्येक चरण के बाद 26 राज्यों में चुनाव के बाद सर्वेक्षण के लिए फील्डवर्क आयोजित किया गया था जो 12 अप्रैल, 2019 से शुरू हुआ और 21 मई तक चला। 26 राज्यों में 211 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) में कुल 24,236 मतदाताओं का साक्षात्कार लिया गया।

सर्वेक्षण की प्रकृति

नेशनल इलेक्शन स्टडी 2019 (एनईएस 2019) एक चुनाव के बाद के सर्वेक्षण है, जो 2019 के आम चुनाव के दौरान पूरे भारत के विद्वानों की एक टीम और लोकनीति द्वारा समन्वित, सेंटर फॉर कम्पेरेटिव डेमोक्रेसी फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS) द्वारा आयोजित किया गया है। NES 2019 भारत के राष्ट्रीय चुनावों का एक बड़ा और व्यापक सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन है और CSDS द्वारा 1967 में शुरू की गई श्रृंखला (1971 और 1996 के बीच एक विराम के साथ) को जारी रखता है।

मतदान के बाद सर्वेक्षण और निर्गम मतानुमान (exit poll) के बीच अंतर

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीएसडीएस द्वारा आयोजित मतदान के बाद सर्वेक्षण एक एक्जिट पोल से बहुत अलग है जिसमें मतदाता मतदान के दिन मतदान केंद्र के बाहर पहुंच जाते हैं। इसके बजाय, मतदाता जो बेतरतीब ढंग से मतदाता सूची से चुने गए थे, उन्हें अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने के बाद अपने निवास स्थान पर एक साक्षात्कार के लिए क्षेत्र के जांचकर्ताओं द्वारा परिणाम ज्ञात होने से पहले संपर्क किया गया था। मतदान के बाद के सर्वेक्षण का उद्देश्य सिर्फ मतदान के व्यवहार को समझने की कोशिश करना नहीं था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि उन कारणों को समझने के लिए कि मतदाताओं ने पार्टियों और उम्मीदवारों को क्यों चुना।

(Source:https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha-2019/the-method-behind-the-sampling/article27249435.ece)

13. लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.4% हो गया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

लोकसभा की महिला सदस्य

17वीं लोकसभा में पहले के मुकाबले महिला प्रतिनिधियों की सबसे अधिक संख्या (78) होगी। वे निचले सदन की पूरी संख्या का 14.39% हिस्सा होंगी, जो पिछली लोकसभा में कुल 65 महिला सांसदों के साथ 12.5% थी।

पार्टी वार महिला सांसद

भाजपा ने अपनी जीत के विशाल आकार के कारण सबसे अधिक संख्या में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (40) को लोकसभा में भेजा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस (9), कांग्रेस (6), बीजेडी (5) और वाईएसआरसीपी (4) है।

हालाँकि, यह क्षेत्रीय दल हैं जो नई लोकसभा में अपने कुल सांसदों के मुकाबले महिला सांसदों के उच्च अनुपात का दावा करते हैं। लोकसभा में BJD की कुल संख्या का 41.6% और सदन में TMC की संख्या का 40.9% हिस्सा महिलाओं का है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने चुनाव शुरू होने से पहले 40% और 30% पार्टी उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा किया था।

जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के लिए कुल विजयी उम्मीदवारों में से 18.18% महिलाएँ हैं। जहां तक राष्ट्रीय दलों का संबंध है, महिला सांसदों का भाजपा के कुल जीतने वाले उम्मीदवारों का मात्र 13.28% और कांग्रेस का 11.76% हिस्सा है।

Making a mark

A total of 716 women candidates were fielded by various parties in the 2019 Lok Sabha election

	Total	Men	Women	% of women winners
BJP	301	261	40	13.28904
Trinamool	22	13	9	40.90909
INC	51	45	6	11.76471
BJD	12	7	5	41.66667
YSRCP	22	18	4	18.18182
DMK	23	21	2	8.695652

(Source:https://www.thehindu.com/news/national/womens-representation-in-lok-sabha-rises-to-a-record-at-144/article27248880.ece)

14. उत्तर प्रदेश का महागठबंधन क्यों विफल हुआ (केवल समझने के लिए पढ़ें; Polity & Governance)

इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के रूप में संदर्भित समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बीच गठबंधन इस आधार पर हुआ था कि दोनों पार्टियां अपनी-अपनी सीटों पर अपने मतों का हस्तांतरण एक-दूसरे को सुनिश्चित करेंगी। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में उन्हें इस प्रयोग की सफलता 2018 की शुरुआत में मिली और कुछ महीने बाद कैराना में भी, जब राष्ट्रीय लोकदल (RLD) इस गठबंधन में शामिल हो गया। हालाँकि, सफलता लंबे समय तक नहीं रही। उपचुनावों में काम करने वाला वोट ट्रांसफर पूरी तरह से भौतिक नहीं था जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता था।

चुनाव के बाद के सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न जातियों और समुदायों की मतदान पसंद का विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि महागठबंधन लोकसभा चुनाव में इतने शानदार ढंग से विफल क्यों हुआ। सबसे पहले, जाटों, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से RLD को वोट दिया था, लेकिन 2014 के बाद से इससे दूर चले गए, पश्चिमी यूपी में गठबंधन के पीछे नहीं गए। उन्होंने न केवल सपा और बसपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, बल्कि उनमें से ज्यादातर ने RLD के उम्मीदवारों को भी वोट नहीं दिया। सर्वेक्षण के अनुसार, 91% जाटों ने भाजपा का समर्थन करना शुरू कर दिया है।

दूसरा, महागठबंधन के पीछे सपा के प्रमुख मतदाताओं, यादवों का समेकन उतना मजबूत नहीं था, जितना होना चाहिए था। जबकि उनमें से तीन-चौथाई लोगों ने महागठबंधन के लिए वोट किया, यह 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम है, जब उनमें से तीन-चौथाई से अधिक ने कांग्रेस-सपा गठबंधन को वोट दिया था।

तीसरा, बीएसपी अपने मुख्य जाटव वोट (महागठबंधन के लिए उनमें से तीन-चौथाई से अधिक वोट) पर पकड़ बनाने में सक्षम थी, लेकिन यह गठबंधन के लिए गैर-जाटव दलितों का समर्थन सुनिश्चित करने में विफल रहा, क्योंकि 2017 में उनमें से लगभग आधे (48%) ने भाजपा उम्मीदवारों को वोट दिया।
चौथा, यहां तक कि तीन-चौथाई मुस्लिम वोट महागठबंधन में चले गए, लगभग 15% कांग्रेस द्वारा भी कब्जा कर लिया गया, खासकर सपा द्वारा लड़ी गई सीटों पर। बसपा उम्मीदवारों की तुलना में सपा प्रत्याशियों की काफी बड़ी हार के कारणों में यह एक कारण हो सकता है।

पांचवीं, भाजपा के पीछे उच्च जातियों, कुर्मी और कोइरी और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) का समेकन जाटवों, मुस्लिमों और यादवों के समेकन से कहीं अधिक मजबूत था। ऊंची जातियों के चार-पांचवें हिस्से, कुर्मी और कोइरी के चौथे-पांचवें और निचले ओबीसी के तीन-चौथाई लोगों ने भाजपा को वोट दिया। गैर जाटव दलितों के साथ, तीनों की आबादी यूपी की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। दूसरी ओर, जाटव, मुस्लिम और यादव मिलकर राज्य की लगभग 40% आबादी को बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह जातियों और समुदायों ने मतदान किया

	पार्टी ने लोकसभा 2019 (उत्तर प्रदेश) के लिए मतदान किया			
	कांग्रेस (%)	भाजपा+ (%)	महागठबंधन (%)	अन्य (%)
ब्राह्मण	6	82	6	6
राजपूत	5	89	7	-
वैश्य	13	70	4	13
जाट	2	91	7	0
अन्य उच्च जाति	5	84	10	1
यादव	5	23	60	12
कुर्मी + कोइरी	5	80	14	1

अन्य ओ.बी.सी.	5	72	18	5
जाटव	1	17	75	7
अन्य एस.सी.	7	48	42	3
मुसलमान	14	8	73	5
अन्य लोग	1	50	35	14

नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता

जाति एक तरफ, सर्वेक्षण यह भी बताता है कि यह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के लिए नहीं था, जो 47% उत्तरदाताओं की प्रधान मंत्री की प्राथमिकता थी, भाजपा राज्य में जितनी सीटें जीत सकती थी, उतनी नहीं जीत पाई।

(स्रोत: उत्तर प्रदेश में लोकनीति-सीएसडीएस पोस्ट पोल सर्वेक्षण।)

(Source:https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha-2019/post-poll-survey-why-uttar-pradeshs-mahagathbandhan-failed/article27249310.ece)

15. NSSO-CSO विलय: भारतीय सांख्यिकी का केंद्रीकरण क्या होगा? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

23 मई को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) ने दो बड़े सरकारी अंगों के विलय के संबंध में एक आदेश जारी किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन (NSSO) को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) नामक इकाई बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) के साथ विलय कर दिया जाएगा।

NSSO के बारे में

NSSO का समृद्ध इतिहास है: इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। एनएसएसओ को तब शुद्ध रूप से सरकार के बाहर संगठित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के हिस्से के रूप में, एक स्वतंत्र, गैर-नौकरशाही, राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्रीकरण संगठन के रूप में, देश भर में ध्वनि, वैज्ञानिक और पूरी तरह से निष्पक्ष नमूना सर्वेक्षण विधियों के आधार पर, सक्षम प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा वितरित किया जाना है। प्रोफेसर महालनोबिस व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया की देखरेख करते थे।

इस सांख्यिकीय डेटा एकत्रीकरण प्रणाली की स्वतंत्रता की भावना 1972 तक जारी रही।

उस युग में, एनएसएसओ डेटा योजना आयोग (पीसी) की रणनीतियों की रीढ़ था, जिससे यह एक बहुत ही पारदर्शी समर्थक विकास कार्यक्रम बन गया।

विकास लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए विकास दर के इनपुट-आउटपुट मॉडल के निर्माण में या गरीबी रेखाओं का आकलन करने और गरीबी दर में कमी, बचत दरों के अनुमान के आधार पर सार्वजनिक निवेश दरों के डिजाइन के लिए प्लानर्स उदारतापूर्वक और प्रभावी रूप से एनएसएसओ डेटा का उपयोग कर सकते थे। यहां तक कि योजना आयोग के नए अवतार, नीति आयोग, ने भारत में विकास कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए NSSO डेटा का उपयोग किया है - चाहे वे स्वास्थ्य या शैक्षणिक या अवसंरचनात्मक विकास हों।

इसके अतिरिक्त, और यह नीति अनुसंधान में एनएसएसओ द्वारा सक्षम दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसने सरकार के बाहर नीति-उन्मुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा दिया। जबकि NSSO का मुख्य उद्देश्य सरकारों की राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया के लिए जानकारी फीड करना था, लेकिन इस दूसरे उद्देश्य ने सरकार के बाहर से नीति-उन्मुख अनुसंधान परिणामों को बढ़ावा दिया। इस तरह के अनुसंधान के कई उदाहरण हैं:गरीबी के उपायों को परिष्कृत करना, बेरोजगारी दर, भूमि सुधारों पर दिशानिर्देश प्राप्त करना, बचत और निवेश दरों को बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीतियों को तैयार करना, कराधान सिद्धांत, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को नया स्वरूप देना, सार्वजनिक और निजी निवेशों को संतुलित करना और आम जनता के लिए समावेशी विकास को लक्षित करना।

हाल के दिनों में, चीजें बदल गई हैं। एनएसएसओ-जनित सांख्यिकीय सूचना प्रणाली की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया जा रहा है फिर चाहे यह बेरोजगारी दर या जीडीपी विकास दर के अनुमान पर हो।

डेटा का केंद्रीकरण?

दोनों निकायों के विलय के साथ, किसी को यह धारणा मिलती है कि एनएसएसओ से डेटा तक पहुंच मुख्य रूप से MoSPI और शायद नीति आयोग द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए है। आखिरकार, यह विलय नीति आयोग सहित सरकारी एजेंसियों को सूचना प्रणाली पर एक त्वरित हाथ लाने में सक्षम करेगा - उपयोग या दुरुपयोग के लिए।

मुख्य सांख्यिकीविद् ने संकेत दिया है कि एनएसएसओ और सीएसओ में शामिल होने का एक बड़ा औचित्य यह है कि इससे प्रशासनिक आसानी आएगी। लेकिन, किसी को इतनी आसानी से प्रभावशीलता का पता नहीं चलता है जब डेटा जनरेटर और उपयोगकर्ता एक साथ समान होते हैं। दूसरे, मंत्रालय में डेटा का केंद्रीकरण सार्वजनिक अनुसंधान और बहस के लिए डेटा के त्वरित और समय पर रिलीज के लिए एक बाधा बन सकता है। इस तरह की परेशानी का एक ताजा उदाहरण बेरोजगारी पर डेटा की हाल ही में अनुपलब्धता है।

इस आधिकारिक डेटा सिस्टम के बाहर शायद ही कोई अन्य एजेंसियां हैं जो अब शोधकर्ताओं तक पहुंच सकती हैं। कोई केवल उन हजारों शोधकर्ताओं के दुखद भाग्य की कल्पना कर सकता है जो अपने सामाजिक-आर्थिक विश्लेषणों के लिए इस तरह के मैक्रो और सूक्ष्म-स्तरीय डेटा पर निर्भर हैं।

यह हो सकता है कि सरकार सरकार के बाहर इस तरह के अनुसंधान के लिए उत्सुक नहीं है - जैसा कि नीति आयोग से आने वाली विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों या HRD मंत्रालय के विचारों से देखा जा सकता है, जिसने लोगों को मुख्य रूप से राष्ट्रीय हित के मामलों पर अनुसंधान करने के लिए कहा है। भारत की कुछ सामाजिक विज्ञान पत्रिकाओं को देखते हुए, पहले से ही इन पंक्तियों के साथ कुछ सबूत मिलते हैं।

हाल ही में, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने सोशल साइंसेज में इंपैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च नामक एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की। केवल विश्वसनीय मैक्रो सांख्यिकीय डेटा तक समय पर पहुँच के अभाव में इस विशाल शोध कार्यक्रम के भाग्य का अनुमान लगा सकते हैं।

जबकि राष्ट्र विकास और शासन की प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता की बात करता है, यह अधिक से अधिक केंद्रीकरण और प्रशासनिक सुविधा की दिशा में, विशेष रूप से सांख्यिकीय सूचना उत्पादन के क्षेत्र की ओर अग्रसर होता दिखाई देता है। सरकार के बाहर अनुसंधान के भाग्य पर सवालों के अलावा, यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या सरकारी एजेंसियों को एनएसएसओ द्वारा उत्पन्न किए जा रहे समृद्ध डेटा को पचाने और उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

(Source: https://thewire.in/government/nsso-cso-merger-what-will-the-centralisation-of-indian-statistics-bring-with-it)

16. पीएस गोले ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली (केवल समझने के लिए पढ़ें; Polity & Governance)

विधायकों को मंत्रिपरिषद के अंग के रूप में शपथ दिलाई गई, जिसमें एसकेएम की कार्यकारी अध्यक्ष निमा लेप्चा शामिल हैं, जो दो सीटों से जीतीं, अरुण उपरती, एयरथांग से विधायक, और सोनम लामा, जिन्होंने विधानसभा में संघ सीट के लिए जीत हासिल की, जो भिक्षुओं के लिए आरक्षित है।

प्रेम सिंह तमांग उर्फ पी.एस. गोलकी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
श्री गोलय की पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM), ने 11 अप्रैल के चुनाव में 32 में से 17 विधानसभा सीटें जीतीं। 25 वर्षों तक राज्य में शासन करने वाले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) ने 15 सीटें जीतीं।

पवन चामलिंग को प्रतिस्थापित किया
वह एसडीएफ के पवन चामलिंग को प्रतिस्थापित करता है, जिनके पास देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है, जिसने लगातार 24 वर्षों तक पांच बार जीत हासिल की है।

श्री गोले के बारे में
हिमालयन राज्य के छठे मुख्यमंत्री 51 वर्षीय श्री गोले ने अपने करियर की शुरुआत स्कूल शिक्षक के रूप में की। श्री गोले को 1994 में एसडीएफ उम्मीदवार के रूप में 1994 में विधानसभा के लिए चुना गया था जब वह सिर्फ 26 वर्ष के थे और 2009 तक लगातार तीन बार कई विभागों के मंत्री के रूप में कार्य किया।

हालाँकि, पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनके और श्री चामलिंग के बीच मतभेद होने के बाद, उन्होंने फरवरी 2013 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का गठन किया। 2014 के विधानसभा चुनाव में, SKM ने 10 सीटें हासिल कीं। श्री गोले को बाद में दोषी ठहराया गया और अगस्त 2018 में उनकी रिहाई तक जेल की सजा दी गई।

(Source-https://www.thehindu.com/elections/sikkim-assembly/ps-golay-sworn-in-as-sikkim-chief-minister/article27259921.ece)

17. एनएसएसओ का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में विलय चिंता का कारण है)Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)CSO) के तहत और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय)NSSO) के विलय का फैसला किया है, जिसने आश्चर्य और चिंता दोनों को जन्म दिया है। वास्तव में 'विलय' का मतलब अस्पष्ट है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा की सत्यता (एनएसएस) पर सवाल उठाने के हालिया प्रयास और जिस तरह से इस मुद्दे को संभाला गया है उसने आशंकाओं को जन्म दिया है।

वर्तमान प्रणाली

वर्तमान प्रणाली के तहत, हर साल सरकार के विभिन्न विभाग उन विषयों की सूची भेजते हैं, जिनकी वे एनएसएसओ द्वारा जांच करना चाहते हैं। अनुरोध राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) को भेजे जाते हैं, जिसमें सीएसओ के प्रमुख और क्षेत्र कार्य के डिजाइन और संचालन के तकनीकी पहलुओं के लिए जिम्मेदार सीएसओ के प्रमुख साथ ही राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सहित सरकार से सम्मानित अर्थशास्त्री, विषय विशेषज्ञ और सरकार के सांख्यिकीविद होते हैं। विशेष क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ भी लाए जाते हैं।

सैंपलिंग डिज़ाइन, कार्यक्षेत्र की जानकारी की गुंजाइश और सामग्री, विशेष कार्य समूहों द्वारा तय किए जाने के लिए शेड्यूल के डिज़ाइन और फ़ील्ड कार्य के प्रोटोकॉल को छोड़ दिया जाता है। इन समूहों की अध्यक्षता शिक्षाविदों, और CSO के वरिष्ठ अधिकारियों और NSSO, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथआधिकारिक विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। ये कार्य समूह बाद -साथ गैर- के सभी चरणों के माध्यम से प्रत्येक दौर की स्थापना से निरंतर पर्यवेक्षण में हैं। एक बारक्षेत्र का काम खत्म हो जाने के बाद, समूह विस्तृत सारणीयन कार्यक्रम और प्रकाशन के लिए तैयार की जाने वाली सारणी तय करते हैं। सारणीबद्ध परिणामों पर एनएससी द्वारा विस्तार से चर्चा की जाती है और इसकी स्वीकृति के बाद इसे प्रकाशित किया जाता है।

डेटा की खुली पहुँच

काफी हिचक और ठेस के बाद, सरकार ने कुछ साल पहले सभी सूचनाओं और प्राथमिक डेटा को विशेष रूप से अकादमिक और अन्य इच्छुक उपयोगकर्ताओं के लिए खुले उपयोग पर रखने का फैसला किया। इस निर्णय ने कई शोधकर्ताओं द्वारा गहन विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों के उपयोग को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाया है। नीति को आकार देने और सर्वेक्षणों को बेहतर बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आशंकाएँ क्या हैं?

NSSO सर्वेक्षणों को शिक्षाविदों, राज्य सरकारों और गैरसरकारी संगठनों के बीच व्यापक सम्मान - देता है। व्यापक आशंकाएं कि सीएसओमें एनएसएसओ के प्रस्तावित अवशोषण ने सर्वेक्षणों को अपनी समीक्षा के अधीन किया और सरकार की मंजूरी के लिए प्रकाशन किया जा सकता है इसलिए इसे अयोग्य तरीके से शीघ्र आवंटित किया जाना चाहिए। कोई भी प्रयास या एक सुझाव भी कि इसके ठोस कार्य, प्रकाशन और डेटा का मुफ्त प्रसार विभाग की मंजूरी के अधीन हैं, भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की विश्वसनीयता को बहुत कम कर देगा।

सुधार के लिए क्षेत्र

इसे किसी भी तरह से आग्रह करना किसी भी तरह से सुझाव नहीं देता है कि वर्तमान संस्थागत व्यवस्था निर्दोष है या कि एनएसएसओ एकदम सही है। इसके विपरीत, यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि संस्था के कामकाज और डेटा एकत्र करने के तरीके में सुधार की गुंजाइश है। इन समस्याओं को अच्छी तरह से जाना जाता है :

1. एनएसएसओ के पास पर्याप्त बजटीय आवंटन नहीं है;
2. प्रशिक्षित फील्ड स्टाफ की भारी कमी है;
3. सर्वेक्षण का पैमाना मुख्य रूप से अप्रबंधित रूप से बड़ा है क्योंकि उपयोगकर्ता सामग्री की विस्तार और अनुमानों के क्षेत्रीय असहमति की डिग्री की मांग करते हैं।

एनएससी इन कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह सचेत है। सैंपलिंग डिज़ाइन, फ़ील्ड सर्वेक्षण के तरीकों में सुधार और डेटा की मान्यता पर निरंतर शोध में निवेश करके डेटा इकट्ठा करने के लिए

जिम्मेदार संस्थानों द्वारा कार्रवाई के लिए समाधान का आह्वान किया गया है। इन कमियों को ठीक करना पूरी तरह से सरकार के क्षेत्र में है।

निष्कर्ष क्या है?

एनएसएसओ को चलाने में सीएसओ अधिकारियों की भूमिका बढ़ने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लेकिन वे सर्वेक्षण डिजाइन और कार्यप्रणाली पर विशेष शोध के लिए धन प्रदान करके मदद कर सकते हैं। इस तरह के अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व वर्तमान में प्राप्त की तुलना में कहीं अधिक ध्यान और संसाधनों के लिए कहता है।

(Source:https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/why-the-integrity-of-data-matters/article27297860.ece**)**

International Organizations & Relations

1. Masood Azhar declared UN terrorist- जानिए- कौन है मसूद अजहर, जिसे आज UN ने घोषित किया वैश्विक आतंकी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद (jaish e mohammad) के सरगना मसूद अजहर(Masood Azhar) को संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। इसे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान में पनाह लेकर आतंकी हमला कराने वाले इस संगठन ने भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। इस वजह से भारत उसे वैश्विक आतंकी घोषित कराने की कोशिश में लगा था। भारत ही नहीं मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति के सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीन इस राह में रोड़ा बन रहा था। चीन इस प्रस्ताव पर चार बार वीटो लगा चुका था, लेकिन पांचवीं बार वह राजी हो गया, जिसके बाद आज मसूद अजहर वैश्विक आतंकी घोषित हो गया।

जैश का सरगना है मसूद अजहर

खूंखार आतंकी मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है जो पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। मसूद अजहर ने मार्च 2000 में हरकत-उल-मुजाहिदीन में विभाजन करावाकर यह संगठन बनाया था। मसूद अजहर को साल 1994 में श्रीनगर पर हमले की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। लेकिन, 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड के बाद भारत सरकार को उसे रिहा करना पड़ा था। इसके अगले ही साल उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम से आतंकवादी संगठन बना लिया। लेकिन, साल 2002 में पाकिस्तान सरकार ने जैश पर बैन लगा दिया।

कौन-कौन से हमले को दिया अंजाम?

मसूद अजहर भारत में अब तक कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। 13 दिसंबर 2001 को मसूद अजहर ने ही भारतीय संसद पर हमला कराया था। इससे पहले अक्टूबर 2001 में ही उसने जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर भी आतंकी हमला कराया था। 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट में वायुसेना की छावनी पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर ही था। इसके अलावा, इसी साल 14 फरवरी को पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली थी।

पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड है मसूद

पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश लाहौर के पास रची गई थी। आतंकियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान के चकलाला और लायलपुर एयरबेस पर दी गई थी। हमले के वक्त आतंकियों के चारों हैंडलर्स पाकिस्तान के बहावलपुर, सियालकोट और शकरगढ़ में मौजूद थे। जैश का सरगना मसूद अजहर, उसका भाई रउफ असगर, उनके दो साथी अशफाक और कासिम हमलावरों को आदेश दे रहे थे। 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का आरोप भी मसूद अजहर पर लगा था।

पुलवामा आतंकी हमले का जिम्मेदार

इसी साल 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा (Pulwama Terror Attack) में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की जैश-ए मुहम्मद ने जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला उस वक्त हुआ, जब सीआरपीएफ के ज्यादातर जवान अपनी छुट्टिया खत्म कर वापस श्रीनगर ड्यूटी पर लौट रहे थे। आदिल अहमद डार नाम के आत्मघाती हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसने विस्फोटक से भरी कार ले जाकर सीआरपीएफ के काफिले से भिड़ा दी थी।

2. 10 साल में चौथी कोशिश कामयाब, जानिए- संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर कैसे कसा शिकंजा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की पिछले 10 वर्षों में यह चौथी कोशिश थी। दरअसल, चीन संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद का अकेला ऐसा देश है जो मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव का विरोध करता रहा है। आइये जानते हैं संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में कैसे शिकंजा कसा...

सबसे पहले साल 2009 में प्रस्ताव, कामयाबी मिली अब भारत ने सबसे पहले साल 2009 में यह प्रस्ताव रखा था। इसके बाद वर्ष 2016 में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति के सामने दूसरी बार प्रस्ताव रखा था। लेकिन हर बार चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके इसमें अड़ंगा लगा देता था। साल 2017 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से भारत ने तीसरी बार यह प्रस्ताव रखा। लेकिन इस बार भी चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके ऐसा होने से रोक दिया था। इस साल मार्च में भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन, हर बार की तरह, इस बार भी चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके ऐसा करने में बाधा पैदा की।

UNSC 1267 प्रतिबंध समिति का फैसला

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की UNSC 1267 प्रतिबंध समिति में किसी आतंकी संगठन या आतंकी के सूचीबद्ध किए जाने के लिए स्पष्ट नियम हैं। यह समिति संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिबंधों के मानकों की देखरेख करती है। साथ ही मानक पर फिट होने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित करती है। यह प्रतिबंधों से छूट के लिए अनुरोधों पर भी विचार करती है। इसी समिति ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के फैसले पर मुहर लगाया है।

आतंकी संगठनों पर कसती है शिकंजा

ISIS/दाएश और अल-कायदा को प्रतिबंध सूची में शामिल करने के प्रस्तावों पर फैसले लेने का काम भी UNSC 1267 प्रतिबंध समिति का ही था। यही समिति सुरक्षा परिषद को प्रतिबंधों के मानकों की सालाना रिपोर्ट भी भेजती है। हथियारों के आयात, विदेश में यात्राएं और संपत्तियों की जब्ती जैसे फैसले भी यही समिति लेती है। जब कोई व्यक्ति, समूह या संस्था का संबंध दाएश या अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ता है। अगर किसी व्यक्ति, समूह, या संस्था का संबंध दाएश या अल-कायदा जैसे संगठनों से जुड़ता है या किसी व्यक्ति, समूह, या संस्था द्वारा दाएश और अल-कायदा के समर्थन दिए जाने की बात सामने आती है तो यह समिति ही प्रतिबंध लगाने का काम करती है।

(Adapted from Jagran.com)

3. Attempt to change predient in Venezuela- राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश, कई सैनिकों ने ब्राजील दूतावास में शरण ली (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

वेनेजुएला में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष के नेता जुआन गाइदो के नेतृत्व में सरकार के तख्तापलट की कोशिशें तेज कर दी हैं। मंगलवार को इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों ने देश के अलग-अलग हिस्से से कराकस के लिए मार्च निकाला। इस दौरान राष्ट्रपति मादुरो के वफादार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को बख्तरबंद गाड़ियों से कुचलने की कोशिश भी की। सेना की कार्रवाई में करीब 69 लोग घायल हुए हैं।

इसी बीच कई सैनिकों ने मादुरो के निर्देश मानने से इनकार करते हुए वेनेजुएला स्थित ब्राजील दूतावास से शरण मांगी है। फिलहाल ऐसे सैनिकों की संख्या 25 है। ब्राजील सरकार ने वेनेजुएला से देश में आने वाले लोगों के लिए 5.7 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त रक्षा बजट निर्धारित किया है, ताकि परेशानी में रह रहे लोगों की मदद की जा सके।

तख्तापलट की कोशिश करने वालों को सजा मिलेगी: मादुरो

मादुरो ने मंगलवार देर शाम अपने खिलाफ तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम घोषित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों ने देशवासियों को भड़काया है उन्हें सजा मिलकर रहेगी। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर क्यूबा अपने पड़ोसी वेनेजुएला का समर्थन करता रहेगा तो उस पर सबसे उच्च स्तर के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो सरकार की मदद के लिए क्यूबा के हजारों सुरक्षा अधिकारी वेनेजुएला में ही मौजूद हैं।

(Adapted from Bhaskar.com)

4. Masood Azhar Declared Global Terrorist: इन आतंकी सरगनाओं पर कब कसेगा शिकंजा! (Relevant for Gs prelims & mains paper II; IOBR)

मसूद अजहर के अलावा ऐसे कई आतंकी सरगना हैं जो पड़ोसी देश पाकिस्तान में आश्रय लिए हुए हैं। पाकिस्तान उनके लिए अभ्यारण्य साबित हो रहा है। भारत के इन सर्वाधिक वांछित अपराधियों द्वारा वह अपने हितों की पूर्ति करता रहता है। भारत ने इन लोगों को सूची कई बार पाकिस्तान को सौंपी है, लेकिन उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती।

हाफिज सईद

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। पाकिस्तान में जमात उद दावा नामक संगठन चलाता है। 2008 में मुंबई हमले का सूत्रधार रहा जिसमें 164 लोग मारे गए। इसी हमले के बाद अमेरिका ने इसके सिर पर एक करोड़ डॉलर का ईनाम घोषित कर रखा है। 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों में भी इसका हाथ रहा। 2001 में भारतीय संसद तक को इसने निशाना बनाया। एनआइए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने इसके दोनों संगठनों को प्रतिबंधित कर रखा है।

सैयद सलाहुद्दीन

कश्मीर में आतंक फैलाने वाले हिज्बुल मुजाहिद्दीन का सरगना है। इसी संगठन के नेतृत्व में यूनाइटेड जेहाद काउंसिल नामक बैनर के तले कई छोटे-छोटे आतंकी संगठन कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एनआइए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। जून, 2017 में अमेरिका ने इसे वैश्विक आतंकी घोषित किया।

दाऊद इब्राहीम

पाकिस्तान में छिपा यह अपराधी भारतीय संगठित अपराध गिरोह डी कंपनी का मुखिया है। भारत में हत्या, उगाही, ड्रग तस्करी, आतंकवाद जैसे कई मामलों में यह वांछित है। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल धमाकों का इसे मास्टरमाइंड माना जाता है। 2003 में भारत और अमेरिका ने इसे वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ है। इसके सिर पर 2.5 करोड़ डॉलर का ईनाम है। फोर्ब्स और एफबीआइ की सूची में दुनिया के शीर्ष दस सबसे वांछित भगोड़ों में इसे तीसरा स्थान हासिल है।

छोटा शकील

दाऊद के इस गुर्गे को उसका दाहिना हाथ माना जाता है। 1988 में यह डी कंपनी में शामिल हुआ। माना जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ दाऊद के कारोबार को चलाने में इसकी मदद करती है। 1993 मुंबई सीरियल धमाकों का यह भी मोस्ट वांटेड है। अमेरिका ने भी इसे प्रतिबंधित कर रखा है।

टाइगर मेमन

इसका पूरा नाम इब्राहीम मुश्ताक अब्दुल रजक मेमन है। लोग इसे टाइगर मेमन के नाम से जानते हैं। दरअसल एक बार इसने एक ड्रग और हथियार तस्कर को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ने से बचाया था, तब इसने वन वे सड़क पर सौ किमी प्रति घंटे से तेज रफ्तार से कार दौड़ाई थी। इसके इसी कारनामे से अपराध जगत में इसे टाइगर कहा जाने लगा। 1993 के सीरियल मुंबई बम धमाकों में इंटरपोल और सीबीआइ की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। डी कंपनी का सदस्य है।

जकीउर रहमान लखवी

लश्कर-ए-तैयबा में दूसरे स्थान का आतंकी है। आतंकियों की नियुक्ति और किसको क्या काम देना है, यह इसके जिम्मे होता है। मुंबई हमले के दौरान सभी आतंकियों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण और तैयारी सब इसी ने की थी। 2006 में मुंबई में हुए ट्रेन धमाकों में शामिल आजम चीमा की नियुक्ति भी इसी ने की थी।

5. मसूद अजहर ऐसे बना था आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद का सरगना (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को आज बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला मसूद अजहर (Masoosd Azhar) आज वैश्विक आतंकी घोषित हो गया है। आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद का सरगना बनने वाला यह मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में 10 जुलाई, 1968 को जन्मा था। इसके नौ भाई-बहन थे। आइए जानते हैं इसके बारे में अन्य बातें।

भारत ही नहीं कई अन्य देशों में भी है इसके संगठन पर प्रतिबंध

मसूद अजहर के आतंकी संगठन को भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी आतंकी संगठनों की सूची में डाला गया है। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। इस पर भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भी आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है।

पाकिस्तान ने लगाया था बैन तब बदला था नाम

पाकिस्तान ने पहले इसके संगठन पर प्रतिबंध लगाया था मगर वह दुनिया को दिखावे के लिए था हालांकि वह गुलाम कश्मीर में कई बार रैली और अन्य कार्यक्रमों में भारत के खिलाफ जहर उलगता हुआ देखा गया है। जैश-ए-मुहम्मद को पाकिस्तानी सरकार ने जब 2002 की शुरुआत में बैन कर दिया था तब इसने अपने संगठन का नाम बदलकर 'ख़ुद्दाम-उल-इस्लाम' रख लिया था।

ओसामा से मिलने के बाद बनाया जैश और बना इसका सरगना

31 दिसंबर 1999 को भारत में हुए चर्चित कंधार प्लेन अपहरण में इसे आतंकियों ने भारत के चंगुल से छुड़ा लिया। इसके बाद यह उमर शेख के साथ अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन से मिलने चला गया। वहां करीब एक माह गुजारने के बाद यह पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान की राजधानी कराची में पहुंचते ही यह एक मस्जिद में करीब एक हजार हथियारबंद आतंकियों के साथ मिलकर जैश-ए-मुहम्मद संगठन की स्थापना की। पाक में इसके अलावा वह हरकत-उल-मुजाहिदीन के लिए भी काम कर रहा था। हालांकि बाद में उस संगठन के ज्यादातर आतंकी जैश में शामिल हो गए।

पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक

आतंकी मसूद अजहर का जन्म पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ है, हालांकि इसके जन्म की तारीख को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। कुछ के मुताबिक इसका जन्म 10 जुलाई, 1968 को हुआ था वहीं कुछ एजेंसियों के मुताबिक इसका जन्म सात अगस्त, 1968 को हुआ है। हालांकि इसका पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी स्कूल का प्रधानाध्यापक था। परिवार के लोग डेयरी और पॉल्ट्री कारोबार से जुड़ा था। इसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक मदरसे में ली थी।

6. US may exit weapons trade treaty- भारत भी नहीं है जिस संधि का सदस्य, अब US भी शस्त्र व्यापार संधि से बाहर हो सकता है (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 2020 में होने जा रहे चुनावों को लेकर सबने कमर कस ली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों के साथ ही हथियार कंपनियों को लुभाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि से अमेरिका के हटने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र का यह समझौता भटकाने वाला है। यह बातें उन्होंने नेशनल राइफल एसोसिएशन (एनआरए) के एक कार्यक्रम में कहीं।ट्रंप का कहना है कि यह संधि अमेरिका के आंतरिक कानूनों में दखल देती है। इसके अलावा यह संधि सेकेंड अमेंडमेंड बिल में मिले अधिकारों का भी हनन करती है। बता दें कि अमेरिका में सेकेंड अमेंडमेंट बिल के तहत प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने का अधिकार मिला हुआ है। आपको बता कि अमेरिका समेत लेटिन अमेरिका के लगभग सभी देश, यूरोपीय संघ, अफ्रीका के कई देश, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के देश, मंगोलिया, जापान, आस्ट्रेलिया समेत कुछ अन्य देशों ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। वहीं भारत, चीन और रूस, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

ये है वजह

ट्रंप ने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन (एआरए) के वार्षिक सम्मेलन में इस संधि से बाहर होने की घोषणा की थी। इस संधि के तहत छोटे हथियारों, युद्धक टैंकों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों जैसे पारंपरिक हथियारों का अरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार किया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2013 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। एनआरए लंबे समय से इसका विरोध कर रहा था, लेकिन अमेरिकी सांसदों ने इसका अनुमोदन नहीं किया था।अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दोबारा चुने जाने के प्रयासों के लिए यह कदम उठाया है। उनकी इस घोषणा की कुछ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की है।

क्या है संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि

संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि 24 दिसंबर 2014 को लागू की गई थी। इस संधि की 101 देशों ने पुष्टि कर रखी है और 34 देशों ने केवल हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हथियारों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है। संधि का काम देशों के बीच होने वाले हथियारों के आयात और निर्यात पर निगरानी रखना और उनके लिए नियम बनाना होता है। इस संधि के तहत राइफल, बंदूकों पर मुख्य ध्यान दिया गया है। इसमें शामिल देशों को संयुक्त राष्ट्र को यह रिकॉर्ड देना होता है कि उनके देश में कितने लोगों के पास कितने हथियार हैं। अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। हस्ताक्षर करने का मतलब संधि के नियमों को मानना नहीं होता यह तभी होता है जब आप उसकी पुष्टि कर दें। इसका मतलब उस संधि में अपनी रुचि दिखाना होता है। इसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल लेकर पुष्टि की जाती है।

इस संधि पर भारत का क्या रहा है कदम

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि में हस्ताक्षर नहीं किए थे। बता दें कि भारत भारी मात्र में हथियारों का आयात करता है। भारत के साथ ही रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई देशों ने भी इस संधि में हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने यह कहते हुए संधि का समर्थन करने से इंकार कर दिया कि यह शस्त्र निर्यातक देशों के हित में आयातक देशों के ऊपर थोपा गया कानून है जिसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा यह परंपरागत हथियारों के अवैध व्यापार एवं इनके दुरुपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में भी असमर्थ प्रतीत होती है।

एक नजर इधर भी

आपको बता दें कि दुनिया भर में होने वाले हथियारों के गैर-कानूनी व्यापार और तस्करी से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर वर्ष 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र संघ से एक विनियंत्रण प्रणाली गठित करने की मांग की थी। उनके ही प्रयास स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2006 में प्रस्ताव सं. 61/89 द्वारा एक शस्त्र व्यापार संधि स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जब इस संधि प्रस्ताव को अपनाने के लिए 2 अप्रैल, 2013 को संयुक्त महासभा में मतदान हुआ था तब 154 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में और 3 देशों-ईरान, सीरिया व उत्तर कोरिया ने इसके विरोध में मतदान किया था जबकि भारत सहित 23 देशों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था।

(Adapted from Jagran.com)

7. Action by Pakistan against Masood Azhar- पाक ने वैश्विक आतंकी घोषित होने के बाद मसूद की संपत्ति जब्त की, यात्रा पर भी रोक (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर की संपत्ति जब्त कर ली है। साथ ही उसके विदेश आने-जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मसूद को 1 मई को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था। भारत इसके लिए 10 साल से कोशिशें कर रहा था।

पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार ने आदेश पारित किया है कि अजहर के खिलाफ रेजोल्यूशन 2368 (2017 का) पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अफसरों को निर्देश दिए गए कि मसूद के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह से अमल में लाया जाए। अजहर पर हथियारों की खरीद-बिक्री पर भी बैन लगाया गया है।

'चीजें आपके अनुकूल हो सकती हैं'

यूएन में भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने गुरुवार को बताया कि जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के मामले पर उन्होंने धोनी जैसा नजरिया अपनाया। अकबरुद्दीन ने न्यूज एजेंसी से कहा कि मैं एमएस धोनी के समान काम करने में यकीन रखता हूं। धोनी केवल लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए धीरज बनाए रखते हैं। अकबरुद्दीन ने कहा- धोनी यह मानते हैं कि आखिर में ही सही, मगर चीजें आपके अनुकूल हो सकती हैं। मैं भी यह मानता हूं कि किसी को भी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए।

इससे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, "मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने की एक वजह पुलवामा आतंकी हमला भी है। जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।" प्रवक्ता ने ये भी साफ किया कि इस मामले में चीन का रुख बदलने के पीछे किसी तरह की सौदेबाजी या उसकी कोई शर्त मान लेना नहीं है।"

पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक पराजय

रवीश ने कहा कि जैश सरगना को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना पाकिस्तान के लिए बड़ी कूटनीतिक हार है। भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान तब सामने आया है जब पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने तमाम राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करने के बाद प्रस्ताव पर हामी भरी है। रवीश ने कहा, "संरा की कमेटी नंबर 1267 के सामने हमने इस आतंकी से जुड़े तमाम साक्ष्य रखे और दूसरे देशों से इन्हें साझा भी किया। इसमें पुलवामा हमला भी शामिल था।" 1267 कमेटी आतंकियों और उनके संगठनों पर प्रतिबंध से जुड़े वैश्विक मामलों को देखती है।

मसूद पर 2009 में पहली बार, 2016 में दूसरी बार पेश किया गया प्रस्ताव

पहली बार मनमोहन सरकार ने मुंबई हमले के बाद 2009 में अजहर मसूद के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पेश किया। दूसरी बार 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को यूएन में पेश किया। तीसरी बार 2017 में उड़ी में सेना के कैंप में हमले के बाद ये प्रस्ताव पेश किया गया। चौथी बार पुलवामा हमले के बाद पेश किया गया। मसूद ने 25 साल में भारत में 20 से ज्यादा बड़े आतंकी हमले किए।

भारत में कई हमलों का जिम्मेदार है मसूद

मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमलों को साजिश रचने के साथ उन्हें अंजाम दे चुका है। इसी साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था। इसकी जिम्मेदारी भी मसूद के संगठन जैश ने ली थी। मसूद 2001 में संसद पर हुए हमले का भी दोषी है। इस दौरान नौ सुरक्षाकर्मियों की जान गई थी। इसके अलावा जनवरी 2016 में जैश के आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस और इसी साल सितंबर में उरी में सेना के हेडक्वॉर्टर पर हमला किया था।

(Adapted from Bhaskar.com)

8. One belt one road project linked with China's yes on Masood Azhar- वन बेल्ट प्रोजेक्ट पर भारत का विरोध नहीं चाहता चीन, इसलिए मसूद के मुद्दे पर उसने पाक का साथ छोड़ा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

आतंकी मसूद अजहर के मुद्दे पर चीन आखिरकार भारत की बात मान गया। उसने चार बार भारत की राह में रोड़े अटकाए थे। वह जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं होने दे रहा था। लेकिन भारत की कूटनीतिक कोशिशें कामयाब हुईं और चीन ने अपनी आपत्तियां हटा लीं। दैनिक भास्कर प्लस ऐप ने विदेश मामलों के जानकार रहीस सिंह, चीन मामलों की एक्सपर्ट और स्कॉलर नम्रता हसीजा और भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अफसर सलमान हैदर से बातचीत कर जाना कि चीन आखिर कैसे पाकिस्तान का साथ छोड़ने को राजी हो गया।

अमेरिका ने जिस प्रोजेक्ट को एनाकोंडा बताया, उस पर भारत का विरोध नहीं चाहता चीन

विदेश मामलों के जानकार रहीस सिंह बताते हैं कि चीन ने हाल ही में कहा था कि वह मसूद के मुद्दे पर भारत के साथ नेगोशिएट करना चाहता है। इस मसले पर भारत का साथ देने के पीछे चीन की यह मंशा हो सकती है कि भारत उसके बेल्ट रोड इनीशिएटिव (बीआरआई प्रोजेक्ट) का विरोध न करे। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट को अमेरिका ने एनाकोंडा बताया था, जबकि यूरोपियन यूनियन भी इसका विरोध करता रहा है। भारत भी इस प्रोजेक्ट का शुरू से विरोध कर रहा है। हो सकता है कि चीन यह चाहता हो कि भारत अब कम से कम बीआरआई प्रोजेक्ट का विरोध न करे।

वे बताते हैं कि पाक को अब मसूद पर प्रतिबंध लगाना होगा और उसकी गतिविधियों को बंद करना होगा। अगर पाक ऐसा नहीं करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। फिलहाल पाक ग्रे लिस्ट में है। पाक के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। उसका चालू खाता घाटा इतना है कि वह आगे व्यापार करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए पाक को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी।

भारत ने मुद्दा नहीं छोड़ा, एयरस्ट्राइक का भी असर पड़ा

चीन मामलों की जानकार और स्कॉलर नम्रता हसीजा कहती हैं कि चीन हर बार मसूद के मुद्दे पर रोड़े अटकाता रहा, लेकिन इस बार भारत ने मुद्दे को नहीं छोड़ा और कामयाब भी हुआ। इसके पीछे भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस और यूके का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि तीनों ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव दिया था। पुलवामा हमले के बाद चीन पर काफी दबाव बढ़ा था कि वह आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं अपना सकता। चीन का पाक में ज्यादातर निवेश पाक के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस तरह से एयरस्ट्राइक की, इसका असर भी हुआ। क्योंकि भारत-पाक के बीच तनाव बढ़ने से चीन को भी खतरा है और उसके जो प्रोजेक्ट पीओके में चल रहे हैं, उन पर असर पड़ सकता है।

चीन भारत के साथ आया, क्योंकि उसे अपनी गलती समझ आई

भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अफसर सलमान हैदर का कहना है कि भारत दुनिया को समझाने में कामयाब रहा है कि वह पाकिस्तान की धरती से चलने वाले आतंकवाद से कितना प्रभावित है। चीन ने हर बार मसूद के मुद्दे को वीटो के जरिए टालने की कोशिश की, लेकिन अब उसे अपनी गलती समझ आ गई। इसलिए उसने पाक का साथ छोड़कर भारत का साथ दिया। चीन के इस फैसले के बाद पाक को अपनी धरती से चल रहे आतंक को बंद करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर कई प्रतिबंध लग सकते हैं।

9. ईरान को धमकाने के लिए अमेरिका ने मध्यपूर्व में अपना नौसेना आक्रमण दल भेजा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए मध्यपूर्व में अपना नौसैना आक्रमण दल तैनात करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि इसका मकसद ईरान को साफ संदेश देना है कि अगर उन्होंने अमेरिका या उसके मित्र देशों के हितों का नुकसान किया तो उसे हमारी बेरहम ताकत का सामना करना पड़ेगा।

बोल्टन ने कहा, "हम ईरान से युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। फिर चाहे वह किसी छद्म तरीके से हो या ईरान की सेनाओं की तरफ से।" अमेरिका ने मध्यपूर्व स्थित अमेरिकी सेंट्रल कमांड में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ बॉम्बर टास्क फोर्स को भी भेजा है।

'ईरान की चेतावनियों के बाद लिया फैसला'

बोल्टन के मुताबिक, ईरान की तरफ से कई परेशान करने वाली चेतावनियां मिलीं, जिसके बाद अमेरिका ने यह फैसला किया। उन्होंने अपने बयान में यह साफ नहीं किया कि उन्होंने नौसेना को मध्यपूर्व में तैनात करने के लिए यह समय क्यों चुना। हालांकि, अंदाजा लगाया जा रहा है कि गाजा स्थित फिलिस्तीनी उग्रवादियों के इजरायल पर हमले के बीच ईरान भी मौके का फायदा उठा सकता है।

एक-दूसरे की सेना को आतंकी करार दे चुके दोनों देश

इसके अलावा पिछले साल ही अमेरिका ने ईरान पर परमाणु संधि तोड़ने का आरोप लगाया था। अमेरिका का कहना था कि ईरान बिना अनुमति के अपने यूरेनियम का संवर्द्धन कर रहा है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने ईरान के सैनिक संगठन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) को भी आतंकी संगठन करार दे दिया है। जवाब में ईरान भी अमेरिकी सेना को मध्य-पूर्व में आतंकी बताकर कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है।

10. अमेरिका 200 अरब डॉलर के चाइनीज इंपोर्ट पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% करेगा
(Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

चीन से व्यापार वार्ता के बीच अमेरिका ने कहा है कि वह 10 मई को 200 अरब डॉलर (13.84 लाख करोड़ रुपए) के चाइनीज इंपोर्ट पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर देगा। अमेरिका का कहना है कि वार्ता बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को ट्वीट कर टैरिफ बढ़ाने की बात कही। साथ ही धमकी दी कि 325 अरब डॉलर (24.49 लाख करोड़ रुपए) के अतिरिक्त इंपोर्ट पर भी जल्द 25% शुल्क लगाया जाएगा।

चीन सौदेबाजी करना चाहता है: ट्रम्प

1. चीन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का व्यापार वार्ता के सिलसिले में बुधवार को अमेरिका जाने का कार्यक्रम था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प की धमकी की वजह से चीन इसे रद्द कर सकता है।

2. ट्रम्प ने कहा है कि चीन 10 महीने से 50 अरब डॉलर के इंपोर्ट पर 25% और 200 अरब डॉलर के इंपोर्ट पर 10% शुल्क दे रहा है। चीन के साथ व्यापार वार्ता जारी है लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है क्योंकि चीन फिर से सौदेबाजी करना चाहता है।

3. अमेरिका और चीन के बीच पिछले साल मार्च में ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर आयात शुल्क बढ़ाया। नवंबर में डोनाल्ड ट्रम्प और चीन के राष्ट्रपति शी-जिनपिंग जी-20 में मिले तो ट्रेड वॉर खत्म करने के लिए व्यापार वार्ता शुरू करने पर सहमति बनी। उस वक्त ट्रम्प इस बात के लिए राजी हुए थे कि मार्च तक टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। वार्ता जारी रहने की वजह से मार्च में फिर से डेडलाइन बढ़ा दी गई।

4. चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 378.73 अरब डॉलर

अमेरिका चाहता है कि चीन के साथ उसका व्यापार घाटा कम हो। पिछले साल यह 378.73 अरब डॉलर रहा था। यूएस की यह मांग भी है कि उसके उत्पादों की चीन के बाजार में पहुंच बढ़े और चीन में अमेरिकी कंपनियों पर टेक्नोलॉजी शेयर करने का दबाव खत्म किया जाए।

(Adapted from Bhaskar.com)

11. IMF प्रमुख ने कहा, अमेरिका और चीन के बीच तनाव से दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरा
(Relevant for GS Prelims and GS Mains Paper II; IOBR)

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष)IMF) की प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच हालिया तनाव की स्थिति दुनिया की अर्थव्यस्था के लिए खतरनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन के उत्पादों पर टैरिफ शुल्क को 10 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद करने की चेतावनी दी है।

आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने बताया, "अमेरिका और चीन के बीच तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट रूप से खतरा है। पेरिस में एक कान्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ताजा " के बीच किसी व्यापार समझौते के होने की (चीन-अमेरिका) से दोनों देशों 'अफवाहों और ट्वीट्स' संभावनाएं घटी हैं।

वहीं पेरिस फोरम इवेंट में बोलते हुए फ्रांस के इकोनॉमी मिनिस्टर ब्रूनो ली मैरे ने भी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच तनाव के प्रभाव के बारे में चेताया था। उन्होंने कहा, "हम चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मौजूदा बातचीत पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि वे पारदर्शिता और बहुपक्षवाद के सिद्धांतों का सम्मान करें।इस " बीच चीन ने कहा है कि उसके शीर्ष व्यापार वार्ताकार अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे और अपने समकक्षों से बातचीत करेंगे।

SOURCE: https://www.jagran.com/

12. ट्रम्प ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए, लोहा-स्टील समेत 4 धातुओं का निर्यात नहीं कर सकेगा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

अमेरिका ने ईरान पर बुधवार को नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध लोहा, स्टील, एल्युमीनियम और तांबे के निर्यात पर लगाए गए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक, ईरान के कुल निर्यात का 10% इन्हीं धातुओं के निर्यात से मिलता है। अमेरिका के नए प्रतिबंधों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है।

ट्रम्प ने कहा, "मैंने ईरान के लोहा, स्टील, एल्युमीनियम और तांबा सेक्टर पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। ईरान के निर्यात राजस्व का सबसे बड़ा गैर-पेट्रोलियम स्रोत यही है। प्रतिबंधों का मकसद ईरान को धातुओं के निर्यात से होने वाले राजस्व में कटौती करना है। हम दूसरे देशों से भी यही कहना चाहते हैं कि ईरान से आने वाले स्टील और अन्य धातुओं को अपने बंदरगाहों पर न उतरने दें।"

गलत जगह इस्तेमाल कर सकता है रकम

ट्रम्प ने ईरानी अधिकारियों से मिलने की भी इच्छा जताई है। साथ ही आदेश में यह भी कहा कि ईरान धातुओं के निर्यात से मिलने वाली रकम को बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद, आतंकी गुटों और उनके नेटवर्क को मदद देने और सैन्य विस्तार में इस्तेमाल कर सकता है। ट्रम्प के मुताबिक- अमेरिका इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ईरान किसी भी रूप से परमाणु हथियार और अंतरमहाद्वीपीय (इंटरकॉन्टिनेंटल) बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे न बढ़ा सके।

ईरान का एटमी डील की कुछ शर्तों को मानने से इनकार

ईरान ने बुधवार को 2015 की एटमी डील की कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही अमेरिका ने उस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ईरान, रूस, चीन, फ्रांस, यूके और जर्मनी समझौते में शामिल हैं। 2018 में अमेरिका ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया था।

ईरान से तेल खरीदने वाले देशों को प्रतिबंधों में छूट नहीं

अप्रैल में अमेरिकी सरकार ने फैसला लिया कि ईरान से तेल आयात करने वाले देशों को अब प्रतिबंधों से कोई छूट नहीं दी जाएगी। मई में भारत समेत 8 देशों को प्रतिबंधों में मिली छूट की मियाद खत्म हो रही है। व्हाइट हाउस की सचिव सारा सैंडर्स के मुताबिक, इसके फैसले का मकसद ईरान का तेल आयात शून्य करना है। सैंडर्स ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक देश अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई अपने साथियों के साथ इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि वैश्विक तेल बाजार में पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होती रहे। उधर, सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार इस फैसले का अध्ययन कर रही है और सही वक्त आने पर इस पर कुछ कहेगी।

दोनों देशों के बीच बढ़ सकता है तनाव

दो दिन पहले ही अमेरिका ने मध्यपूर्व में अपना नौसैना आक्रमण दल तैनात करने का फैसला किया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन ने कहा कि इसका मकसद ईरान को साफ संदेश देना है कि अगर उन्होंने अमेरिका या उसके मित्र देशों के हितों का नुकसान किया तो उसे हमारी बेरहम ताकत का सामना करना पड़ेगा। बोल्टन ने कहा, "हम ईरान से युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। फिर चाहे वह किसी छद्म तरीके से हो या ईरान की सेनाओं की तरफ से।"

13. चीन में खत्म की जा रही मुसलमानों की पहचान, शिनजियांग प्रांत में रोजा रखने पर प्रतिबंध (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

चीन के शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों की पहचान खत्म की की जा रही है। वहां रहने वालों मुसलमानों के खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रमजान की शुरुआत होते ही मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में सरकारी अधिकारियों, छात्रों और बच्चों के रोजे रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन की सरकारी वेबसाइट पर इस बारे में निर्देश जारी किया गया।

शिनजियांग प्रांत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर इस प्रतिबंध को लागू करने में जुटे हैं। यहां तक कि चीन का सबसे प्रमुख दोस्त पाकिस्तान भी इस मुद्दे पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जबकि कुछ समय पहले व्यापारिक समझौते के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चीन की यात्रा की थी।

चीन का दावा है कि शिनजियांग ओइगर ऑटोनॉमस रीजन (एक्सयूएआर) में सामाजिक स्थिरता बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हयूमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) की इसी हफ्ते जारी की गई रिपोर्ट में इस बारे में दावा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति ने उइगर मुस्लिमों के साथ किए जा रहे इस व्यवहार पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

उइगर मुस्लिमों पर रखी जा रही है कड़ी नजर, किया जा रहा उत्पीड़न

रिपोर्ट में कहा गया है कि रि-एजुकेशनल कैंपों में दौरों के बीच अधिकारी मुसलमानों से उनकी जिंदगी और राजनीतिक विचारों के बारे में पूछताछ करते हैं। एक तरह से वे उनका राजनीतिक शुद्धीकरण करना चाहते हैं। एचआरडब्लू की रिसर्चर माया बैंग ने बताया कि शिनजियांग में रहने वाले मुस्लिम परिवार अपने ही घर में कड़ी निगरानी में रहने को मजबूर हैं। यहां तक कि वे क्या खाते हैं और कब सोते हैं, इस बारे में भी सीपीसी को खबर रहती है।

संयुक्त राष्ट्र की निगरानी समूहों का कहना है कि उइगरों मुस्लिमों को चौकसी और सुरक्षा अभियानों के बहाने निशाना बनाया गया है। हजारों उइगर मुस्लिमों को हिरासत में रखा गया है और उन्हें विचारधारा बदलने वाले केंद्रों में भेज दिया गया है। विदेशों से शिनजियांग प्रांत में लौटने वाले सैकड़ों उइगर छात्र गायब हो गए हैं। उनमें से कई हिरासत में हैं और कई हिरासत में मर भी चुके हैं।

कट्टरता विरोधी शिविरों में रखा जाता है कैद

संयुक्त राष्ट्र की निगरानी समिति के एक अनुमान के मुताबिक है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को तथाकथित कट्टरता विरोधी शिविरों में कैद करके रखा गया है और अन्य 20 लाख को राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा बदलने वाले तथाकथित पुनर्शिक्षण शिविरों में जबरन भेजा गया है।

चीन में मुसलमानों को सूअर खाने को किया जाता है विवश

शिनजियांग प्रांत की जेल में दो महीने कैद में समय बिताने वाले ओमिर बेकाली ने कहा कि चीन में चल रहे इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य लोगों की धार्मिक सोच खत्म कर देना है। इस्लाम में सूअर खाने की सख्त मनाही है। चीन के इन शिविरों में मुसलमान को शुक्रवार के दिन सूअर खाने को विवश किया जाता है, जबकि यह दिन इस्लाम मानने वालों के लिए सबसे पवित्र है।

नमाज अदा करने और दाढ़ी रखने पर हिरासत में किया जाता है बंद

ओमिर ने बताया कि नमाज अदा करने और दाढ़ी बढ़ाने वालों को भी ये लोग कट्टरवादी कहकर हिरासत में बंद कर देते हैं। बंधकों को अपनी स्थानीय भाषा बोलने की भी आजादी नहीं है। कैदियों को स्टुडेंट कहकर बुलाने वाले अधिकारी सहित सारे लोग सिर्फ चीनी भाषा इस्तेमाल करते हैं। ओमिर उन गिने-चुने लोगों में से हैं जो चीन की इन शिविरों से अभी तक बाहर निकल पाए हैं।

चीन में राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व में उइगर मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत किसी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गली-चौराहों पर सख्त निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जाती है। उइगर समुदाय का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके घरों के अंदर भी नजर रखनी शुरू कर दी है।

जबरन लगवाए जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नारे

एमनेस्टी और मानवाधिकार वाच समेत कई मानवधिकार संगठनों का दावा है कि इन शिविरों में जबरन चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की वफादारी की कसम दिलवाई जाती है। विश्व उइगर कांग्रेस का कहना है कि शिविरों में बिना आरोप बंदी बनाकर रखा जाता है और जबरन कम्युनिस्ट पार्टी के नारे लगाने को कहा जाता है। हालांकि चीन ने इन आरोपों से इनकार किया है।

SOURCE: https://www.jagran.com/

14. दक्षिण चीन सागर में अमेरिका संग भारत और जापान ने किया सैन्य अभ्यास (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

अमेरिका, भारत, जापान और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे वाले जलमार्ग क्षेत्र में संयुक्त नौसेना अभ्यास कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका का विध्वंसक पोत, भारत के दो युद्धपोत, जापान का विमानवाहक पोत और फिलीपींस का गश्ती पोत शामिल हुए। चारों देश इसी तरह का सैन्य अभ्यास इस क्षेत्र में पहले भी कर चुके हैं जिस पर चीन ने नाराजगी जताई थी।

अमेरिकी नौसेना के कमांडर एंड्रयू जे क्लग ने गुरुवार को कहा, 'यह पेशेवर जुड़ाव क्षेत्र में हमारे सहयोगियों, साझीदारों और मित्र देशों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने का अवसर है।' क्लग अमेरिकी विध्वंसक पोत यूएसएस विलियम पी लॉरेंस के कैप्टन हैं। एक हफ्ते चला नौसैनिक अभ्यास बीते बुधवार को समाप्त हुआ। इसमें जापान ने अपने दो बड़े विमानवाहक युद्धपोतों में से एक इजुमो को भेजा था। जबकि भारत के विध्वंसक पोत आइएनएस कोलकाता और टैंकर आइएनएस शक्ति ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया।

इस युद्धाभ्यास के दौरान ही बीते सोमवार को अमेरिका के दो अन्य युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे वाले द्वीपों के पास से गुजरे थे। चीन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसके जवाब में अमेरिकी नौसेना ने कहा था कि वह दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही के लिए इस तरह के अभियान करती रहती है।

पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा

चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। जबकि इस क्षेत्र के देशों ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना-अपना दावा करते हैं।

(Source: https://www.jagran.com/)

15. भूटान और भूटान के प्रधानमंत्री के बारे में क्या खास है? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

भूटान के प्रधानमंत्री एम लोटे टीशेरिंग शनिवार को डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। भूटान की जनसंख्या 7,50,000 है। पीएम का दावा है कि डॉक्टर के रूप में काम करना और सर्जरी करना उनके लिए एक तनाव को दूर करने का काम है।

क्यों खास है भूटान?

1. बौद्ध साम्राज्य भूटान ने खुद को आर्थिक विकास के बजाय ख़ुशी के लिए बेंचमार्क किया।

2. सकल राष्ट्रीय खुशी के स्तंभों में से एक पर्यावरण का संरक्षण है। भूटान कार्बन नेगेटिव है और इसका संविधान कहता है कि देश का 60% हिस्सा वनाच्छादित है। यह पर्यावरणीय पर्यटन पर भी कार्य करता है और तेज़ी के मौसम में प्रति आगंतुक से 250 डॉलर का दैनिक शुल्क लेता है।

3. राजधानी थिम्पू में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है, और टेलीविजन को केवल 1999 में अनुमति दी गई थी।

4. तीरंदाजी प्रतियोगिताएं पूरे राष्ट्र में मशहूर हैं। बुराई को दूर करने के लिए घरों पर चित्रित फालूस भी एक आम दृश्य हैं।

5. भूटान में स्वास्थ्य सेवा के लिए मरीजों को सीधे भुगतान नहीं करना पड़ता है। जबकि देश में जीवन प्रत्याशा में बड़े सुधार, शिशु मृत्यु दर में कमी और कई संक्रामक रोगों के उन्मूलन, जीवनशैली रोगों की संख्या - शराब और मधुमेह सहित - में वृद्धि देखी गई है।

लेकिन भूटान को "थंडर ड्रैगन की भूमि" भी कहा जाता है, जिसमें इसकी समस्याएं भी हैं, उनमें से भ्रष्टाचार, ग्रामीण गरीबी, युवा बेरोजगारी और आपराधिक गिरोह हैं।

16. 180 देश प्लास्टिक कचरे के निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए सहमत हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

हानिकारक कचरे के सीमापार गतिविधि पर बेसल कन्वेंशन

बैठक जिनेवा में आयोजित की गई थी। जिनेवा की बैठक ने 1989 के बेसल कन्वेंशन में संशोधन कर हानिकारक कचरे के सीमापार गतिविधि के नियंत्रण को कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे में प्लास्टिक कचरे को शामिल किया।

संशोधन की आवश्यकता है

हानिकारक और जहरीले रसायनों को खत्म करने की मांग करने वाले IPEN छत्रक समूह ने कहा कि नया संशोधन विकासशील देशों को दूसरों द्वारा "प्लास्टिक कचरे को डंप करने" से मना करने के लिए सशक्त करेगा। “बहुत लंबे समय से, यू.एस. और कनाडा जैसे विकसित देश अपने मिश्रित जहरीले प्लास्टिक कचरे को विकासशील एशियाई देशों को निर्यात कर रहे हैं, उनका दावा है कि इसे प्राप्त करने वाले देश में पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा। भले ही अमेरिका और कुछ अन्य ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन वे उन देशों को प्लास्टिक कचरा नहीं भेज सकते हैं जो इस समझौते पर हैं।

डिकोफोल और पेरफ्लुओरोक्टानोइक एसिड

बैठक में दो जहरीले रासायनिक समूहों को खत्म करने के लिए भी काम किया गया - डायकोफॉल और पेरफ्लूरोक्टानोइक एसिड, साथ ही संबंधित यौगिक। उत्तरार्द्ध का उपयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और घरेलू अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें नॉन-स्टिक कुकवेयर और खाद्य प्रसंस्करण उपकरण, साथ ही कालीन, कागज और पेंट शामिल हैं।

IPEN के बारे में

IPEN एक जनहित के गैर-सरकारी संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो एक ऐसी दुनिया के लिए एक साथ काम कर रहा है, जिसमें जहरीले रसायनों का उत्पादन या उपयोग उन तरीकों से नहीं किया जाता है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।

IPEN की स्थापना 1998 में हुई थी और यह स्वीडन में एक गैर-लाभकारी, जनहित संगठन के रूप में पंजीकृत है। यह 100 से अधिक देशों में 500 से अधिक भाग लेने वाले संगठनों में शामिल है, मुख्य रूप से विकासशील और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था वाले देशों में।

(Source:https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-life/180-nations-agree-to-curb-export-of-plastic-waste/article27106145.ece**)**

17. दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका और चीन) के बीच व्यापार विवाद कैसे शुरू हुआ? यदि उनका गतिरोध व्यापक आर्थिक संघर्ष में बढ़ जाता है तो क्या होगा? इससे भारत और शेष विश्व कैसे प्रभावित हो सकते हैं? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

200 बिलियन डॉलर के चीनी सामान पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया है। इस कदम से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टैरिफ युद्धों का एक और दौर शुरू हो गया है। उच्चतर टैरिफ अब अमेरिका में सभी चीनी आयातों पर लागू होते हैं।

अमेरिका-चीन विवाद की उत्पत्ति

पिछले साल मार्च में चीन से आयातित स्टील और एल्यूमीनियम वस्तुओं पर ट्रम्प द्वारा भारी शुल्क लगाने के बाद से अमेरिका और चीन के बीच संघर्षपूर्ण युद्ध शुरू हुआ। चीन ने अरबों डॉलर के अमेरिकी आयात पर बराबर टैरिफ लगाकर जवाब दिया।

वाशिंगटन के मांग के बाद विवाद बढ़ गया कि चीन ने अमेरिका के साथ अपने 375 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे को कम किया, और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और चीनी बाजारों में अमेरिकी माल की अधिक पहुंच के लिए "सत्यापन योग्य उपाय" पेश किए।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापार युद्ध का प्रभाव

1. आईएमएफ ने कहा कि अमेरिका-चीन व्यापार तनाव एक कारक था जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर को कम करने में योगदान दिया।

2. उच्च आयात टैरिफ होने से आयात की कीमत बढ़ जाएगी और इस तरह दोनों देशों में खपत पर असर पड़ेगा।

3. व्यापार तनाव एक तेजी से खंडित वैश्विक व्यापार ढांचे में परिणाम हो सकता है।

दोनों देशों के बीच टैरिफ को कम करने के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि अभी भी उम्मीद है कि दोनों देश अपने मुद्दों को सुलझा लेंगे, लेकिन व्यापार वार्ता में पूर्ण विश्लेषण का खतरा बढ़ गया है।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत कैसे प्रभावित होता है?

1. शेयर बाजारों पर अल्पकालिक प्रभाव हो सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेंचमार्क सेंसेक्स अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों के अनुरूप गिर रहा है।

2. लंबे समय में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए अच्छी नहीं है।

3. हालांकि, भारत दुनिया की शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनाव से लाभ उठा सकता है।

क्या व्यापार विवाद WTO में जाएगा?

हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मामला विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में जाएगा, डेटा बताता है कि अमेरिका आमतौर पर व्यापार विवादों को जीतता है, विशेष रूप से चीन के खिलाफ, वैश्विक व्यापार मध्यस्थ से पहले। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमीज के अनुसार, पिछले 16 वर्षों में, अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ में चीनी कार्यों को 23-0 से चुनौती दी है, जिसमें 19-0 की जीत-हार का रिकॉर्ड है - जिसमें चार मामले लंबित हैं। सबसे हालिया फैसले में, डब्ल्यूटीओ पैनल ने पाया कि चीन की कृषि सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के नियमों के साथ असंगत थी, और अमेरिकी दावों को बरकरार रखा।

अमेरिका-चीन व्यापार और निवेश तथ्य

-यूएस वस्तु और सेवा व्यापार चीन के साथ 2018 में अनुमानित $737.1 बिलियन था। निर्यात: $179.3 बिलियन; आयात: $557.9 बिलियन; घाटा: $378.6 बिलियन

-चीन 2018 में कुल 659.8 बिलियन डॉलर (टू-वे) माल व्यापार के साथ यूएस का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है। निर्यात: $120.3 बिलियन; आयात: $539.5 बिलियन; अमेरिकी माल व्यापार घाटा: $419.2 बिलियन

-चीन में सेवाओं (निर्यात और आयात) के साथ 2018 में अनुमानित $ 77.3 बिलियन का कुल निर्यात। निर्यात: $ 58.9 बिलियन; आयात: $ 18.4 बिलियन; अमेरिकी सेवाएं व्यापार अधिशेष: $ 40.5 बिलियन

-911,000 नौकरियां (अनुमानित) अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार 2015 में चीन को वस्तु और सेवाओं के निर्यात (नवीनतम डेटा उपलब्ध) द्वारा समर्थित थे; माल निर्यात द्वारा समर्थित 601,000; सेवाओं के निर्यात द्वारा समर्थित 309,000

-यूएस एफडीआई 2017 में चीन (स्टॉक) $ 107.6 बिलियन था, 2016 से 10.6% की वृद्धि। चीन में अमेरिकी प्रत्यक्ष निवेश विनिर्माण, थोक व्यापार, वित्त और बीमा द्वारा जुड़ा हुआ है।

-अमेरिका में -चीन एफडीआई 2017 में $ 39.5 बिलियन था, जो 2016 से 2.3% नीचे है। अमेरिका में चीन का प्रत्यक्ष निवेश विनिर्माण, रियल एस्टेट, डिपॉजिटरी संस्थानों द्वारा जुड़ा हुआ है।

(Source: https://indianexpress.com/article/explained/simply-put-the-us-china-trade-war-trump-tariffs-5724261/)

18. पाकिस्तान को तीन वर्षों में आईएमएफ से $6 बिलियन प्राप्त होना (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

आईएमएफ के साथ क्या सौदा है?

पाकिस्तान ने एक बेलआउट पैकेज पर आईएमएफ के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत तीन वर्षों में नकदी-तंगी वाले देश को 6 बिलियन डॉलर मिलेंगे। स्टाफ-स्तरीय समझौता अब वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के निदेशक मंडल द्वारा औपचारिक अनुमोदन का इंतजार कर रहा है। इस समझौते का उद्देश्य आईएमएफ के अनुसार, "घरेलू और बाहरी असंतुलन को कम करके मजबूत और अधिक समावेशी विकास के लिए पाकिस्तान की रणनीति" का समर्थन करना है।

बेलआउट पैकेज का इतिहास

नवीनतम सौदा 22 वां बेलआउट पैकेज होगा क्योंकि पाकिस्तान 1950 में IMF का सदस्य बना था। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2018 में आईएमएफ से बेलआउट पैकेज के लिए संपर्क किया जब इमरान खान सरकार ने सत्ता संभाली।

पैकेज के संभावित प्रभाव

प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा आईएमएफ द्वारा कुछ कठोर शर्तों पर आपत्ति जताने के बाद अंतिम परिणाम में और देरी हुई। इससे पहले, पाकिस्तान सरकार आईएमएफ पैकेज के बारे में कठिन परिस्थितियों के कारण अस्पष्ट थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पैकेज आम लोगों के लिए आर्थिक कठिनाइयों की एक सुनामी लाएगा, जिसमें गैस और बिजली सहित सामान और उपयोगिताओं की ऊंची कीमतें, ईंधन की कीमतों में अधिक वृद्धि और रुपये का और अवमूल्यन शामिल हैं।

(Source:https://thewire.in/south-asia/pakistan-to-get-6-billion-from-imf-over-three-years)

19. अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी के जवाब में चीन 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के माल पर टैरिफ बढ़ोतरी कर रहा है (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

चीन टैरिफ में बढ़ोतरी कर रहा है

चीन ने घोषणा की कि वह 1 जून से लगभग सभी चीनी आयातों के लिए अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के नवीनतम दौर के प्रतिशोध में 60 अरब डॉलर के अमेरिकी माल पर टैरिफ बढ़ाएगा।

यूएस द्वारा टैरिफ वृद्धि पर जवाब

यह घोषणा अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता के नवीनतम दौर के बाद पिछले सप्ताह बिना किसी सौदे के समाप्त हो गई, और वाशिंगटन द्वारा 200 बिलियन डॉलर मूल्य के चीनी सामानों पर शुल्क बढ़ाए जाने के बाद यह घोषणा की गई।

इससे पहले, अमेरिका ने सितंबर में 200 बिलियन डॉलर के चीनी आयात पर 10% टैरिफ लगाया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी $ 300 बिलियन की चीनी वस्तुओं पर नए शुल्कों को लागू करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था।

संकल्प के लिए रखा गया समय

प्रतिशोध के बावजूद,बीजिंग ने 1 जून की तारीख निर्धारित करके एक प्रस्ताव खोजने का समय दिया।

(Source: https://www.thehindu.com/news/international/china-hits-back-imposes-tariff-hike-on-us-goods-worth-60-bn/article27119987.ece)

20. विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। इसका भारत पर क्या प्रभाव है; भारत के समक्ष राजनयिक रूप से और ईरान के तेल के आयातक के रूप में क्या चुनौतियां हैं? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की।

ईरान के खिलाफ अमेरिका की हालिया कार्रवाई क्या है?

चार साल के अंतराल के बाद ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के साथ, भारत अनिश्चित स्थिति में है। यह ईरान से तेल आयात नहीं कर सकता है, 1 मई के बाद अमेरिका ने ईरानी तेल आयात करने से भारत पर लगे प्रतिबंधों पर छूट को हटा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव हाल ही में बढ़ा। यूएस ने अमेरिकी मध्य कमान क्षेत्र के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और एक बॉम्बर टास्क फोर्स की तैनाती की।

ईरान को निशाना बनाने के लिए ट्रम्प की चाल, और सऊदी अरब और इज़राइल के साथ पक्ष,से संभावित रूप से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 8 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी श्रमिक पश्चिम एशियाई क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं।

इस समय ज़रीफ़ की यात्रा का क्या महत्व है?

ज़रीफ़ की यात्रा तेहरान द्वारा रैली समर्थन के लिए एक रणनीतिक कदम है। एक कुशल राजनयिक जो ईरान और पी-5 + 1 देशों के बीच संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) वार्ता में सबसे आगे था, ज़रीफ़ दिल्ली आने से पहले ही चीन और रूस में जा चुके हैं।

ईरान और अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ रहे तनाव के संबंध में भारत कहां खड़ा है?

भारत ने ईरान को संदेश दिया है कि वह जेसीपीओए समझौते के सभी पक्षों को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जारी रखेगा और सभी पक्षों को "रचनात्मक रूप से" संलग्न होना चाहिए और सभी मुद्दों को "शांतिपूर्वक और बातचीत के माध्यम से" हल करना चाहिए।

क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी तनाव इन भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाला है और यहां तक कि उन्हें जोखिम में डाल सकता है। पिछली तनावपूर्ण स्थितियों में, भारत को इस क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालना पड़ा। लेकिन खाली करने की इसकी क्षमता सीमित है - हजारों से अधिक नहीं।

कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ता के रूप में और व्यापक कूटनीतिक और रणनीतिक अर्थ में ईरान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?

इराक और सऊदी अरब के बादईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। यह 2010-11 तक सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन प्रतिबंधों ने बाद के वर्षों में इसे सातवें स्थान पर ले आया।

2 मई से ईरान से कच्चे तेल का आयात करने वाले देशों के लिए छूट समाप्त करने के अमेरिकी निर्णय से भारत के हितों को चोट पहुंच सकती है, क्योंकि इसे वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी होगी।

इस समय प्रतिबंधों पर विभाजन

प्रतिबंधों के पिछले सेट के दौरान, जो 2010 में लगाए गए थे, इस बार दुनिया प्रतिबंधों को लेकर विभाजित है। अमेरिका को छोड़कर, अन्य भागीदारों - विशेष रूप से यूरोपीय संघ और तीन प्रमुख यूरोपीय देशों यूके, जर्मनी और फ्रांस ने समझौते के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

चाबहार बंदरगाह विकास पर अमेरिका और भारत का साझा रुख

हालाँकि, एक एकमात्र अस्वीकृति यह है कि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के विकास पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि दिल्ली और वाशिंगटन के अफगानिस्तान तक पहुँचने के उद्देश्य दोनों समान हैं। चाबहार क्षेत्र में भारत का रणनीतिक निवेश है और अफगानिस्तान के लिए एक पहुंच बिंदु के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्योंकि संघर्ष-ग्रस्त देश बंदरगाह विहीन देश है। इसे मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है, जो सीधे भारत के लिए दुर्गम है। यह बंदरगाह सामरिक रूप से पाकिस्तान को घेरने और अफगानिस्तान पहुंचने का एकमात्र रास्ता है।

(Source: https://indianexpress.com/article/explained/simply-put-why-iran-ministers-visit-matters-5727853/)

21. चीन ने विकिपीडिया को सभी भाषाओं में अवरुद्ध कर दिया है (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

चीन ने विकिपीडिया को बंद कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइट चीन में लंबे समय से अवरुद्ध हैं। संवेदनशील मुद्दों के बारे में व्यक्तिगत विकिपीडिया लेख, जैसे कि तियानमेन स्क्वायर और तिब्बत में लोकतंत्र समर्थक विरोध लंबे समय से चीन में अवरुद्ध हैं, हालांकि, मुख्य साइट उपलब्ध थी।

विकिपीडिया पर कुल ब्लॉक का संदेह अप्रैल के अंत में सामने आया जब कुछ चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि साइट अब उपलब्ध नहीं थी।

दमन का संभावित कारण

चीन में इंटरनेट प्राधिकरण अक्सर प्रमुख राजनीतिक घटनाओं या संवेदनशील वर्षगांठ से पहले सेंसरशिप बढ़ाते हैं। इस जून में 30 वर्ष पूरे होंगे जब सेना ने तियानमेन स्क्वायर के आसपास लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल किया था।

(Source:https://www.thehindu.com/news/international/china-blocks-wikipedia-in-all-languages/article27141724.ece)

22. पाकिस्तान के आईएमएफ बेलआउट को समझना (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी अस्थिरता को जारी रखा है, इसकी सर्पी अर्थव्यवस्था को 3 दशकों में 13वीं बार बेलआउट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आवश्यकता है। इसकी वित्तीय स्थिति कितनी भयावह है, यह यहां कैसे पहुंची?

रविवार को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने $ 6 बिलियन के ऋण के साथ पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की, जिसे 39 महीनों में वितरित किया जाएगा। संवितरण निधि के प्रबंधन और उसके कार्यकारी बोर्ड द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बाद शुरू होगा।

फंड के साथ पाकिस्तान के बेलआउट सौदे का राजनीतिक संदर्भ क्या है?

यह पिछले तीन दशकों में पाकिस्तान के लिए IMF का 13 वाँ बेलआउट पैकेज है। आईएमएफ ऋण लगभग हमेशा कठिन परिस्थितियों के साथ आते हैं। अतीत में उनके पास आरक्षण होने के बावजूद, इमरान खान के पास आईएमएफ के साथ बातचीत करने के अलावा बहुत कम विकल्प थे। सितंबर 2013 में, निर्वाचित होने के तीन महीने के भीतर, नवाज शरीफ सरकार ने निधि से $ 6.6 बिलियन का ऋण स्वीकार कर लिया, जिसे तीन साल में समाप्त कर दिया गया।

और वे कौन सी आर्थिक स्थितियां हैं जिनमें पाकिस्तान ने फंड के साथ समझौता किया?

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आकार $313 बिलियन है। पिछले 12 वर्षों में विकास दर 3.5% सालाना रही है। देश में मुद्रास्फीति की उच्च दर और विशाल राजकोषीय और चालू खाता घाटा है। पाकिस्तानी रुपया का दिसंबर 2017 से कई बार अवमूल्यन किया गया है, और पिछले 18 महीनों में लगभग 35% खो दिया है।

तो, पाकिस्तान के लिए यह बेलआउट कितनी जरूरी थी?

सत्ता में आने के बाद, खान मदद के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और चीन तक पहुँच गया है। रियाद ने पिछले साल अक्टूबर में भुगतान समर्थन संतुलन में 3 बिलियन डॉलर का वादा किया था, और यूएई ने दिसंबर में पाकिस्तान को $ 3 बिलियन का समर्थन किया था। इस साल फरवरी में, चीन ने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए ऋण और अनुदान में $ 3.5 बिलियन का विस्तार किया।

लेकिन इस समस्या को दूर करने में इन सभी से मदद नहीं हुई है। 3 मई, 2019 को समाप्त सप्ताह के लिए, भारतीय स्टेट बैंक, देश के केंद्रीय बैंक के साथ शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार $ 8.9 बिलियन था। ये विदेशी मुद्रा भंडार केवल दो महीने के आयात के लिए पर्याप्त हैं। वित्त वर्ष 2018 में पाकिस्तान का आयात $ 56 बिलियन था।

आईएमएफ ने पाकिस्तान पर किस तरह की शर्तें लगाई हैं?

मोटे तौर पर, आईएमएफ सरकार से कर आधार का विस्तार करने, छूट दूर करने और विशेष उपचारों पर रोक लगाने की उम्मीद करेगा, यह देखते हुए कि पाकिस्तान में 208 मिलियन में से लगभग एक मिलियन लोग करों का भुगतान करते हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र में कटौती और उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और सब्सिडी को कम करने के लिए कहेगा।

आईएमएफ पाकिस्तान से यह भी उम्मीद करेगा कि वह रुपया 'अस्थाई' करे - अर्थात, इसके मूल्य को बाजार को निर्धारित करने की अनुमति दे- और पाकिस्तान के स्टेट बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए नीतिगत दरों में और वृद्धि करे।

क्या यह सब काम करने की उम्मीद है?

IMF के साथ समझौतों पर अडिग रहने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड उत्साहजनक नहीं है। यह अक्सर राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी खरीदने और बेचने जैसी स्थितियों को पूरा करने में विफल रहा है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए साहसिक कदम

उठाने की आवश्यकता है और जैसा कि यह उस दिशा में आगे बढ़ता है, यह सुनिश्चित करे कि उसके गरीबों को मितोपभोग उपाय से नुकसान न हो।

(Source;https://indianexpress.com/article/explained/simply-put-understanding-pakistans-imf-bailout-5729934/)

23. ताइवान समलैंगिक विवाह: संसद ने समान-लिंग विवाह को वैध बनाया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

समान-लिंग विवाह को वैध बनाने में ताइवान की संसद एशिया में पहली संसद बन गई है।

हम यहां कैसे पहुंचे?

2017 में, ताइवान की संवैधानिक अदालत ने फैसला सुनाया कि समान-लिंग जोड़ों को कानूनी रूप से शादी करने का अधिकार था। अदालत द्वारा संसद को दो साल की समय सीमा दी गई थी।

यह इस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना कैसे करता है?

वियतनाम ने 2015 में समलैंगिक विवाह समारोह का अपराधीकरण नहीं किया,लेकिन समान-लिंग संघों के लिए पूर्ण कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया।

जबकि चीन में समलैंगिक विवाह अभी भी अवैध है, लेकिन 1997 में देश में समलैंगिकता का अपराधीकरण नहीं किया गया था, और तीन साल बाद आधिकारिक रूप से इसे मानसिक बीमारियों की सूची से हटा दिया गया था।

एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समलैंगिक यौन संबंध सितंबर 2018 से आपराधिक अपराध नहीं है।

हालाँकि अन्य एशियाई देशों में दृष्टिकोण भिन्न है। अप्रैल में, ब्रुनेई ने सख्त नए इस्लामिक कानूनों की घोषणा की, जो गुदा मैथुन और व्यभिचार के अपराध को पत्थर मारकर मौत की सजा देते हैं, लेकिन यह कहता है कि यह समलैंगिक सेक्स के लिए मौत की सजा को लागू नहीं करेगा।

24. सुधार और सुलह की शुरूआत करने के लिए 2009 में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद श्रीलंका ने पर्याप्त नहीं किया है (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

तमिल आक्रामक के खिलाफ गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद श्रीलंका ने 10 साल पूरे कर लिए हैं।

राजनीतिक समाधान को नजरअंदाज किया

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि देश ने जातीय सुलह, युद्ध-काल की ज्यादतियों के लिए जवाबदेही और संवैधानिक सुधार की दिशा में बहुत ठोस प्रगति हासिल नहीं की है, जिसमें एक राजनीतिक समाधान भी शामिल है। शांति के फल आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार तक सीमित हैं, लेकिन तमिल अल्पसंख्यकों की व्यापक शिकायतें बनी हुई हैं।

स्थानांतरगमन और पुनर्वास में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन कई शिकायतें हैं। कई लोग कहते हैं कि उनकी जमीन सेना के कब्जे में है, जो राज्य के स्वामित्व वाली भूमि के बड़े हिस्से को भी नियंत्रित करती है। एक नए संविधान को बनाने की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए गए थे, लेकिन यह प्रक्रिया एक ठहराव पर है।

श्रीलंका का इतिहास

श्रीलंका में मुख्य रूप से दो जातीय लोग हैं: सिंहली और तमिल। औपनिवेशिक समय के दौरान, तमिलों को श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी भाग में स्थित चाय और अन्य वृक्षारोपण में काम करने के लिए स्थानांतरित किया गया था। तमिलों को श्रीलंका में कई भेदभावों का सामना करना पड़ रहा था। श्रीलंका को स्वतंत्रता के बाद, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। श्रीलंका ने एकात्मक संरचना को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप प्रांतों को शक्तियों की कीमत पर केंद्र सरकार को बड़ी शक्तियां मिलीं। विकास निधि का उपयोग सिंहली क्षेत्रों में भी किया जाता था।

1980 की शुरुआत में,'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम'(LTTE) का गठन किया गया था जो वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में एक तमिल आतंकवादी संगठन था। संगठन तमिल लोगों के लिए श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में तमिल ईलम का एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। लिट्टे ने श्रीलंकाई सेना के शिविरों के साथ-साथ नागरिकों के खिलाफ एक अलग राष्ट्र की मांग के लिए हिंसक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। लिट्टे को 21 वीं सदी के पहले दशक के अंत तक श्रीलंकाई सरकार द्वारा कुचल दिया गया था। हालाँकि, अभी भी तमिलों को अपने स्वयं के कल्याण के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं और वे श्रीलंका में कई भेदभावों के अधीन हैं।

(Source:https://www.thehindu.com/opinion/editorial/ten-years-on/article27179339.ece)

25. जम्मू और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार की प्रतिक्रिया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

जम्मू-कश्मीर में कथित उल्लंघनों पर जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद (HRC) की ओर से दिए गए जवाब पर नाराज़गी जताते हुए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निकाय को सूचित किया है कि वह अब अपनी रिपोर्ट पर HRC के विशेष प्रतिवेदक के साथ कोई संचार नहीं करेगा।

विशेष प्रतिवेदक द्वारा पूछे गए प्रश्न

एक्सट्राजुडिक एक्ज़ीक्यूटिव्स, टॉर्चर, और राइट टू हेल्थ पर वर्तमान विशेष प्रतिवेदक - एग्नेस कैलमार्ड, डायनियस पुरस और निल्स मेल्ज़र - ने मानव आयुक्त के उच्चायुक्त के कार्यालय की एक जून 2018 रिपोर्ट का उल्लेख किया था (OHCHR) और मार्च 2019 में सरकार को लिखा गया, रिपोर्ट में सूचीबद्ध कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए नई दिल्ली द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा गया। इसके अलावा, विशेष प्रतिवेदक ने अकेले 2018 से "चिंता के 13 मामले" सूचीबद्ध किए थे, जिसमें "चार बच्चे सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा मारे गए आठ नागरिकों में से थे।"

सभी दावों को खारिज करते हुए, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन ने ओएचसीएचआर को जवाब दिया कि भारत संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के साथ जुड़ने का इरादा नहीं रखता है।

भारत ने कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर OHCHR की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था - जम्मू और कश्मीर पर पहली बार ऐसी रिपोर्ट जो जून 2018 में सामने आई - और मानवाधिकार के उच्चायुक्त ज़िद रायद अल हुसैन पर "स्पष्ट पूर्वाग्रह" को सामने लाने का आरोप लगाया।

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का क्या कहना है?

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि भारत पहले से ही कई कन्वेंशनों का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें 2011 में हस्ताक्षरित एक "स्टैंडिंग इनविटेशन" शामिल है, जिसमें भारत आने के लिए सभी विशेष प्रतिवेदकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर सहित 20 से अधिक ऐसे यात्रा अनुरोध लंबित हैं।

संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों ने यह भी कहा कि 2016-2018 के बीच, OHCHR स्पेशल प्रतिवेदकों ने 58 संचार भेजे थे, और उन्हें जम्मू-कश्मीर पर 23 अप्रैल के पत्र के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

एनजीओ से रिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तुति जम्मू-कश्मीर स्थित एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसएपर्ड पर्सन्स (एपीडीपी) और जम्मू-कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (जेकेसीसीएस) द्वारा तैयार किए गए 560 पृष्ठों की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करने के साथ हुआ।

रिपोर्ट, यातना: भारतीय राज्य के जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण के साधन, सुरक्षा बलों द्वारा संदिग्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन और क्रूरता के 432 मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिनमें से केवल 27 मामलों की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग ने की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जम्मू और कश्मीर में लगभग 70% यातना पीड़ित नागरिक थे (आतंकवादी नहीं) और यातना के परिणामस्वरूप 11% की मृत्यु हुई। मामलों में बिजली से मृत्यु दंड देना, वाटर-बोर्डिंग 'और यौन उत्पीड़न की घटनाएं शामिल थीं, जिसे सरकार बार-बार नकारती रही है।

26. मोदी शपथ ग्रहण में BIMSTEC नेताओं को आमंत्रित करने के लिए क्यों भारत के पड़ोसियों को महत्वपूर्ण संकेत भेजते हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

मध्य एशिया तक निमंत्रण बढ़ाया गया

30 मई को अपने शपथ ग्रहण समारोह में BIMSTEC (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल पहल की खाड़ी) किर्गिज़ गणराज्य और मॉरीशस देशों के नेताओं को आमंत्रित करके, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सावधानीपूर्वक कूटनीतिक चाल चली है जो बंगाल की खाड़ी से मध्य एशिया के साथ-साथ दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के लिए भारत के पड़ोस के लिए एक आगे बढ़ने का संकेत देती है।

पाकिस्तान को छोड़ा

पिछली बार, मोदी ने सार्क नेताओं को आमंत्रित किया था, और तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उपस्थिति ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नई शुरुआत की उम्मीद जताई थी। इस बार, सार्क के बहिष्करण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को अपने पड़ोसियों के साथ नई दिल्ली से बातचीत से बाहर रखना है।

पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के लिए किसे आमंत्रित किया गया है, और क्यों

किर्गिज गणराज्य के नेता को आमंत्रित करके, भारत शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को आगे बढ़ा रहा है, जिसका नेतृत्व किर्गिज नेता कर रहा है, और जिसके सदस्य चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान हैं। भारत, जो 2017 में पाकिस्तान के साथ एक सदस्य बन गया, वह अपने रणनीतिक उद्देश्यों- आतंकवाद और संयोजकता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सदस्यता का लाभ उठाना चाहता है।

और इस वर्ष जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ, दुनिया में भारतीय मूल के सबसे अच्छे लोगों में से एक है। 2014 के बाद से मोदी ने भारतीय प्रवासियों के लिए राजनयिक पूंजी का निवेश किया है, इस निमंत्रण को एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में देखा जाता है।

हालाँकि, प्रमुख संदेश BIMSTEC तक पहुंचना है, जिसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं।

सार्क से बिम्सटेक तक

जबकि पिछली बार पीएम का सार्क प्रयास पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण बंद करने में विफल रहा था, लेकिन इन समूहों के साथ दिल्ली द्वारा की जाने वाली प्रगति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

BIMSTEC के साथ नई दिल्ली का जुड़ाव सार्क के खत्म होने से बढ़ा। अक्टूबर 2016 में, उरी हमले के बाद, भारत ने उस समूहीकरण के लिए नए सिरे से जोर दिया, जो लगभग दो दशकों से अस्तित्व में था, लेकिन बड़े पैमाने पर इसको उपेक्षित किया गया था। गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ, मोदी ने बिम्सटेक नेताओं के साथ एक आउटरीच शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

सितंबर में, इनमें से कुछ बिम्सटेक देशों ने नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन के बहिष्कार के लिए नई दिल्ली के आह्वान का समर्थन किया था। जैसा कि शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था, भारत ने उरी हमले को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान को अलग-थलग करने में जीत का दावा किया था।

BRICS-BIMSTEC आउटरीच समिट और BIMSTEC नेताओं की वापसी के दो साल बाद, चौथा BIMSTEC शिखर सम्मेलन सितंबर 2018 में काठमांडू में आयोजित किया गया था। नतीजा काफी व्यापक माना जाता था, जो कि नीली अर्थव्यवस्था से लेकर आतंकवाद-रोधी तक फैला हुआ था, हालाँकि यह 21 वर्षों में केवल चौथा शिखर था।

क्षेत्र क्यों मायने रखता है

बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। दुनिया की आबादी का एक-पांचवां (22%) इसके आसपास के सात देशों में रहता है, और उनके पास संयुक्त जीडीपी $ 2.7 बिलियन के करीब है।

खाड़ी में विशाल अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन भी हैं। दुनिया के व्यापार का एक-चौथाई माल हर साल खाड़ी को पार करता है।

क्षेत्र को एकीकृत करने के प्रयास में, समूह का गठन 1997 में किया गया था, मूल रूप से बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ, और बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल थे। बिम्सटेक, जिसमें अब दक्षिण एशिया के पांच देश और आसियान के दो देश शामिल हैं, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल है। इसमें मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख देश शामिल हैं।

थाईलैंड में फुकेत इंदिरा पॉइंट से केवल 273 समुद्री मील की दूरी पर है, जो चेन्नई और मदुरई के बीच की दूरी से कम है।

भारत की हिस्सेदारी

1. BIMSTEC के साथ एसोसिएशन भारत के भूमिबद्ध उत्तर पूर्व के लिए समुद्र और भूमि कनेक्टिविटी दे सकता है।

2. सामरिक दृष्टिकोण से, बंगाल की खाड़ी, मलक्का जलडमरूमध्य के लिए कीप, हिंद महासागर तक अपनी पहुंच कायम रखने के लिए एक तेजी से मुखर चीन के लिए एक प्रमुख थिएटर उभरा है।

बीजिंग ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्सटेक देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बुनियादी ढांचे को वित्त और विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है।

(Source-https://indianexpress.com/article/explained/modi-swearing-in-invite-bimstec-leaders-sends-important-signals-indias-neighbours-5751380/)

27. श्रीलंका, जापान, भारत ने कोलंबो बंदरगाह में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

श्रीलंका, जापान और भारत ने संयुक्त रूप से कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त पहल की लागत $ 500 मिलियन और $ 700 मिलियन के बीच अनुमानित है। श्रीलंका परियोजना में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगा और संयुक्त उद्यम के साझेदार 49% को बनाए रखेंगे।

परियोजना प्रकृति में रणनीतिक क्यों है?

ईसीटी चीन समर्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय शहर से लगभग 3 किमी दूर स्थित है, जिसे "बंदरगाह शहर" के रूप में जाना जाता है, जो कोलंबो के समुद्री मोर्चे पर पुनर्निर्मित भूमि पर बनाया जा रहा है। जापान में 0.1 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 40 साल का सॉफ्ट लोन देने की संभावना है।

पहल के लिए भारत के योगदान का विवरण प्रतीक्षित है, लेकिन नई दिल्ली की इस परियोजना में भागीदारी के लिए रुचि जगजाहिर है। रणनीतिक रूप से स्थित ईसीटी में 70 प्रतिशत से अधिक ट्रांसशिपमेंट कारोबार भारत से जुड़ा हुआ है।

श्रीलंका में आंतरिक विरोध

टर्मिनल के विकास में भारत की संभावित भूमिका का सरकार के कुछ वर्गों ने विरोध किया था। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने परियोजना में किसी भी भारतीय की भागीदारी का विरोध किया था, क्योंकि "राष्ट्रीय संपत्ति" विकसित करने के लिए विदेशी अभिनेताओं में खींचा तानी राजनीतिक रूप से जारी है। राष्ट्रपति श्री सिरिसेना और प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अक्टूबर 2018 में एक कैबिनेट बैठक के दौरान इस मामले पर एक गर्म तर्क दिया था, स्पष्ट रूप से भारतीय भागीदारी की अनुमति देने की ओर पीएम का झुकाव अधिक है।

(Source:https://www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-japan-india-sign-deal-to-develop-east-container-terminal-at-colombo-port/article27273794.ece)

28. प्रतिस्पर्धा में भारत 43 वें स्थान पर है; सिंगापुर टॉप पर है (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

वास्तविक जीडीपी में वृद्धि की मजबूत दर, व्यापार कानून में सुधार और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण भारत की रैंकिंग में पिछले एक साल में 43वें स्थान पर एक स्थान से सुधार हुआ है। 2017 में भारत 45 वें स्थान पर था, लेकिन 2016 में 41 वें स्थान पर था।

2019 रैंकिंग में, भारत ने कई आर्थिक मापदंडों और कर नीतियों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सार्वजनिक वित्त, सामाजिक ढांचे, शिक्षा के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मामले में पिछड़ गया है। शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए सिंगापुर ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। सिंगापुर पिछले साल तीसरे स्थान पर था। हांगकांग अपने दूसरे स्थान पर बना हुआ है।

रैंकिंग के बारे में

IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, 1989 में स्थापित, प्रतिस्पर्धी वातावरण को बढ़ावा देने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए 63 रैंक अर्थव्यवस्थाओं में से प्रत्येक से 235 संकेतक शामिल करती है।

अर्थशास्त्री प्रतिस्पर्धा को देश की अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह स्थायी विकास प्राप्त करने के लिए व्यवसायों को सशक्त बनाता है, रोजगार उत्पन्न करता है और अंततः नागरिकों के कल्याण को बढ़ाता है।

आईएमडी बिजनेस स्कूल ने कहा कि यह स्वास्थ्य और शिक्षा पर बेरोजगारी, जीडीपी और सरकार के खर्च के साथ-साथ सामाजिक सामंजस्य, वैश्वीकरण और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को कवर करने वाले एक कार्यकारी राय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर ध्यान देता है।

आईएमडी के अध्ययन में कहा गया है कि भारत के समक्ष चुनौतियां रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट बैंडविड्थ, राजकोषीय अनुशासन के प्रबंधन के साथ-साथ माल और सेवा कर के कार्यान्वयन और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने से संबंधित मुद्दे हैं।

(Source:https://www.thequint.com/pti/india-moves-up-to-rank-43-in-competitiveness-singapore-tops-chart)

29. आज के शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान, पीएम मोदी की आउटरीच को दर्शाता है)Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

"पड़ोसी पहले फोकस "

जब वह पांच साल पहले प्रधान मंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी ने सार्क नेताओं को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। जब वह कार्यालय में पुनप्रवेश करते हैं :, तो समारोह में बिम्सटेक देशों, किर्गिज गणराज्य और मॉरीशस के नेताओं द्वारा भाग लिया जाएगा।

बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, और भूटान के नेताओं को आमंत्रित बंगाल की - "पड़ोसी पहले" मोदी के - क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए पहल-खाड़ी में देश बहु फोकस का हिस्सा है। किर्गिज़ गणराज्य वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष (एससीओ) है; मॉरीशस के प्रधान मंत्री इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे।

2014 के बाद सार्क देशों को पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण उतारने में विफल; यह कूटनीतिक रूप से पड़ोस, प्रवासी भारतीयों और मध्य एशियाई देशों के चीनरूस के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय समूह - तक पहुंचने के लिए पीएम का नया प्रयास है।

महत्वपूर्ण मेहमान

1. बांग्लादेश के राष्ट्रपति हामिद प्रधान मंत्री शेख हसीना का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो जापान की यात्रा कर रहे हैं।

2. राष्ट्रपति सिरिसेना, जो 2015 से श्रीलंका के पद पर हैं।

3. राष्ट्रपति विन माइंट राज्य काउंसलर आंग सान सू की के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जिन्हें संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति बनने से रोक दिया गया है। वह सू की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो यूरोप की यात्रा कर रही हैं।

4. किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जेनबकोव, वह शपथ ग्रहण में भाग ले रहे हैं क्योंकि किर्गिज़ गणराज्य एससीओ के अध्यक्ष हैं।

5. प्रधान मंत्री ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 तक पहले पीएम थे। कुख्यात नेपाल नाकाबंदी के दौरान भारत के साथ उसके संबंधों में खटास आई, लेकिन 2018 में सत्ता में लौटने के बाद से संबंधों में सुधार हुआ है।

6. मॉरीशस के प्रधान मंत्री जुगनुथ, वह पूर्व पीएम सर अनिरुद्ध जुगानथ के पुत्र हैं, और इस वर्ष जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे।

7. ग्रिसडा बूनराच थाईलैंड के प्रधान मंत्री प्रथुथ चानचा के भरोसेमंद है। मंत्री बूनराच प्रधान -ओ-मंत्री की ओर से भाग ले रहे हैं, जो थाईलैंड में सरकार के गठन में व्यस्त है।

Source:https://indianexpress.com/article/explained/guests-at-todays-swearing-in-what-the-pm-narendra-modis-outreach-signifies-5755425/)

Geography

1. Why cyclones in India hit the east coast - क्यों अधिकांश तूफान बंगाल, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु को करते हैं तबाह? जानें वजह (Relevant for GS Prelims & Mains Paper I; Geography)

तूफान फानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के करीब पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि यह तूफान तीव्र हो सकता है और ज्यादा तबाही मचा सकता है। पिछले साल भी तूफान गाजा ने तमिलनाडु के तटों पर तबाही मचाई थी। 20 लोगों ने जान गवां दी थी और काफी नुकसान भी हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर ही ज्यादातर तूफान क्यों आते हैं और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल आदि को अधिक प्रभावित करते हैं।

साइक्लोन या चक्रवात क्या है

साइक्लोन पश्चिमी प्रशांत महासागर और भारत के पास बंगाल के आसपास उठने वाला चक्रवाती तूफान हैं। साइक्लोन समंदर में उस जगह से उठता है जहां पर तापमान अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा होता है। उत्तरी ध्रुव के नजदीक वाले इलाकों में साइक्लोन घड़ी चलने की उल्टी दिशा में आगे बढ़ता है। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के आस-पास साइक्लोन घड़ी चलने की दिशा में आगे बढ़ता है।

बंगाल की खाड़ी में ज्यादा आते हैं चक्रवात

इतिहास के 35 सबसे घातक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में से 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। इन तूफानों से बांग्लादेश में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 200 साल में दुनिया भर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से दुनिया भर में हुई कुल मौत में से 40 फीसदी सिर्फ बांग्लादेश में हुई है। जबकि भारत में एक चौथाई जानें गई हैं।

ओडिशा सबसे ज्यादा प्रभावित

1891 से 2002 के बीच ओडिशा में 98 तूफान आए। हालांकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मौत हुई हैं।

ठंडा है पश्चिम तट

बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा तूफान आते हैं। इसका कारण हवा का बहाव है। इससे पश्चिमी ओर का सागर ठंडा रहता है। ठंडे सागर में कम तूफान आते हैं। वहीं पश्चिमी तट पर बनने वाले ज्यादातर तूफान भी ओमान की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए यह भारतीय तटों की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। नेशनल साइक्लॉन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक साल 1891 से 2000 के बीच भारत के पूर्वी तट पर 308 तूफान आए। इसी दौरान पश्चिमी तट पर सिर्फ 48 तूफान आए।

पूर्वी तट के तूफान ज्यादा ताकतवर और ऊंची लहरें

पूर्वी तट पर बने तूफान ज्यादा ताकतवर होते हैं। वहीं पूर्वी तटों से लगने वाले राज्यों की भूमि भी ज्यादा समतल है, इसलिए यह तूफानों को मोड़ भी नहीं पाती है। जबकि पश्चिमी तट के तूफान मुड़ जाते हैं। जब एक विशेष तीव्रता का तूफान भारत के पूर्वी तट और बांग्लादेश से टकराता है तो इससे जो लहरें उठती हैं वो दुनिया में किसी भी हिस्से में तूफ़ान की वजह से उठने वाली लहरों के मुकाबले ऊंची होती हैं। इसके पीछे वजह है तटों की खास प्रकृति और समुद्र का छिछला तल।

अप्रैल से बढ़ती तूफानों की संख्या

अप्रैल से दिसंबर तक तूफानों का मौसम होता है। लेकिन 65 फीसदी तूफान साल के अंतिम चार माह सितंबर से दिसंबर के बीच आते हैं।

हवा की रफ्तार से तय होते हैं तूफान के प्रकार

तूफान का वर्गीकरण कम दबाव के क्षेत्र में हवा की रफ्तार से होता है। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान को उष्म कटिबंधीय तूफान कहते हैं। यह तीव्र तूफान में बदल जाता है अगर हवा की रफ्तार 89 से 118 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तूफान बेहद तीव्र हो जाता है अगर हवा 119 से 221 के बीच होती है। इससे तेज रफ्तार वाले तूफान सुपर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं।

(Adapted from Bhaskar.com)

2. Cyclone Fani को लेकर ताजा अलर्ट, 'तितली' से ज्यादा बरपा सकता है कहर, तीनों सेनाएं मुस्तैद (Relevant for GS Prelims; Geography)

Cyclone Fani भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'फेनी' बुधवार तक बेहद खतरनाक रूप ले सकता है। यह 175-185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। इसके संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियानों के लिए अपने जहाज और हेलिकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। भारतीय नौसेना हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ ने भी राहत और बचाव कार्य के लिए अपनी 41 टीमें तैनात की हैं।

केंद्र की एडवाइजरी, ले सकता है खतरनाक रूप

गृह मंत्रालय के नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर (एनइआरसी) की तरफ से ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश सहित तीन केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान-निकोबार, पुडूचेरी एवं लक्ष्यद्वीप के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक मंगलवार की सुबह तक इसके बेहद खतरनाक साइक्लोनिक स्टर्म का रूप लेने का अनुमान किया गया है। एक मई शाम तक यह उत्तर-पश्चिम की तरफ गति कर सकता है। इसके बाद उत्तर पूर्व की दिशा में गति करते हुए ओडिशा की तरफ बढ़ने का अनुमान है।

सेना और वायु सेना इकाइयां स्टैंड बाई पर

ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सेना और वायु सेना की इकाइयों को स्टैंड बाई पोजीशन पर रखा गया है। मौसम विज्ञान विभाग, भुवनेश्वर के निदेशक एचआर विश्वास ने बताया कि यह तूफान ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से होते हुए पश्चिम बंगाल का रुख करेगा। उन्होंने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। इसके साथ ही ट्रेन सेवाओं को निलंबित रखने या उनके मार्गों में बदलाव के सुझाव भी दिए हैं। विभाग की ओर से मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

तीन तक ओडिशा तट से टकराने का अनुमान

अनुमान है कि चक्रवाती तूफान फेनी तीन मई तक ओडिशा तट से टकरा सकता है। ऐसे में तटीय जिलों के जिलाधीशों को सतर्क रहने को कहा गया है। ओड्राफ, एनडीआरएफ तथा दमकल वाहिनी कर्मचारियों को पहले ही वहां पर भेज दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि तूफान के कारण भद्रक और बालेश्वर के बीच तट पर भूस्खलन की आशंका है। पुरी में सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद कर दी गई हैं। साथ ही सूखे खाद्य पदार्थ, पेयजल, दवा, पशु खाद्य की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

केरल, आंध, तमिलनाडु और ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने इस तूफान के कारण केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। नौसेना ने तंबू, कपड़े, दवाइयां, कंबल, भोजन सामग्री, रबड की नाव, डाक्टर्स और अतिरिक्त गौताखोरों को तैयार रखा है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एहतियाती कदम उठाने और राहत कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए 10 हजार 86 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

नौसेना के विमान तैनात

नौसेना के मुताबिक, उसके विमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्टेशनों में तैनात हैं। आपात स्थिति में इनसे मुसीबत में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 1 मई से 3 मई तक बंगाल की खाड़ी से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर तेज हवाएं चलेंगी। खतरनाक रूप लेते जा रहे इस तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर चिंता जताई है और अधिकारियों को सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं।

'तितली' से भी अधिक हो सकता है खतरनाक

चक्रवात फेनी का प्रभाव चक्रवाती तूफान 'तितली' से भी अधिक हो सकता है। इसे लेकर क्षेत्रीय मौसम विभाग, भुवनेश्वर की तरफ से मंगलवार को सूचना जारी की गई है। क्षेत्रीय निदेशक एचआर विश्वास ने बताया कि चक्रवाती तूफान फेनी मंगलवार की सुबह सीवीयर साइक्लोन वेरी का रूप धारण कर चुका है। तटीय ओडिशा के सभी जिलों में दो मई से बारिश शुरू हो जाएगी। तीन व चार को तटीय ओडिशा के सभी जिलों में बारिश होगी। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। बंदरगाहों में दो नंबर खतरे का निशान लगा दिया गया है।

3. Naming of tropical cyclones - बांग्लादेश ने चक्रवाती तूफान को फैनी नाम दिया, अगले साइक्लोन का नाम वायु होगा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper I; Geography)

ओडिशा समेत देश के चार राज्यों में दो दिन तक चक्रवाती तूफान फैनी का असर रहेगा। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में 2014 में हुदहुद, 2017 में ओकी, फिर तितली और 2018 में गजा तूफान आए। फैनी के बाद अगला चक्रवाती तूफान जब भी आएगा उसका नाम वायु होगा। आमतौर पर यह जिज्ञासा रहती है कि इन तूफानों के नाम कैसे और किस आधार पर रखे जाते हैं। विश्व में अब जितने तूफान आते हैं उन सभी को एक नाम दिया जाता है।

2004 से शुरू हुआ नाम देने का सिलसिला

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 15 साल पहले यानी 2004 में शुरू हुआ। इसके लिए एक सूची बनाई गई। इस सूची में आठ देश शामिल हैं। आठ देशों को क्रमानुसार आठ नाम देने हैं। जब जिस देश का नंबर आता है तो उस देश की सूची में दिए गए नाम के आधार पर उस तूफान का नामकरण कर दिया जाता है। फैनी नाम बांग्लादेश ने दिया है।

8 देशों ने 64 नाम दिए

तूफानों के नाम आठ देशाेंं ने दिए हैं। इनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। हर देश ने आठ नाम दिए हैं। इस तरह कुल 64 नाम तय किए गए हैं।

सबसे पहले 'ओनिल'

2004 में जब तूफानों को नाम देने की परंपरा शुरू हुई तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बांग्लादेश को ये मौका मिला। उसने पहले तूफान को ओनिल नाम दिया। इसके बाद जो भी तूफान आए, उनके नाम निर्धारित क्रमानुसार तय किए गए। क्रम निर्धारण 8×8 की एक टेबल से किया जाता है। जब ये नाम क्रमानुसार समाप्त हो जाएंगे तो फिर एकबार इन्हें ऊपर से शुरू किया जाएगा। अब तक इस टेबल की सात पंक्तियां पूर्ण हो चुकी हैं। फैनी आठवें कॉलम का पहला नाम है। इसके बाद भारत की तरफ से नाम दिया जाएगा। ये होगा वायु। इस लिस्ट में आखिरी नाम होगा अम्फान और ये थाईलैंड का दिया हुआ है।

नामकरण इसलिए ताकि पहचान और सतर्कता रहे

एक सवाल लाजिमी है कि तूफानों को आखिर नाम देने की जरूरत क्या है? दरअसल, इसकी कुछ वजहें मानी जाती है। जैसे, इससे मीडिया को रिपोर्ट करने में आसानी होती है। नाम की वजह से लोग चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और आपदा से निपटने की तैयारी में भी मदद मिलती है। आम जनता भी ये नाम संबंधित विभागों के जरिए सुझा सकती है। इसके लिए नियम हैं। दो शर्तें प्राथमिक हैं। पहली- नाम छोटा और सरल हो। दूसरी- जब इनका प्रचार किया जाए तो लोग समझ सकें। एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि सांस्कृतिक रूप से नाम संवेदनशील न हों और न ही उनका अर्थ भड़काऊ हो।

4. माउंट एवरेस्ट: त्रासदी से सीखें, सुरक्षा उपायों को कड़ा करें (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Geography)

माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊँची चोटी 8,848 मीटर पर, सभी साहसी लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन नेपाल-चीन सीमा पर स्थित पहाड़ तेजी से कठोर पर्वतारोही के लिए भी खतरनाक जगह बनते जा रहे हैं।

एवरेस्ट पर चढ़ने का खतरा

इस महीने के निहित जोखिम, गोरखा पूर्व सैनिक, निर्मल पुरजा द्वारा एक तस्वीर के साथ उजागर किए गए थे। छवि, जो वायरल हो गई और जिस तरह से दुनिया भर में लोगों ने कल्पना की कि वह माउंट एवरेस्ट को स्केल करने के लिए है, एवरेस्ट पर चढ़ने की प्रतीक्षा में एक लंबी कतार दिखाई दी, ऐसे सभी खतरों के साथ एक प्रतीक्षा की जाती है। इस सीजन में, चार भारतीयों सहित कम से कम 10 पर्वतारोही मारे गए हैं या लापता हो गए हैं।

आगंतुकों की संख्या

विशेषज्ञ परमिट की संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए नेपाल को कह रहे हैं। इसने इस वसंत के लिए रिकॉर्ड 381 तक किया, प्रतीक यात्री से 11,000 डॉलर प्राप्त किए जाते हैं (तिब्बत की ओर से चढ़ना और अधिक महंगा है)। बुधवार को, 200 पर्वतारोहियों ने शिखर पर चढ़कर, एक ही दिन के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल, 807 शिखर पर पहुंचने में कामयाब रहे। 2012 में, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि एवरेस्ट क्षेत्र में 26,000 से अधिक आगंतुक थे, और तब से यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है।

चढ़ने में जोखिम

नेपाल के अधिकारियों का तर्क है कि परमिट लापरवाही से जारी नहीं किए जाते हैं, और इस वर्ष के समीप जैसे जाम खराब मौसम के के कारण होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्वतारोहियों को संकीर्ण समय-सीमा के भीतर शिखर सम्मेलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। दुर्लभ ऊंचाई पर उप-शून्य तापमान में इंतजार करना घातक हो सकता है - इस मौसम में होने वाली मौतें ज्यादातर शीतदंश, थकावट, निर्जलीकरण और ऑक्सीजन की कमी के कारण होती हैं।

Economics

1. Recognised investors to get exemption from Angel tax-मान्यता प्राप्त निवेशकों को एंजल टैक्स से छूट देने की तैयारी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

स्टार्ट-अप कंपनियों को एंजल टैक्स के बोझ से मुक्ति देने के लिए सरकार ने नया रास्ता निकाला है। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार मान्यताप्राप्त निवेशकों को एंजल टैक्स से छूट देने पर विचार कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह छूट हासिल करने के लिए निवेशकों को एक निश्चित नेटवर्थ के मानक का पालन करना पड़ सकता है। 'मान्यताप्राप्त निवेशकों' को परिभाषित करने का एक मकसद यह भी है कि स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

अधिकारी के मुताबिक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) मान्यताप्राप्त निवेशकों की परिभाषा तय करने पर काम कर रहा है। यह परिभाषा तय हो जाने के बाद उसे अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा, 'मान्यताप्राप्त या अच्छे निवेशक कितनी भी रकम का निवेश कर सकते हैं। लेकिन हमें एक मानदंड बनाना ही होगा। नियमों को इतना खुला होना ही चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित कर सके। लेकिन उसे बहुत ज्यादा खुला या बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए।'

विभाग के मुताबिक मान्यताप्राप्त या सही निवेशकों को एक वर्ष में कितनी रकम के निवेश की इजाजत दी जानी चाहिए, यह इस पर निर्भर करेगा कि उनकी कुल संपत्ति कितनी है। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्ष में दो करोड़ रुपये का निवेश करते हैं, तो आपकी कुल संपत्ति उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। निवेशकों की कुल संपत्ति और निवेश की राशि में तारतम्यता होनी चाहिए। ऐसे निवेशकों में ट्रस्ट, व्यक्ति या पारिवारिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। शर्तें पूरी करने वाले ऐसे निवेशकों को 25 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश पर भी एंजल टैक्स से छूट दी जाएगी। वर्तमान में स्टार्ट-अप कंपनियों को सालाना 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल टैक्स से छूट मिली हुई है।

वर्तमान में हर साल 300-400 स्टार्ट-अप कंपनियों में एंजल निवेश हो रहा है। एंजल निवेशकों द्वारा लगाई निवेश की रकम 15 लाख रुपये से चार करोड़ रुपये तक होती है। विभाग स्टार्ट-अप कंपनियों में कैटेगरी-1 और कैटेगरी-2 के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआइएफ) को भी टैक्स बोझ से मुक्त रखने पर विचार कर रहा है।

2. NSE fined for co-location case- सेबी ने एनएसई को ब्याज सहित 687 करोड़ रु. जमा करने का आदेश दिया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने को-लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को 687 करोड़ रुपए का जुर्माना ब्याज सहित विशेष फंड में जमा कराने का आदेश दिया है। एनएसई के दो पूर्व-सीईओ रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण को एक अवधि विशेष के दौरान प्राप्त सैलरी के 25% हिस्सा जमा कराने को कहा है। साथ ही इन दोनों पर किसी लिस्टेड कंपनी या मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआईआई) या मार्केट इंटरमीडियरी के साथ काम करने पर पांच साल की रोक लगाई है। ये दोनों छह माह तक सिक्यूरिटी मार्केट में कारोबार भी नहीं कर पाएंगे।

को-लोकेशन के कारण एक्सचेंज सर्वर तक जल्द पहुंचते थे ब्रोकर

को-लोकेशन का मतलब एक्सचेंज परिसर में ब्रोकरों द्वारा सर्वर लगाने से है। इससे नजदीकी ब्रोकरों को दूर के ब्रोकरों के मुकाबले एक्सचेंज के सर्वर तक जल्द पहुंच मिल जाती है। सेबी एनएसई पर चुनिंदा ब्रोकरों को यह लाभ पहुंचाने के आरोपों की जांच कर रहा था। नियामक ने जांच में पाया कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ।

(Adapted from Bhaskar.com)

3. Pepsico withdrew case on Gujarat farmers- पेप्सिको गुजरात के 4 किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेगी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

आलू की रजिस्टर्ड किस्म से जुड़े विवाद में पेप्सिको गुजरात के 4 किसानों पर दर्ज केस वापस लेगी। कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पेप्सीको ने बताया कि सरकार से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। कंपनी ने अप्रैल में किसानों पर मुकदमा किया था।

क्या है विवाद?

पेप्सिको का दावा है कि किसानों ने एफसी5 वैरायटी के आलू उगाए। यह किस्म कंपनी ने 2016 से रजिस्टर्ड करवा रखी है। इसे वह अपने लेज ब्रांड के चिप्स बनाने में इस्तेमाल करती है।

4. स्टार्ट-अप्स को मदद के लिए टैक्स नियमों में ढील की तैयारी, आयकर कानून में बदलाव की तैयारी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

स्टार्ट-अप कंपनियों को फंड जुटाने में हो रही दिक्कतों के निदान के लिए सरकार ने आयकर कानून में ढील देने की तैयारी की है। इसके तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने एक प्रस्ताव रखा है कि रिहाइशी संपत्तियों की बिक्री के अलावा किसी वित्त वर्ष के घाटे को उससे अगले वित्त वर्ष में समायोजित करने से जुड़े आयकर नियमों में ढील दी जा सकती है।

ये सुझाव डीपीआइआइटी द्वारा तैयार 'स्टार्ट-अप विजन 2024' दस्तावेज का हिस्सा हैं। पूंजी जुटाने में मुश्किलों का सामना कर रही स्टार्ट-अप कंपनियों की दिक्कतें दूर करने के मकसद से डीपीआइआइटी ने नई सरकार के लिए यह विजन दस्तावेज तैयार किया है।

डीपीआइआइटी ने आयकर कानून की धारा 54जीबी में ढील देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत रिहाइशी संपत्तियों की बिक्री के चुनिंदा मामलों में कैपिटल गेन टैक्स से छूट दी जा सकती है। डीपीआइआइटी ने आयकर कानून की धारा 79 में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके माध्यम से चुनिंदा कंपनियों के मामले में नुकसान को अगले वित्त वर्ष में समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक स्टार्ट-अप कंपनियों को नुकसान अगले वित्त वर्ष में समायोजित करने के लिए इस वक्त 100 फीसद हिस्सेदारी उनके ही पास रहने की शर्त है। इसे घटाकर 26 फीसद किया जा सकता है, ताकि स्टार्ट-अप कंपनियों को नए निवेशक मिलें।

5. कारगर नहीं है NOTA का मौजूदा प्रारूप, चुनाव प्रणाली में बदलाव की है जरूरत (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

चुनावी माहौल गरम है। एक-एक वोट के लिए घोर संघर्ष जारी है। ऐसे में कुछ स्थानों से मतदान के बहिष्कार की खबरें जन और तंत्र दोनों को आकुल करती हैं। एक विचार यह भी है कि बहिष्कार करना लोकतांत्रिक नहीं है क्योंकि इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग हो जाना माना जाता है। इससे अच्छा है नोटा (नन ऑफ़ दी अबव)। अर्थात मत किसी भी उम्मीदवार को नहीं दिया जाए। कुछ लोगों के विचार में नोटा को वोट देना अपने वोट को निरर्थक या बेकार करना है। इसकी असलियत क्या है?

ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर नोटा नाम का बटन लगाने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के 23 सितंबर 2013 के एक निर्देश पर किया गया है। दलील यह थी कि नोटा का बटन होने से ऐसे मतदाता के मत की गोपनीयता बनी रहेगी जो किसी भी उम्मीदवार के हक में वोट नहीं देना चाहता, और ना ही वोट देने से अनुपस्थित रहना चाहता। न्यायालय ने इस दलील को तो माना ही पर अपने निर्णय में और भी कुछ लिखा। उस पर हम बाद में आएंगे। चुनाव आयोग ने ईवीएम पर नोटा नाम का एक बटन लगा दिया लेकिन और कोई भी बदलाव नहीं किया।

इसका परिणाम ये हुआ कि नोटा के हित में जो वोट पड़े, उनको गिना तो गया पर उनका चुनाव के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे कहने को तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कर दिया गया पर असल में फैसले की जो भावना थी, उसका पालन नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की भावना को दो वाक्यों में साफ जाहिर की थी। 'इस प्रकार, एक जोशीले लोकतंत्र में, मतदाता को नोटा चुनने का मौका दिया जाना चाहिए ..., जो कि ... राजनीतिक दलों को मजबूर करेगा कि वे अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दें।

जब राजनीतिक दलों को अहसास होगा कि बड़ी संख्या में लोग उम्मीदवारों के साथ अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम में बदलाव होगा और राजनीतिक दल लोगों की इच्छा को मानने के लिए मजबूर हो जायेंगे कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएं, जो ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते है।'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भावनानुसार लागू करने के लिए प्रावधान होना चाहिए था कि अगर नोटा को सबसे अधिक वोट मिले (सब उम्मीदवारों से अधिक), हो वह चुनाव रद्द हो जाना चाहिए, और इसके बाद एक नया चुनाव होना चाहिए जिसमें उन उम्मीदवारों को खड़े होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। केवल यही तरीका है जिससे राजनीतिक दल बेहतर और अच्छी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफशब्दों में लिखा, 'केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह करने के बजाय केवल ईवीएम में नोटा नाम का एक बटन लगा दिया और कुछ नहीं किया। इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना ताक पर रख दी गई।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूर्णतया लागू करने में दो राज्य चुनाव आयोगों ने बहुत ही सराहनीय पहल की है। 13 जून 2018 को महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें लिखा था कि अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे अधिक वोट मिलेंगे, तो वह चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। उसकी जगह नया चुनाव कराया जायेगा। यह प्रावधान हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग से तो कहीं बेहतर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं करता।

इसकी भरपाई हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने की। उनकी अधिसूचना 22 नवंबर 2018 को जारी हुई। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, तो वह चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जगह नया चुनाव कराया जायेगा जिसमें पहले वाले उम्मीदवार खड़े नहीं हो सकेंगे।

राज्य चुनाव आयोग केवल पंचायत और नगर निगमों के चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। विधान सभाओं, संसद, राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की है। आशा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग इन दो राज्य चुनाव आयोगों का अनुसरण करेगा और नोटा को कारगर बनाएगा।

(Adapted from Jagran.com)

6. रियल एस्टेट में निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदना जरूरी नहीं, REIT के जरिए भी लगा सकते हैं पैसे (Relevant for GS Prelims & GS Mains Paper III; Economics)

आम तौर पर लोग रेंटल इनकम या भविष्य में प्रॉपर्टी की कीमतों में होने वाले इजाफे को देखते हुए निवेश करते हैं। हालांकि, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) के जरिए बिना भौतिक रूप से प्रॉपर्टी में निवेश किए उसका फायदा उठाया जा सकता है।

क्या होता है REIT?

REIT म्युचुअल फंडों के जैसे ही होते हैं जहां निवेशक किसी अंतर्निहित प्रतिभूति के रूप में रियल एस्टेंट में निवेश करते हैं। मतलब REIT आपके द्वारा जुटाए गए पैसों का निवेश ऐसी प्रॉपर्टीज में करते हैं जहां मुनाफे या रेंटल इनकम की संभावना सबसे अधिक होती है। हालांकि, कुछ मामलों में यह म्युचुअल फंडों से भिन्न भी होता है।

वास्तव में REIT एक ट्रस्ट है जो स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के जरिए रियल एस्टेट में पैसे लगाता है। REIT में तीन इकाइयां शामिल होती हैं- स्पॉन्सर, मैनेजर और ट्रस्टीज।

REIT में निवेश के फायदे

REIT के जरिए देश की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है। भारत में REIT को सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में ही निवेश की अनुमति मिली हुई है। इसलिए एक निवेशक के तौर पर देश के विभिन्न SEZ, ऑफिस, मॉल आदि में निवेश किया जा सकता है।

कैसे करें RIET में निवेश?

REIT में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। हाल ही में एंबेसी REIT का आईपीओ आया था जिसमें निवेश की न्यूनतम रकम 2.4 लाख रुपये तय की गई थी। हालांकि, बाजार नियामक सेबी ने REIT में निवेश की न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दिया था।

किन निवेशकों को करना चाहिए REIT में निवेश:

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे निवेशक जो कम से कम 3 से 5 साल की समयसीमा लेकर चल रहे हैं उन्हें REIT में निवेश पर विचार करना चाहिए। रेंटल इनकम बढ़ने के साथ ही उनके रिटर्न में भी इजाफा होता रहेगा।

(Adapted from jagran.com)

7. सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत, विदेश जाने की मिली अनुमति (Relevant for GS Prelims and GS Mains Paper III; Economics)

आइएनएक्स मामले में कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च अदालत ने कार्ति चिदंबरम को मई और जून में अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जाने की इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही ये आदेश भी दिया है कि इसके लिए कार्ति को 10 करोड़ की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति द्वारा विदेश जाने की अनुरोध पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि ये ऐसा मामले नहीं है कि इसके लिए तुरंत सुनवाई की जाए। वहीं सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने एयसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी पर अंतरिम छूट की अवधि .30 मई तक के लिए बढ़ा दी है। गौरतलब है कि सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा जिसके बाद यह अनुरोध किया।

क्या है एयरसेल मैक्सिस केस?

साल 2006 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से जुड़ा एयरसेल मैक्सिस केस सामने आया। पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री इस डील को मंजूरी दी थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास महज 600 करोड़ रूपये तक के ही प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को मंजूरी देने का अधिकार था। उन्हें इससे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट समिति से मंजूरी लेना जरूरी था। एयरसेल मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी का था। इसके बाद भी चिदंबरम ने इस डील को कैबिनेट की मंजूरी के बिना पास कर दिया। इस मामले में इडी द्वारा दायर चार्जशीट में पी चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा कुल 18 आरोपी हैं।

SOURCE: https://www.jagran.com/

8. अनिल अंबानी की आरकॉम पर दिवालिया कार्रवाई शुरू, कंपनी पर 50 हजार करोड़ रुका . कर्ज (Relevant for GS Prelims and GS Mains Paper III; Economics)

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस पर दिवालिया कार्रवाई शुरू हुई। नया (आरकॉम) बनाने के (सीओसी) नियुक्त करने और क्रेडिटर्स की कमेटी (आरपी) रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल लिए आरकॉम के कर्जदाता नेशनलकंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पहुंचे। यह किसी कंपनी के (एनसीएलटी) खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहला कदम होता है।

आरकॉम ने 2 साल पहले बंद कर दिए थे ऑपरेशंस

1. आरकॉम ने पिछले साल दिवालिया प्रक्रिया पर स्टे लिया था लेकिन असेट्स की बिक्री में विफल रहने पर इस साल फरवरी में खुद ही दिवालिया प्रक्रिया में जाने का फैसला लिया था। कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि यह कदम सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा। इससे 270 दिन की तय अवधि में आरकॉम की संपत्ति बेचकर कर्ज के भुगतान की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। पिछले दिनों आरकॉम ने अपीलेट ट्रिब्यूनल से स्टे की अपील वापस ले ली थी।

2. कारोबार में घाटा होने और कर्ज बढ़ने की वजह से आरकॉम ने 2 साल पहले ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। उसने रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचकर दिवालिया होने से बचने की कोशिश की लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और सरकार की ओर से मंजूरी में देरी की वजह से डील नहीं हो पाई।

3. इस साल मार्च में आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी ने बड़े भाई की मदद से एरिक्सन के 480 करोड़ रुपए चुकाए और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचे, नहीं तो अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ता। एरिक्सन ही पिछले साल आरकॉम के खिलाफ एनसीएलटी गई थी।

4. एरिक्सन से पहले चाइना डेवलपमेंट बैंक ने भी दिवालिया अदालत का दरवाजा (एनसीएलटी) खटखटाया था। आरकॉम ने उससे1 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। बाद में आरकॉम ने मुंबई स्थित अपने मुख्यालय का एक हिस्सा देकर सेटलमेंट किया।

5. पिछले हफ्ते एसबीआई ने आरकॉम पर दिवालिया प्रक्रिया के लिए आरपी शॉर्टलिस्ट करने के लिए मीटिंग रखी। अप्रैल में इसका प्रस्ताव पेश किया था।

आरकॉम के क्रेडिटर्स की कमेटी को 66 फीसदी वोटों के साथ नए आरपी के लिए मंजूरी देनी होगी। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने मौजूदा आरपी को 30 मई तक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। उसी दिन मामले की सुनवाई होगी।

SOURCE: https://www.bhaskar.com/

9. अनिल अंबानी की आरकॉम पर दिवालिया कार्रवाई शुरू, कंपनी पर 50 हजार करोड़ रु. का कर्ज (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) पर मंगलवार को दिवालिया कार्रवाई शुरू हुई। नया रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) नियुक्त करने और क्रेडिटर्स की कमेटी (सीओसी) बनाने के लिए आरकॉम के कर्जदाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) पहुंचे। यह किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहला कदम होता है।

आरकॉम ने 2 साल पहले बंद कर दिए थे ऑपरेशंस

1. आरकॉम ने पिछले साल दिवालिया प्रक्रिया पर स्टे लिया था लेकिन असेट्स की बिक्री में विफल रहने पर इस साल फरवरी में खुद ही दिवालिया प्रक्रिया में जाने का फैसला लिया था। कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि यह कदम सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा। इससे 270 दिन की तय अवधि में आरकॉम की संपत्ति बेचकर कर्ज के भुगतान की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। पिछले दिनों आरकॉम ने अपीलेट ट्रिब्यूनल से स्टे की अपील वापस ले ली थी।

2. कारोबार में घाटा होने और कर्ज बढ़ने की वजह से आरकॉम ने 2 साल पहले ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। उसने रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचकर दिवालिया होने से बचने की कोशिश की लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और सरकार की ओर से मंजूरी में देरी की वजह से डील नहीं हो पाई।

3. इस साल मार्च में आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी ने बड़े भाई की मदद से एरिक्सन के 480 करोड़ रुपए चुकाए और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचे, नहीं तो अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ता। एरिक्सन ही पिछले साल आरकॉम के खिलाफ एनसीएलटी गई थी।

4. एरिक्सन से पहले चाइना डेवलपमेंट बैंक ने भी दिवालिया अदालत (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटाया था। आरकॉम ने उससे 1 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। बाद में आरकॉम ने मुंबई स्थित अपने मुख्यालय का एक हिस्सा देकर सेटलमेंट किया।

5. पिछले हफ्ते 3 तारीख को एसबीआई ने आरकॉम पर दिवालिया प्रक्रिया के लिए आरपी शॉर्टलिस्ट करने के लिए मीटिंग रखी। अप्रैल में इसका प्रस्ताव पेश किया था। आरकॉम के क्रेडिटर्स की कमेटी को 66 फीसदी वोटों के साथ नए आरपी के लिए मंजूरी देनी होगी। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने मौजूदा आरपी को 30 मई तक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। उसी दिन मामले की सुनवाई होगी।

SOURCE: https://www.bhaskar.com/

10. रिलायंस की सहायक कंपनी ने ब्रिटेन के खिलौना रिटेलर Hamleys का अधिग्रहण किया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की सहायक कंपनी रिलायंस ब्रांड्स ने सी.बनर इंटरनेशनल के यूके-बेस्ड Hamleys का अधिग्रहण किया।

Hamleys के बारे में

18 देशों में Hamleys के लगभग 167 स्टोर हैं। भारत में, रिलायंस के पास Hamleys के लिए मुख्य फ्रैंचाइज़ी है, और वर्तमान में यह 29 शहरों में 88 स्टोर संचालित करती है।

अधिग्रहण क्यों किया गया?

यह अधिग्रहण रिलायंस ब्रांड को वैश्विक खिलौना खुदरा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना देगा। जैसा कि ज्ञात है, रिलायंस इस साल के अंत में एक ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस शुरू करने की योजना बना रहा है जो भोजन, फैशन से लेकर खिलौने तक सब कुछ बेच देगा और यह अधिग्रहण पूरी तरह से अपनी रणनीति में फिट होगा।

Hamleys का इतिहास

Hamleys वर्तमान में चीनी फैशन समूह सी.ब्नेर इंटरनेशनल के स्वामित्व में है, जिसने 2015 में इसे £100 मिलियन के लिए अधिग्रहण किया था।

हम्लेस ने 1760 में,एक एकल-दुकान, नूह के आर्क से शुरुआत की, उस समय के आसपास जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी।

(**Source:** https://indianexpress.com/article/business/companies/reliance-subsidiary-acquires-uk-toy-retailer-hamleys-5720180/)

11. ऑटोमोबाइल बिक्री में गिरावट आना भारत में आर्थिक मंदी का संकेत है (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

हालिया संकेतक

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने अप्रैल में कुल ऑटोमोबाइल उद्योग की बिक्री में लगभग 16% की गिरावट दर्ज की है। मार्च के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से पता चलता है कि उत्पादन एक साल पहले से 0.1% गिर गया। यह 21 महीने के निचले स्तर पर था। पूर्ववर्ती माह में 8.9% संकुचन के कारण पूंजीगत वस्तु क्षेत्र 8.7% तक घट गया है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 5.1% गिर गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति

दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति भी खराब होने की उम्मीद है, और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण पहले से ही तेल की कीमतों को आगे बढ़ा रहे हैं।

नई सरकार से उम्मीदें

23 मई के बाद उभरने वाली नई सरकार को उचित नीतिगत उपाय करने होंगे, जिससे न केवल मांग में मजबूती आए, बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सके कि इस तरह का पुनरुद्धार मजबूत हो, एक समान रूप से हो और स्थायी हो।

(Source:https://www.thehindu.com/opinion/editorial/missing-demand/article27130430.ece)

12. RBI अब अपने ऋण-हानि अनुपात में सुधार के लिए बैंकों को बाध्य करने के लिए विचलन का उपयोग करता है (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

ऋण मान्यता में विचलन क्या है?

विचलन तब होता है जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को पता चलता है कि किसी ऋणदाता ने किसी विशेष वर्ष में अप्राप्य ऋणों की न्यूनरिपोर्ट (या बिलकुल भी नहीं) की है और इसलिए ऋणदाता को प्रकटीकरण करने के लिए कहता है यदि न्यून-रिपोर्टिंग अप्राप्य ऋणों या प्रावधान का 10% से अधिक है।

डिफ़ॉल्ट रूप से कौन से बैंक हैं?

तीन सरकारी बैंकों- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने परिणामों की घोषणा करते हुए विचलन की सूचना दी थी। इन सभी बैंकों में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विचलन देखा गया। विचलन की पहचान नहीं की गई क्योंकि इन बैंकों ने ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया था, लेकिन क्योंकि उन्हें वर्गीकृत करने में देर हो गई थी।

एनपीए की श्रेणियां

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, लंबित ऋण की अवधि के आधार पर बैंकों को एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।

1. अवमानक परिसंपत्तियां (Substandard assets): परिसंपत्ति जो 12 महीने या उससे कम अवधि से एनपीए बनी हुई हैं।

2. संदिग्ध परिसंपत्तियां (Doubtful assets): परिसंपत्ति को संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक परिसंपत्ति श्रेणी में रही है।

3. हानि परिसंपत्तियां (Loss assets): एक हानि परिसंपत्ति असंग्रहणीय होती है या संग्रहणीय है, परंतु बहुत थोड़े मान को संदर्भित करती है। हालांकि हानि परिसंपत्ति का कुछ न्यूनतम या पुनर्प्राप्ति मान हो सकता है।

विचलन उच्च प्रावधान की ओर कैसे जाता है?

चूंकि एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तारीख को पीछे कर दिया गया था, इसलिए बैंकों को उच्च प्रावधान करना पड़ा। एनपीए के पहले चरण में, जो कि 'अवमानक' श्रेणी है, 15-20% प्रावधान की आवश्यकता है और अगली श्रेणी के लिए, जो 'संदिग्ध' है, 40% प्रावधान की आवश्यकता है। इसलिए, बैंकों को पहले की तारीख में एनपीए के रूप में खाते को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया है, जिसका अर्थ है, परिपक्वन के कारक के कारण प्रावधान की आवश्यकता में वृद्धि।

13. गिरते निर्यात के कारण भारत का बढ़ता व्यापार घाटा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

गिरता हुआ निर्यात

विदेशी व्यापार के लिए अनुमान अप्रैल में व्यापारिक निर्यात वृद्धि में तेज मंदी दिखाते हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.64% है। यदि हम विदेशी बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों के शिपमेंट में 31% वृद्धि की गणना नहीं करते हैं, तो भारत का माल का निर्यात वास्तव में पिछले महीने डॉलर के संदर्भ में 3% से अधिक है।

निर्यात में कमी का विश्लेषण

निर्यात में गिरावट 30 प्रमुख उत्पाद समूहों में से 16 में देखी गई थी। गिरावट इंजीनियरिंग और यहां तक कि परंपरागत रूप से मजबूत निर्यात क्षेत्रों - मणि और आभूषण, चमड़ा और चमड़े के उत्पादों, कपड़ा और वस्त्र और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में देखी गई। ये क्षेत्र सभी नौकरियों के प्रमुख प्रदाता हैं। इस प्रकार, इन क्षेत्रों में कमी से घरेलू बाजार में नौकरियों, मजदूरी और खपत की मांग प्रभावित होगी।

आयात में वृद्धि

कच्चे तेल और सोने की खरीद के कारण अप्रैल में आयात 4.5% बढ़कर $41.4 बिलियन हो गया। हालांकि, तेल और सोने को छोड़कर, पिछले महीने 2% से अधिक आयात किया गया, यह दर्शाता है कि वास्तविक उत्पादक क्षेत्रों में आयात की मांग कम हो गई है।

निर्यात की जगह माल के आयात के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 के पहले नौ महीनों में व्यापार घाटा बढ़कर 51.9 अरब डॉलर हो गया है। यह पहले से ही वित्तीय वर्ष की 12 महीने की कमी से $ 48.7 बिलियन से आगे निकल गया है।

(Source:https://www.thehindu.com/opinion/editorial/external-woes/article27165660.ece)

14. डब्ल्यूटीओ में अपील क्यों अटकी हुई है, अगर प्रक्रिया टूट जाती है तो भारत कैसे प्रभावित होगा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का विवाद निपटान तंत्र एक "संकट" से गुजर रहा है: निकाय अपने नए अपीलीय निकाय में नए सदस्यों को नियुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है जो व्यापार में अपील सुनता है। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक निकाय निष्क्रिय हो सकता है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवादों में बंद देशों को सहारा के लिए कोई मंच नहीं बचेगा। इन नियुक्तियों में कठिनाई के कारण डब्ल्यूटीओ की विवाद समाधान प्रणाली को ध्वस्त होने से रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए पिछले सप्ताह 20 से अधिक विकासशील देशों ने नई दिल्ली में मुलाकात की।

डब्ल्यूटीओ की अपीलीय संस्था क्या है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

1995 में स्थापित अपीलीय निकाय, सात सदस्यों की एक स्थायी समिति है जो डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा लाए गए व्यापार-संबंधी विवादों में पारित निर्णयों के खिलाफ अपील की अध्यक्षता करती है। विश्व व्यापार संगठन में 500 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विवादों के साथ और 1995 के बाद से जारी 350 से अधिक शासनों ने, संगठन का विवाद निपटान तंत्र दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय है, और अपीलीय निकाय इन मामलों में सर्वोच्च प्राधिकारी है।

निकाय की वर्तमान स्थिति क्या है?

पिछले दो वर्षों में, निकाय की सदस्यता आवश्यक सात के बजाय केवल तीन व्यक्तियों तक रह गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो मानता है कि विश्व व्यापार संगठन इसके खिलाफ पक्षपाती है, नए सदस्यों की नियुक्तियों को रोक रहा है और कुछ सदस्यों के पुनर्नियुक्ति, जो अपने चार साल के कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं, कर रहा है। इस वर्ष दिसंबर में दो सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, केवल एक सदस्य के साथ निकाय छोड़ेंगे।

एक अपील की अध्यक्षता के लिए कम से कम तीन लोगों की आवश्यकता होती है, और यदि दो सेवानिवृत्त लोगों को बदलने के लिए नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो निकाय प्रासंगिक होना बंद हो जाएगा। 1995 और 2014 के बीच, अपनाया गया 201 पैनल की रिपोर्ट का लगभग 68% की अपील की गई थी। जबकि अमेरिका सीधे विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों की तुलना में अधिक विवादों में शामिल है, भारत सहित कई देश-विवादों में तीसरे पक्ष के रूप में दर्ज होते हैं। भारत अब तक 54 विवादों में प्रत्यक्ष भागीदार रहा है, और 158 में तीसरे पक्ष के रूप में शामिल रहा है।

और यहाँ से आगे का रास्ता क्या है?

जबकि अपीलीय निकाय की नई नियुक्तियां आमतौर पर डब्ल्यूटीओ के सदस्यों की आम सहमति से होती हैं, वहां मतदान के लिए प्रावधान है जहां सर्वसम्मति संभव नहीं है। भारत सहित 17 कम विकसित और विकासशील देशों के समूह ने अपीलीय निकाय में गतिरोध को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, इस आशय के एक प्रस्ताव को प्रस्तुत या समर्थन कर सकते हैं, और बहुसंख्यक मत द्वारा अपीलीय निकाय पर नए सदस्य प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।

(Source;https://indianexpress.com/article/explained/why-appeals-are-stuck-at-wto-how-india-will-be-hit-if-process-breaks-down-5736410/)

15. 1.5 लाख करोड़ की कार्ययोजना को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए एक महत्वाकांक्षी 1.5 लाख करोड़ की कार्ययोजना शुरू करने की योजना बनाई है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन योजना के रूप में वर्णित किया जा रहा है। आखिरी एनईपी 1986 में संशोधन के साथ 1992 में जारी किया गया था।

EQUIP परियोजना

मंत्रालय की EQUIP परियोजना शुरू करने की योजना है। EQUIP का मतलब शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम है और दस समितियों द्वारा तैयार किया गया था, जिसका नेतृत्व नीतीयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और पूर्व राजस्व सचिव हसमुख अढिया और सरकार के भीतर कुछ कॉर्पोरेट प्रमुखों ने किया था।

दस समितियों ने उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए रणनीति का मसौदा तैयार किया है, विशेष रूप से सेवा वाले समुदायों के लिए; सकल नामांकन राशन में सुधार; शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार; शैक्षिक बुनियादी ढांचे का निर्माण; अनुसंधान और नवाचार की गुणवत्ता में सुधार; प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षण उपकरण का उपयोग; और मान्यता प्रणालियों, शासन संरचनाओं और वित्तपोषण पर काम करते हैं।

धन की आवश्यकता

यह देखते हुए कि पिछले बजट में उच्च शिक्षा विभाग को केवल 37,461 करोड़ आवंटित किए गए थे, EQUIP परियोजना को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होगी। सचिव ने कहा कि केंद्र उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (HEFA) के माध्यम से बाजार से पैसा जुटाएगा।

यह HEFA के वर्तमान दायरे से परे होगा। एचआरडी मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच 2017 में स्थापित संयुक्त उद्यम को 2022 तक उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ जुटाने का काम सौंपा गया है। एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब तक ₹ 30,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(Source:https://www.thehindu.com/education/higher-education-to-get-a-boost-with-15-lakh-crore-action-plan/article27240106.ece)

16. ड्राफ्ट निर्यात नीति का अनावरण किया गया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

वाणिज्य मंत्रालय निर्यात नीति के एक व्यापक मसौदे के साथ सामने आया है जिसमें निर्यातकों के लिए तैयार गणक प्रदान करने के लिए उत्पाद-विशिष्ट नियम शामिल हैं। मसौदा नीति का उद्देश्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों पर लागू प्रत्येक उत्पाद के लिए निर्यात मानदंडों को मजबूत करना है। संकलन एक निर्यातक को किसी विशेष उत्पाद से संबंधित सभी लागू मानदंडों को जानने में मदद करेगा, जिससे उसे उस वस्तु के लिए नीतिगत शर्तों को समझने में मदद मिलेगी।

नीति के पीछे तर्क

हर उत्पाद को आठ अंकों का एचएस कोड दिया गया है।

यह कवायद मानदंडों को मजबूत करने के लिए है न कि देश की मौजूदा निर्यात नीति में कोई बदलाव करने के लिए। डीजीएफटी ने कहा कि अद्यतन मसौदा जनवरी 2018 के बाद जारी सभी मौजूदा नीतिगत शर्तों, सभी अधिसूचनाओं और सार्वजनिक नोटिसों को शामिल करके तैयार किया गया था। इसके अलावा, इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाए गए गैर-टैरिफ नियम भी शामिल हैं।

17. यूएस ने भारत को करेंसी वॉचलिस्ट से हटा दिया)Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

अमेरिकी सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव बढ़ने के कारण संभावित रूप से संदिग्ध विदेशी मुद्रा नीतियों के लिए प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की अपनी सूची से भारत को हटा दिया।

भारत का नाम क्यों हटाया गया?

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की मैक्रोइकॉनॉमिक और विदेशी मुद्रा नीतियों के अनुसार भारत को ट्रम्प प्रशासन की कुछ चिंताओं को उसकी मुद्रा प्रथाओं और वृहद आर्थिक नीतियों से करने के लिए सूची से "संबोधित"हटा दिया गया है। इसके अनुसार, भारत से चिंता का एकमात्र कारक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय "महत्वपूर्ण" व्यापार अधिशेष है, जो देश की अधिकतम सीमा $ 20 बिलियन को पार करता है।

निगरानी सूची में जोड़ने का मापदंड क्या है?

अमेरिका ने अपनी निगरानी सूची में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों को शामिल किया है अगर वे कम से कम दो तीन मानदंडों को पूरा करते हैं यदि इसके पास या तो अमेरिका के साथ एक - महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष है, अगर इसमें सामग्री चालू खाता अधिशेष है या यदि यह विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार एकतरफा हस्तक"ेषेप में लगा हुआ है। "

व्यापार संबंधों में सुधार को दर्शाता है

मुद्रा नीति का इस्तेमाल ट्रम्प प्रशासन ने व्यापार वार्ता में एक उपकरण के रूप में किया है। यह कदम मात्रात्मक मानदंडों पर आधारित है लेकिन यह भारतअमेरिका व्यापार तनाव में संभावित - गिरावट को इंगित करता है। अमेरिका अपने नोटिस की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत को व्यापार लाभ की वापसी को सूचित करने पर रोक लगा रहा है, संभवतः इस उम्मीद में कि नई सरकार गतिरोध का बचाव करेगी।

भारत कब शामिल हुआ था?

भारत को एक साल पहले सूची में शामिल किया गया था, क्योंकि 2017 में, वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में विदेशी मुद्रा की खरीद ने विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से ऊपर धकेल दिया था। इसमें 20 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार अधिशेष भी था। वर्तमान सूची के देशों में चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम शामिल हैं।

अमेरिका से दबाव

पिछले दो वर्षों में, अमेरिका ने स्टील और एल्युमीनियम जैसे उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाया, साथ ही देश को उसके सामान्यीकृत प्रणाली से हटा दिया, जिससे भारतीय व्यवसायों को कुछ व्यापार लाभ प्राप्त हुए।

Environment

1. IUCN study on melting of glaciers- बढ़ते तापमान की वजह से सन 2100 तक पिघल जाएंगे दुनिया के आधे हैरिटेज ग्लेशियर (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Environment)

वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को लेकर एक और चेतावनी जारी की गई है। एक शोध में कहा गया है कि अगर दुनिया का तापमान मौजूदा रफ्तार से बढ़ता रहा तो सन 2100 तक विश्व के आधे हैरिटेज ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इससे पीने के पानी का संकट पैदा होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और मौसम चक्र में भी परिवर्तन हो सकता है। इस आपदा की चपेट में आकर हिमालय का खुम्भू ग्लेशियर भी खत्म हो सकता है।

तीन बड़े हैरिटेज ग्लेशियर पर खतरा ज्यादा

यह अध्ययन 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर' यानी आईयूसीएन ने किया है। हैरिटेज ग्लेशियर्स को लेकर यह दुनिया का पहला शोध माना गया है। रिसर्च में शामिल वैज्ञानिकों के अनुसार, स्विट्जरलैंड के मशहूर ग्रोसर एल्चेस्टर और ग्रीनलैंड के जैकबशावन आईब्रेस भी खतरे के दायरे में आते हैं। अध्ययन के लिए ग्लोबल ग्लेशियर इन्वेंट्री डेटा के अलावा कंप्यूटर मॉडल की भी मदद ली गई। इनके जरिए वर्तमान स्थितियों का आकलन किया गया।

21 ग्लेशियर को बचाना मुश्किल

शोध पत्र में कहा गया है कि अगर तापमान वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन मौजूदा दर से होता रहा तो सन 2100 तक 46 प्राकृतिक ग्लेशियरों में से 21 हैरिटेज खत्म हो जाएंगे। रिसर्च के मुताबिक, अगर उत्सर्जन कम भी होता है तो इनमें से आठ को बचाना मुश्किल होगा।

मानव सभ्यता के लिए खतरनाक होंगे परिणाम

शोध की अगुआई करने वाले वैज्ञानिक पीटर शैडी ने कहा, "इन ग्लेशियर को खोना किसी त्रासदी से कम नहीं होगा। इसका सीधा असर पेयजल के संसाधनों पर पड़ेगा। समुद्री जलस्तर में वृद्धि होगी और मौसम चक्र पर भी इसका असर साफतौर पर देखा जाएगा। अब दुनियाभर की सरकारों को चेत जाना चाहिए क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन ग्लेशियरों का रहना बेहद जरूरी है।

2. दस लाख प्रजातियों पर लटकी विलुप्ति की तलवार, इंसानी जीवन भी होगा प्रभावित (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Environment & Biodiversity)

विनाशलीला के छठे दौर की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। हर चार में से एक प्रजाति पर विलुप्ति की तलवार लटकने लगी है। दुनिया से जैव विविधता खत्म होगी तो इंसानी जीवन भी अप्रभावित नहीं रहेगा। हम अपने विनाश की ओर बढ़ चले हैं। यह निष्कर्ष है दुनिया में जैव विविधता को लेकर किए गए अब तक के सबसे बड़े अध्ययन का। सोमवार को प्रकाशित इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बॉयोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (आइपीबीईएस) की इस रिपोर्ट का संयुक्त राष्ट्र ने भी समर्थन किया है। दुनिया भर के पचास देशों के पांच सौ विशेषज्ञ इसमें शामिल रहे।

खत्म हो रही विविधता

अध्ययन के अनुसार प्रत्येक चार में से एक प्रजाति पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। स्थलीय और जलीय जीव भी इसकी चपेट में हैं। पादप प्रजातियां भी इस संकट से गुजर रही हैं। जो प्रजातियां जल और थल दोनों पर रहती हैं, उनको सर्वाधिक खतरा है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि दुनिया जीवों के विनाश की घटना की तरफ बढ़ रही है। 50 करोड़ साल में यह ऐसा छठा घटनाक्रम होगा। पूर्व की तुलना में मौजूदा विनाशलीला की दर हजार गुना तेज है।

चौथाई जमीन मानव से दूर

आइपीबीईएस के अध्ययन के अनुसार धरती का एक चौथाई हिस्सा ही ऐसा है जो इंसानी गतिविधियों के असर से अभी अछूता है। हालांकि इसको लेकर भी चिंता बढ़ रही है। 2050 तक ऐसी जमीन की हिस्सेदारी सिर्फ दसवें हिस्से तक सिमट जाएगी।

परागण की बड़ी समस्या

दुनिया की 75 फीसद खाद्य पदार्थों से जुड़ी फसलें परागण के लिए जीवों पर आश्रित हैं। ऐसे में परागण कीटों के नुकसान से सालाना वैश्विक फसलों के 235-577 अरब डॉलर का आउटपुट खतरे में है। दुनिया की खाद्य सुरक्षा हिचकोले लेते दिख रही है।

जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन

अध्ययन की रिपोर्ट में चेताया गया है कि जब तक आप जैव विविधता नहीं बचाएंगे तब तक जलवायु परिवर्तन का सिलसिला नहीं रुकेगा और जब जलवायु परिवर्तन को रोका जाएगा तभी जैव विविधता रहेगी और तभी दुनिया का हर जीव सुरक्षित रहेगा।

जमीन की खराब गुणवत्ता

इंसानी गतिविधियां नकारात्मक रूप से 3.2 अरब लोगों का कल्याण प्रभावित कर रही हैं। गैर टिकाऊ कृषि और वानिकी, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण इसकी बड़ी वजहें हैं। 2018 में दुनिया के उष्ण कटिबंधीय इलाकों में करीब 1.20 करोड़ हेक्टेयर वन खत्म हो गए।

SOURCE: https://www.jagran.com/

3. तटीय विनियमन क्षेत्र: तट के साथ निर्माण के नियम कैसे विकसित हुए हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Environment)

विनियमन क्षेत्र की परिभाषा

सभी सीआरजेड नियमों में, विनियमन क्षेत्र को उच्च-ज्वार रेखा से 500 मीटर तक के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। जनसंख्या, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, किनारे से दूरी आदि जैसे मानदंडों के आधार पर कई तरह के प्रतिबंध लागू होते हैं।

CRZ के उल्लंघन का चित्रण

प्रशासनिक तंत्र

जबकि CRZ नियम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन कार्यान्वयन उनके तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों को केंद्रीय नियमों के अनुसार अपने स्वयं के तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना चाहिए।

CRZ नियम, 1991

CRZ नियम समुद्र के पास दुर्बल पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने के लिए तट के करीब मानव और औद्योगिक गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अनिवार्य नियम 1991 में पहली बार बनाए गए थे। मूल विचार यह है: क्योंकि समुद्र के बगल में स्थित क्षेत्र बेहद दुर्बल होते हैं, कई समुद्री और जलीय जीवन रूपों के लिए घर, को दोनों जानवरों और पौधों, और जलवायु परिवर्तन से भी खतरा होता है, उन्हें अनियंत्रित विकास से बचाने की आवश्यकता होती है।

1991 के नियमों में संशोधन की आवश्यकता है

कई संशोधनों के बावजूद, राज्यों ने 1991 के नियमों को अत्यंत प्रतिबंधक पाया। उन्होंने शिकायत की कि यदि सख्ती से लागू किया जाता है, तो नियम तट के करीब रहने वाले लोगों के लिए सभ्य घर बनाने और बुनियादी विकासात्मक कार्यों को पूरा करने जैसी सरल चीजों की अनुमति नहीं देंगे। 1991 के नियमों ने ओडिशा में पोस्को स्टील प्लांट और नई सदी के पहले दशक में प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डे जैसे औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बाधाएँ भी पैदा कीं।

नियमों का विकास

केंद्र ने 2011 में नए सिरे से सीआरजेड नियमों को अधिसूचित किया, जिसने कुछ चिंताओं को दूर किया। नवी मुंबई हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक छूट दी गई थी। (पोस्को परियोजना अन्य कारणों से बंद करने में विफल रही थी।) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं, जो तट के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है, को छूट दी गई थी। हालाँकि, ये नियम अपर्याप्त भी पाए गए।

पर्यावरण मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में नए सीआरजेड नियम जारी किए, जिन्होंने निर्माण पर कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया, निकासी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया, और तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा।

वर्तमान स्थिति

इस साल जनवरी में, सरकार ने नए सीआरजेड नियमों को अधिसूचित किया। तथाकथित CRZ-III (ग्रामीण) क्षेत्रों के लिए, दो अलग-अलग श्रेणियों को निर्धारित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2,161 प्रति वर्ग किमी की जनसंख्या घनत्व के साथ घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों (CRZ-IIIA) में, नो-डेवलपमेंट ज़ोन अब उच्च-ज्वार स्तर से 50 मीटर है, जो पहले 200 मीटर था। CRZ-IIIB श्रेणी में (2,161 प्रति वर्ग किमी के नीचे जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों) में उच्च-ज्वार रेखा से 200 मीटर तक का कोई विकास क्षेत्र नहीं है। नए नियमों में मुख्य भूमि के तट के पास के सभी द्वीपों और मुख्य भूमि के सभी बैकवाटर द्वीपों के लिए 20 मीटर का नो-डेवलपमेंट ज़ोन है।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/coastal-regulation-zone-how-rules-for-building-along-coast-have-evolved-5726052/)

4. वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता एक नई ऊँचाई पर पहुँची (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Environment)

11 मई को, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक सांद्रता को पहली बार 415 भागों प्रति मिलियन (पीपीएम) के निशान को पार कर दिया। तेजी से बढ़ती एकाग्रता इस बात का सूचक है कि ग्रह गर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जितनी अधिक होगी, ग्रीनहाउस गैस का प्रभाव उतना ही अधिक होगा जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाएगा।

कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता की प्रवृत्ति

कई हजार वर्षों तक, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता 270-280 पीपीएम के आसपास स्थिर रही, इससे पहले कि औद्योगिक क्रांति ने धीरे-धीरे इसे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। जब 1958 में वेधशाला में प्रत्यक्ष माप शुरू हुआ, तो सांद्रता 315 पीपीएम के आसपास थी। इसे 380 पीपीएम तक पहुंचने में लगभग 50 साल लग गए, यह पहली बार 2004 में कम हो गया था, लेकिन इसके बाद वृद्धि तेजी से हुई।

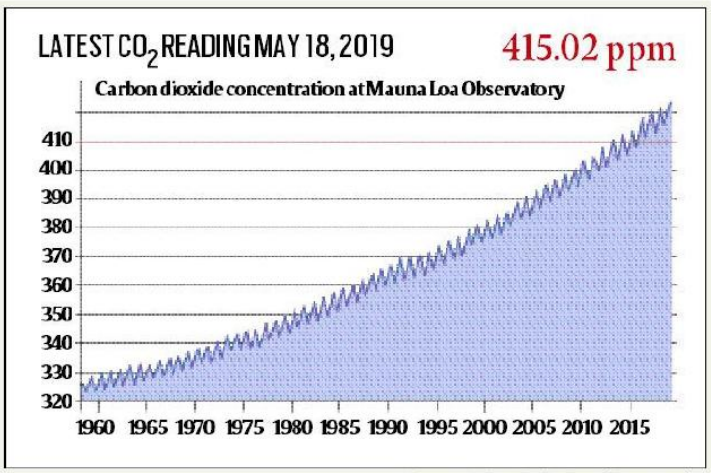

वर्तमान में, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रति वर्ष 2 पीपीएम से अधिक बढ़ रही है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वर्ष से वृद्धि दर 3 पीपीएम तक पहुंचने की संभावना है।

कार्बन डाइऑक्साइड का लंबा जीवन

वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा लगातार विभिन्न, ज्यादातर मानव निर्मित, प्रक्रियाओं में उत्सर्जित होने के कारण होती है। हाल के वर्षों में, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि काफी कम हो गई है। यह 2014 और 2016 के बीच लगभग सपाट रहा, और 2017 में 1.6% और 2018 में लगभग 2.7% बढ़ा। 2018 में, कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन का अनुमान 37.2 बिलियन टन था।

वायुमंडलीय सांद्रता में तेजी से वृद्धि, इस तथ्य के कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में बहुत लंबा जीवनकाल है, 100 और 300 वर्षों के बीच। इसलिए, भले ही उत्सर्जन चमत्कारिक रूप से अचानक शून्य हो जाए, लेकिन निकट अवधि में वायुमंडलीय सांद्रता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा हिस्सा पौधों और महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे वायुमंडल में जाने के लिए दूसरे आधे हिस्से को छोड़ दिया जाता है। वायुमंडल में लगभग 7.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त होने से इसकी वायुमंडलीय सांद्रता में 1 पीपीएम वृद्धि होती है। इसलिए, 2018 में, उदाहरण के लिए, कुल उत्सर्जन का आधा, या लगभग 18.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में जोड़ा गया होगा, जिससे वायुमंडलीय सांद्रता में 2.48 पीपीएम की वृद्धि होगी।

पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एक पूर्वानुमान योग्य मौसमी परिवर्तनशीलता का अनुसरण करता है। पौधे गर्मियों के दौरान अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी गोलार्ध के गर्मियों के महीनों में कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा वायुमंडल में जुड़ जाती है, जिसमें दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में काफी अधिक वनस्पति होती है। यह परिवर्तनशीलता कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडलीय एकाग्रता के बहुत लयबद्ध मौसमी उतार-चढ़ाव में देखी जा सकती है।

तापमान समतुल्यता

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक लक्ष्य को तापमान लक्ष्यों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के लक्ष्य में। वैश्विक समुदाय का घोषित प्रयास 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के औसत तापमान में वृद्धि को बनाए रखना है। वैश्विक तापमान में 2ºC वृद्धि के अनुरूप कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता स्तर को आमतौर पर 450 पीपीएम समझा जाता है। विकास दर की मौजूदा दरों पर, यह स्तर 12 साल से भी कम समय में पहुंच जाएगा, यानी 2030 तक। पूर्व-औद्योगिक समय के दौरान की तुलना में अधिक, और यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे।

कुछ साल पहले तक, यह समझा जाता था कि यह मील का पत्थर कम से कम 2035 तक नहीं पहुंचेगा। 1.5ºC वृद्धि के लिए इसी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा पिछले साल जारी एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया को कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, बल्कि ग्रीनहाउस गैसों के शुद्ध शून्य उत्सर्जन को हासिल करने की जरूरत है, जो कि 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर तापमान में वृद्धि को रोकने के किसी भी यथार्थवादी संभावना को जीवित रखने के लिए है। 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध शून्य को 2075 तक प्राप्त करने की आवश्यकता है।

नेट शून्य तब प्राप्त होता है जब कुल उत्सर्जन को जंगलों जैसे प्राकृतिक सिंक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण द्वारा निष्प्रभावी किया जाता है, या तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/carbon-dioxide-in-atmosphere-hits-a-high-how-it-relates-to-global-warming-5741252/)

5. एक संघर्ष क्षेत्र बनना: महाराष्ट्र के जंगल में मानव बनाम बाघ (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Environment)

वन्यजीवों के हमलों में मानव की मौतें महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी के जंगलों में 2006 में 6 से, 2018 में 18 तक बढ़ रही हैं, उनमें से ज्यादातर बाघ और तेंदुए के हमलों में हुई हैं। इस क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष क्षेत्र के रूप में उभरने वाले कारकों पर एक नज़र, और शमन या उपाय खोजे गए:

क्षेत्र

चंद्रपुर जिले का 1,200 वर्ग किलोमीटर का ब्रह्मपुरी वन प्रभाग - 41 बाघों (16 नर, 25 मादा, कुछ 15-16 शावकों के अलावा) के साथ-साथ 80-90 तेंदुओं का घर - एक बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ब्रह्मपुरी आज देश का सबसे कीमती बाघ गैर-संरक्षित क्षेत्र है।

बाघ की आबादी

ब्रह्मपुरी में मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनने के कारणों में, सबसे स्पष्ट है बाघों की संख्या 2013 में लगभग 15-16 से बढ़कर अब 41 हो गई है। संपूर्ण रूप से चंद्रपुर जिले में 100 से अधिक बाघ हैं, संभवतः यह देश में कहीं भी एक जिले के लिए सबसे अधिक

है। ब्रह्मपुरी के 41 बाघों को 610 से अधिक गांवों के साथ रहना पड़ता है, जिनमें से आधे जंगल के करीब हैं।

मवेशी का घनत्व

संघर्ष के अन्य कारणों में जंगल का उच्च विखंडन और उच्च मवेशी घनत्व हैं। बाघों के लिए आसान भोजन होने के कारण, मवेशी मारने के मामले 2009-10 में 305 से बढ़कर 2018-19 में 852 हो गए हैं। बाघों से भरे जंगल के लिए ब्रह्मपुरी में सड़कों की संख्या सबसे अधिक है। और फिर चारों तरफ कृषि क्षेत्र हैं। तो, बाघ फैलाव या गतिविधि मनुष्यों के साथ संघर्ष को ट्रिगर करने के लिए बाध्य है।

अन्य कारक

बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए एक प्रमुख कारक संगठित अवैध गिरोह है जो 2013 से काम कर रहा था।

महुआ के फूल

किसी भी जंगल के साथ, मानव-वन्यजीव संघर्ष ज्यादातर वन्यजीवों के साथ लोगों के इंटरफेस के कारण होता है। लोग ब्रह्मपुरी जंगल के अंदर जाते हैं और मामूली वन उपज और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते हैं। आम तौर पर अप्रैल-मई के दौरान संघर्ष तेज होता है, जब लोग महुआ के फूलों और तेंदू के पत्तों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं, जिसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। महुआ के फूल पोषक तत्वों से भरपूर और खाद्य होते हैं, और शराब बनाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं।

शमन के उपाय

वन अधिकारियों ने संभावित संघर्ष स्थलों की मैपिंग की है। जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिए 50% अनुदान पर एलपीजी प्रदान करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने जंगलों में प्रवेश किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि वन्यजीवों के हमलों में मानव मृत्यु की संख्या 2008 में 6 से घटकर 2013 में 1 हो गई।

स्थानांतरण का विकल्प

यह अब तक अस्पष्ट है। नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जहां महिला आबादी में कमी हैं। वह भी क्षेत्र में तेजी से प्रजनन को कम करेगा।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/making-of-a-conflict-zone-humans-vs-tigers-in-a-maharashtra-forest-5743146/)

Science and Technology

1. 5G technology based television- हुवावे लाएगी दुनिया का पहला 5G टेक्नोलॉजी वाला टेलीविजन, 8K रेजोल्यूशन को करेगी सपोर्ट (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

चीनी कंपनी हुवावे दुनिया का पहला 5G टेक्नोलॉजी वाला टेलीविजन लाने का प्लान कर रही है। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस टीवी से सैमसंग और एपल जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देना चाहती है। हाल ही में जब सैमसंग ने दुनिया का पहला 5G टेक्नोलॉजी वाली स्मार्टफोन गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च किया था, तब उसके 2 दिन बाद ही हुवावे ने भी अपनी पहला 5G स्मार्टफोन मेट एक्स लॉन्च कर दिया था।

ऐसा होगा हुवावे की 5G अनेबल टीवी

निक्केई एशियन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक इस 5G टेलीविजन का डिस्प्ले 8K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। वहीं, दर्शक इस टीवी पर 360 डिग्री वीडियो देख पाएंगे। इसमें वर्चुअल रियलिटी (VR) कंटेंट के साथ दूसरे हैवी रेजोल्यूशन वीडियो भी प्ले होंगे।

रिपोर्ट में दावा है कि टीवी में कई ऐसे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे, जो किसी टीवी में पहली बार आएंगे। ये टीवी कंपनी के ही स्मार्ट होम अप्लायंस को सपोर्ट करेगा। पिछली तिमाही के दौरान हुवावे के सेलिंग आंकड़ों में लागतार ग्रोथ देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इसने एपल और सैमसंग की सेलिंग को भी पीछे छोड़ा है।

(Adapted from Bhaskar.com)

2. चीनी व पाक पोतों पर सेटेलाइट द्वारा रखी जा सकेगी नजर (Relevant for GS Prelims & GS Mains Paper III; Science & Technology)

आगामी 22 मई को भारत अंतरिक्ष में अपनी दूसरी आंख स्थापित करने जा रहा है। इस रडार इमेजिंग सेटेलाइट (रीसैट-2बीआर1) द्वारा किसी भी मौसम में एक मीटर की दूरी पर स्थित दो वस्तुओं की सटीक पहचान की जा सकेगी। इसी श्रृंखला के पूर्व में भेजे गए सेटेलाइट के इनपुट से ही भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था और जैश-ए-मुहम्मद के कैंपों को तबाह किया था।

रीसैट-2बीआर1

भारत की अंतरिक्ष में दूसरी आंख कहे जाने वाले इसरो के इस आधुनिक रडार इमेजिंग सेटेलाइट को 22 मई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा।

खूबियाँ

इस श्रृंखला के पूर्व में भेजे गए सेटेलाइट से यह काफी उन्नत है। इसकी इमेजिंग और सर्विलांस क्षमता काफी अधिक है। इसका एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार (एसएआर) रात दिन किसी भी मौसम में काम करेगा। बादलों के बीच भी लक्ष्य के पहचान की क्षमता है। धरती पर एक मीटर के दायरे में चीजों की स्पष्ट पहचान में सक्षम है। एक दिन में धरती पर मौजूद किसी वस्तु की यह दो या तीन बार तस्वीर ले सकेगा। इसीलिए कश्मीर में आतंकी कैंपों और सीमा पार कर घुसपैठ करने वाले आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने में इसे ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है।

समुद्री सुरक्षा में भी उपयोगी

भारतीय सीमाओं को हर ओर से सुरक्षित रखने में इसका अहम योगदान होगा। जिस तरह से चीन हिंद महासागर में भारत की घेरेबंदी कर रहा है उससे उसके युद्धपोतों पर नजर रखने में इस सेटेलाइट की बड़ी भूमिका होगी। अरब सागर में पाकिस्तानी पोतों पर भी इसकी नजर होगी। आपदा प्रबंधन में भी इसका प्रभावी उपयोगिता साबित होगी।

26/11 के बाद महसूस हुई जरूरत

मुंबई में 26 नवंबर को हुए आतंकी हमले के बाद रीसैट-1 पर रीसैट-2 कार्यक्रम को वरीयता दी गई। वजह यह थी कि इसमें इजरायल निर्मित ज्यादा उन्नत रडार प्रणाली लगी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि के लिए इसे 20 अप्रैल, 2009 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। धरती से 536 किमी की ऊंचाई पर यह सेटेलाइट रात-दिन भारतीय सीमाओं की निगहबानी कर रहा है।

(Adapted from jagran.com)

3. भारतीय नेवी में स्कॉर्पीन क्लास की चौथी पनडुब्बी आइएनएस वेला हुई लॉन्च (Relevant for GS Prelims & GS Mains Paper III; Science & Technology)

भारतीय नौसेना की चौथी स्कॉर्पीन पनडुब्बी आइएनएस वेला को मुंबई के मजगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) में लॉन्च किया गया। भारत कुल 6 स्कॉर्पीन पनडुब्बियों को पानी में उतारने वाला है जिनमें से 'वेला' चौथी है। इस पनडुब्बी के आने से देश की नौसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। बाकी बची दो पनडुब्बियां, आइएनएस वागीर और आइएनएस वागशीर पर काम चल रहा है और जल्द ही इन्हें भी समुंद्र में उतारा जाएगा।

पनडुब्बियों के बारे में

रक्षा मंत्रालय के इस महत्वाकांक्षी सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बियां हासिल करने में करीब 45 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन कंपनियों में अडानी डिफेंस, लार्सन एंड टुब्रो और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय ने 'एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट' का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसे संभावित कंपनियों के साथ साझा भी किया गया है। मालूम हो कि 'प्रोजेक्ट 75' के तहत पहले ही नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इनका डिजायन फ्रांसीसी कंपनी नैवल ग्रुप ने तैयार किया है।

(Adapted from Jagran.com)

4. सह संस्थापक ने कहा- जुकरबर्ग जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो गए, कंपनी का टूटना जरूरी
(Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

फेसबुक के सह संस्थापक क्रिस ह्यूज ने चेताया है कि कंपनी के हेड मार्क जुकरबर्ग जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इसलिए अब फेसबुक का टूटना जरूरी है। ह्यूज ने आरोप लगाया कि फेसबुक अपनी प्रतियोगी कंपनियों को या तो खरीद लेता है या फिर उनकी नकल कर लेता है, ताकि सोशल मीडिया के क्षेत्र में उसका वर्चस्व बना रहे। इससे इनवेस्टर भी किसी प्रतिद्वंदी कंपनी में पैसा नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता है कि वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे।

एक दशक पहले फेसबुक छोड़ चुके ह्यूज

जुकरबर्ग और क्रिस ह्यूज ने ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2004 में दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक शुरू किया था। हालांकि, करीब 10 साल पहले ह्यूज ने खुद को कंपनी से अलग कर लिया था। फिलहाल वह अमेरिका में इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट नाम के संगठन से जुड़े हैं। यह संगठन देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने की मांग उठा रहा है।

जुकरबर्ग का प्रभाव हैरान करने वाला

न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में ह्यूज ने आरोप लगाया कि फेसबुक को बढ़ावा देने के लिए यूजर्स की सिक्योरिटी और सभ्यता के साथ भी समझौता किया। उन्होंने कहा, "जुकरबर्ग का दुनिया पर प्रभाव हैरान करने वाला है। वे सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर भी नियंत्रण रखते हैं। कंपनी का बोर्ड भी एक सलाहकार समिति की तरह काम करता है, न कि अपने हेड के कामों पर नजर रखने वाले के तौर पर।"

अमेरिकी सरकार को फेसबुक को तोड़ देना चाहिए

क्रिस ह्यूज ने कहा कि फेसबुक की ताकत कम करने के लिए अमेरिकी सरकार को दो चीजें करनी चाहिए। पहली की वह फेसबुक का एकाधिकार खत्म करे और इसे नियम के मुताबिक चलाए ताकि इसे अमेरिकियों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सके। उन्होंने सरकार से अपील की वह इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को फेसबुक से अलग करे और कंपनी के किसी भी तरह के नए अधिग्रहण को कुछ सालों के लिए रोक दे। इससे फेसबुक को फायदा ही होगा और वह नई तकनीक में निवेश कर काफी फायदा पा सकेगा।

(Source: https://www.bhaskar.com**)**

5. क्यों देश 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक परिवहन की चाह में छोटे वाहनों को लक्षित कर रहा है? (Relevant for GS Prelims and Mains Paper III; Science & Technology)

हाल ही में, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की कि टाटा संस के एमरिटस के अध्यक्ष रतन टाटा ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एक अनिर्दिष्ट राशि का निवेश किया था। ओला इलेक्ट्रिक कई प्रायोगिक कार्यक्रम चला रही है जिसमें चार्ज करने के समाधान और दोपहिया और तिपहिया वाहनों को लगाना शामिल है। क्या ओला इलेक्ट्रिक की पहल 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्पार्क प्रदान करेगी?

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत की नीति क्या है?

जबकि शेष दुनिया में कार निर्माता प्रीमियम सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं (लागत 10 लाख से अधिक), भारत छोटे वाहनों को लक्षित कर रहा है। इसका कारण, NITI Aayog के अनुसार, भारतीय सड़कों पर 79% वाहन दुपहिया वाहन हैं, जबकि तीन-पहिया वाहन और कारों पर क्रमशः 4% और 12% वाहन की आबादी के लिए 10 लाख से कम खर्च होता है। छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने से घरेलू मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। जबकि चीन, यू.एस. और कुछ यूरोपीय देश इलेक्ट्रिक कारों को आगे बढ़ाने के लिए 40% तक की विभिन्न सब्सिडी देते हैं, भारत गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन देना चाहता है। वाहन की दक्षता के साथ-साथ प्रति किमी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आधार पर क्रेडिट की पेशकश की जाएगी। जबकि उत्सर्जन लक्ष्य को पार करने वाले निर्माताओं को क्रेडिट खरीदने की आवश्यकता होगी, उन्हें प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। क्रेडिट की कीमत बाजार द्वारा तय की जाएगी।

अगले पांच वर्षों में, भारत का लक्ष्य सड़क पर कम से कम 15% इलेक्ट्रिक वाहन लेकर आना है। 28 फरवरी को, भारत ने तीन साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन (FAME-2) योजना के दूसरे चरण की घोषणा की। तेजी से धारण करने को प्रोत्साहित करने के लिए, एक इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 लाख दोपहिया, 5 लाख तीन-पहिया, 55,000 चार-पहिया और 7,000 बसों का समर्थन करेगी। जबकि ध्यान दोपहिया वाहनों के लिए निजी वाहनों पर होगा, सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले तीन और चार पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' के तहत चार्जिंग स्टेशन और अन्य बुनियादी ढाँचे स्थापित करना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज क्या है?

लिथियम आयन बैटरी (दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली बैटरी) का उपयोग करने वाली इलेक्ट्रिक कारों में, यह 200 और 300 किमी प्रति चार्ज के बीच है। एक शहर में ड्राइविंग रेंज आमतौर पर प्रति दिन 25-30 किमी है। सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक बैटरी का जीवनकाल होगा। वर्तमान बैटरी तकनीक के अनुसार, इसका जीवनकाल बाकी वाहनों की तुलना में कम होगा। विकसित देशों में कुछ कार निर्माता बैटरी पर आठ साल या 1,60,000 किमी की वारंटी दे रहे हैं।

बैटरी को चार्ज करने में कितना समय लगेगा?

वर्तमान में, इलेक्ट्रिक कारों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों में 50 kWh (किलोवाट घंटा) की क्षमता होती है और इसे घर पर उपलब्ध मौजूदा बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके रात भर चार्ज किया जा सकता है। जैसे मोबाइल फोन के मामले में, इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी 7 और 22 किलोवाट की आपूर्ति का उपयोग करके तेजी से चार्ज की जा सकती है। सर्विस स्टेशनों पर चार्जिंग स्टेशनों में 50 या 120 किलोवाट की आपूर्ति होती है और बैटरी को 20-30 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। लेकिन तेजी से चार्ज करने से ओवरहीटिंग और निम्नीकरण होता है, और अगर बार-बार किया जाता है, तो बैटरी लाइफ कम हो जाती है।

क्या इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे?

भारत में लगभग 55% बिजली उत्पादन मुख्य रूप से कोयले का उपयोग कर रहा है। पनबिजली उत्पादन 13% है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिनमें लघु जलविद्युत परियोजनाएं, पवन और सौर, लगभग 21% शामिल हैं। तो जैसे अमेरिका और चीन के मामले में, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने पर भी कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध कमी ज्यादा नहीं होगी। यह फ्रांस और यू.के. के विपरीत है, जहां गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। हालांकि, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले शहरों और कस्बों में निकास-पाइप उत्सर्जन में कमी देखी जाएगी, विशेष रूप से सूक्ष्म कण। यह भारत के मामले में महत्वपूर्ण होगा जो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 का घर है।

क्या इस्तेमाल की जाने वाली बैटरियों को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है?

इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। 2025 तक बैटरी रीसाइक्लिंग एक उद्योग बन जाएगा जब इस्तेमाल किया बैटरी भरपूर मात्रा में हो जाएगा।

क्या मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोबाल्ट है?

लिथियम आयन बैटरी में, कोबाल्ट कैथोड (सकारात्मक इलेक्ट्रोड) का एक प्रमुख घटक है। कोबाल्ट ओवर-हीटिंग को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी को स्थिरता प्रदान करता है और इस प्रकार कई वर्षों में चार्जिंग और निर्वहन की अनुमति देता है। कोबाल्ट खनन निकल और तांबे का उप-उत्पाद है। दुनिया में कोबाल्ट की आपूर्ति का लगभग 60% लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो से आता है। जैसा कि बैटरी तकनीक विकसित होती है, इस्तेमाल की जाने वाली कोबाल्ट की मात्रा कम हो सकती है या रुक भी सकती है।

6. मानव शरीर का एटलस क्या है, और इसका महत्व क्या है? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने 'मानव (MANAV)': मानव एटलस पहल शुरू की। यह मानव शरीर के प्रत्येक ऊतक को मैप करने और विभिन्न रोगों से जुड़े ऊतकों और कोशिकाओं की भूमिकाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए एक परियोजना है।

इसमें क्या शामिल है

प्रत्येक शरीर के ऊतक सहित मानव शरीर का व्यापक नक्शा सभी उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य से बनाया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य मानव शरीर विज्ञान को दो चरणों में समझना है - सामान्य चरण और रोग चरण। डीबीटी ने दो संस्थानों की ओर से 13 करोड़ रुपये का निवेश किया है: नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च। दोनों संस्थान पुणे में स्थित हैं। निजी कंपनी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ने इस परियोजना को 7 करोड़ रुपये की सह-वित्त पोषित किया है।

परियोजना को कैसे पूरा किया जाएगा?

चयनित विषयों में अंतिम वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन नेटवर्क बनाने वाली जानकारी पर टिप्पणी करने और उपचार करने में प्रशिक्षित किया जाएगा। मानव टीम ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को टीमों के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

छात्रों के पंजीकृत होने के बाद, छात्र समूहों को शोध पत्र सौंपे जाएंगे, और विशेष उपकरणों का उपयोग करके एनोटेशन और क्यूरेशन में प्रशिक्षित किया जाएगा।

परियोजना का महत्व क्या है?

संगठित आंकड़े भविष्य के शोधकर्ताओं और चिकित्सकों और दवा विकासक के लिए सहायक होगा। परियोजना वैज्ञानिक साहित्य को पढ़ने, व्यक्तिगत ऊतकों का विश्लेषण करने और टिप्पणी करने और उपचार करने के लिए छात्र समुदाय को प्रमुख कौशल भी प्रदान करेगी। इस तरह का डेटाबेस बीमारी के कारणों का पता लगाने, विशिष्ट मार्गों को समझने और अंततः यह तय करने में काम आएगा कि शरीर का रोग चरण ऊतकों और कोशिकाओं से कैसे जुड़ा हुआ है।

(Source: https://indianexpress.com/article/explained/atlas-of-human-body-whats-in-it-and-why-5724266/)

7. DRDO ने सफलतापूर्वक ABHYAS का उड़ान परीक्षण आयोजित किया (Relevant for GS Prelims; Science & Technology)

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने आज ओडिशा के चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण रेंज से ABHYAS - हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) का सफल उड़ान परीक्षण किया।

ABHYAS क्या है?

DRDO Abhyas भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) द्वारा बनाया जा रहा एक उच्च गति वाला नष्ट होने वाला हवाई लक्ष्य (HEAT) है। हवाई लक्ष्य एक मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे आमतौर पर रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो आमतौर पर विमान-रोधी दल के प्रशिक्षण में उपयोग किया जाता है।

(Source:http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1571949&RegID=3&LID=1)

8. चेहरे की पहचान तकनीक- पक्ष और विपक्ष (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

तो, चेहरे की पहचान क्या है?

चेहरे की पहचान एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान करने और उसे अलग करने के लिए चेहरे पर विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है। पहले कैमरों से जो 1960 के दशक के मध्य तक के चेहरों को पहचान सकते थे, अब चेहरे की पहचान कई तरह से विकसित हुई है - चेहरे की 3D आकृति को देखने से लेकर त्वचा के प्रतिरूप को पहचानने तक।

सुरक्षित वातावरण या उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, शक्तिशाली कंप्यूटरों में प्लग किए गए, चेहरे निकाल सकते हैं और उन्हें एक डेटाबेस के खिलाफ मैच कर सकते हैं, या बस कुछ प्रकार के चेहरे चुन सकते हैं। जैसा कि कैमरा क्षमताओं में सुधार हुआ है, चेहरे की पहचान कम रोशनी में, और लंबी दूरी से भी संभव हो गई है।

कुछ लोग इससे असहज क्यों हैं?

पिछले एक दशक में, दुनिया भर में शहरी स्थानों को बड़े पैमाने पर निगरानी कैमरों द्वारा कवर किया गया है, जिससे चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग के लिए रास्ते खुल गए हैं। चीन, जो संभवतः दुनिया में सीसीटीवी कैमरों का सबसे व्यापक नेटवर्क है, कथित तौर पर हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भीड़ से वांछित व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग कर रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में पुलिस अधिकारियों ने अपराध के संदिग्धों की पहचान करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया है। चेहरे की पहचान के उपयोग की चिंता गोपनीयता की हानि पर चिंताओं से उपजी है, और डर है कि राज्य नागरिकों के इस मौलिक अधिकार की रक्षा करने में अनिच्छुक या अक्षम हो सकता है। नागरिक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि उनके ज्ञान के बिना लोगों की पहचान बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो सकती है।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/the-push-for-and-the-pushback-against-facial-recognition-technology-5729943/)

9. स्किमिंग: एटीएम के उपकरण कैसे डेटा चुरा सकते हैं, अपराधियों का क्लोन कार्ड बनाने में कैसे मदद करते हैं? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

पिछले हफ्ते, दिल्ली पुलिस ने पाया कि सात दिनों के भीतर तीन एटीएम में 87 खातों से 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

यह कैसे किया गया था?

स्किमर एक उपकरण है जिसे एटीएम में कार्ड प्रविष्टि स्लॉट की तरह दिखने और बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्किमर्स, जिसे आमतौर पर एक अप्रशिक्षित आंख द्वारा देखा नहीं जा सकता है, सर्किटरी है जो एटीएम कार्ड की चुंबकीय पट्टी पर डेटा को पढ़ते हैं और संग्रहीत करते हैं, यहां तक कि एटीएम भी उसी डेटा को संसाधित करता है। आमतौर पर, जालसाज़ भी कैश डिस्पेंसर के शीर्ष, जमा स्लॉट या कीबोर्ड के ऊपर जैसे अगोचर स्थानों में पिनहोल कैमरे स्थापित करते हैं। यह कार्ड के लिए पिन चुराता है। कुछ मामलों में, अपराधियों ने एक स्किमिंग डिवाइस के साथ लगे एक जालसाज़ पिन पैड का उपयोग किया है और इसे मूल पिन पैड के ऊपर रखा गया है।

स्थापना के कुछ दिनों बाद,अपराधी स्किमिंग मशीनों और कैमरों को पुनर्प्राप्त करते हैं और चोरी किए गए डेटा को इकट्ठा करते हैं, और कार्ड के लिए पिन को डीकोड करते हैं। एक मामले में,

पुलिस ने कहा, तिरुवनंतपुरम में, स्किमर और कैमरे से वायरलेस मोड में डेटा एकत्र किया गया था। चोरी किए गए डेटा का उपयोग करते हुए, अपराधी एटीएम कार्डों को क्लोन करते हैं और विभिन्न शहरों में इनका उपयोग करते हैं; अन्य समय में, वे डेटा को सहयोगियों को स्थानांतरित करते हैं, या अन्य गिरोह को डेटा बेचते हैं।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/skimming-how-devices-at-atms-can-steal-data-help-criminals-clone-cards-5731877/)

10. 5 जी की तैनाती की वैश्विक सूची में भारतीय टेलीकॉम क्यों नहीं हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

सरकार के इस दावे के बावजूद कि भारत " छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता", दुनिया भर के 294 स्थानों में 20 ऑपरेटरों द्वारा 303 5G तैनाती की सूची में कोई भी भारतीय दूरसंचार कंपनियों का आंकड़ा नहीं है।

वर्तमान में, भारत में किसी भी कंपनी या वाणिज्यिक तैनाती की पहचान नहीं की गई है।

स्विट्जरलैंड में उच्चतम तैनाती

स्विट्जरलैंड 217 शहरों में सबसे अधिक वर्तमान 5 जी तैनाती वाला देश है।

भारत में 5G की स्थिति

पिछले साल फरवरी में, मोबाइल कंपनी Airtel और चीनी उपकरण निर्माता Huawei ने भारत का पहला 5G परीक्षण किया था, जिसके दौरान 3 Gbps का उपयोगकर्ता प्रवाह क्षमता को हासिल किया गया था। लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/no-indian-telecom-companies-in-global-list-of-5g-deployments-5730146/)

11. किलोग्राम की नई माप (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

2019 के बाद से, किलोग्राम अधिक सटीक हो जाएगा। नए कलाकृतियों को प्रकृति के उन स्थिरांक से प्राप्त करना चाहिए जो सभी अन्योन्याश्रित हैं। किलोग्राम केवल उन इकाइयों में से एक था जो अभी भी एक वास्तविक वस्तु के लिए आंकी गई थी।

किलोग्राम का पूर्व माप क्या था?

1889 से, एक नमक-शेकर के आकार का सिलेंडर, 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम से बना है, जिसे ब्यूरो इंटरनेशनल डेस पोयड्स एट मेचर्स (बीआईपीएम) में रखा गया है जिसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ़ वेट्स एंड मेजर्स, पेरिस भी कहा जाता है और माप की परिभाषा के रूप में वास्तव में एक किलोग्राम वजन का होता है। 1957 से भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में भी इस माप की प्रतिकृति है और इसने संदर्भ के रूप में कार्य किया है। एनपीएल नेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम (NPK-57) का रखरखाव करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप किलोग्राम (IPK) के साथ अंशांकित किया जाता है।

माप की इकाइयाँ अब भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हुई नहीं हैं

कई मानक इकाइयां जैसे कि सेकंड, मीटर, एम्पीयर, केल्विन, मोल, कैंडेला और, किलोग्राम अब भौतिक वस्तुओं द्वारा परिभाषित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक मीटर उस माप का एक प्लैटिनम-इरिडियम बार था। 1960 में, मीटर को 1 / 299,792,458 सेकंड में वैक्यूम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया गया था।

वस्तुओं से इकाइयों को अलग करने का कारण

संक्षेप में, इकाइयों को कलाकृतियों से मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि कलाकृतियाँ टूट-फूट के अधीन हैं और इस प्रकार माप में त्रुटि का स्रोत बन सकती हैं। इसके अलावा, आईपीके थोड़ा अतिरिक्त द्रव्यमान लगाता है जब छोटे धूल कण उस पर रह जाते हैं; जब इसे साफ किया जाता है, तो यह अपने मूल द्रव्यमान को छोड़ देता है।

किलोग्राम की नई परिभाषा

2018 में, बीआईपीएम में एक वोट के बाद, 60 देशों के प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की कि किलोग्राम को प्लैंक स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। प्लैंक स्थिरांक एक ऐसी मात्रा है जो एक प्रकाश कण की ऊर्जा को उसकी आवृत्ति से संबंधित करती है। एक मशीन का उपयोग करके जिसे किबल संतुलन कहा जाता है, जिसमें विद्युत चुम्बकीय बल द्वारा एक परीक्षण द्रव्यमान का भार ऑफसेट किया जाता है, प्लांक स्थिरांक का मूल्य तय किया गया था, किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था, और नई परिभाषा के लिए 20 मई, 2019 की तारीख तय की गई थी।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/how-the-kilogram-has-changed-why-your-body-mass-has-not-5739320/)

12. PSLV-C46 ने RISAT-2B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C46) ने आज आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से RISAT-2B उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह SDSC, श्रीहरिकोटा से 72 वां लॉन्च वाहन मिशन था।

लॉन्च के बारे में

PSLV-C46 ने लिफ्ट-ऑफ के बाद लगभग 15 मिनट और 25 सेकंड में RISAT-2B को 556 किमी की कक्षा में उठा लिया। अलग होने के बाद, RISAT-2B के सौर सरणियों को स्वचालित रूप से और ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (ISTRAC) को बेंगलुरु में उपग्रह के नियंत्रण में तैनात किया गया था। आने वाले दिनों में, उपग्रह को अपने अंतिम परिचालन विन्यास में लाया जाएगा।

RISAT-2B के बारे में

RISAT-2B एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन लगभग 615 किलोग्राम है। उपग्रह का उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना है।

चंद्रयान -2 लॉन्च की योजना

इसरो अब 06 सितंबर, 2019 को अपेक्षित चंद्रमा के लैंडिंग के साथ, 09 जुलाई से 16 जुलाई, 2019 के दौरान चंद्रयान -2 ऑनबोर्ड GSLV Mk-III के लॉन्च के लिए तैयार है।

(Source: http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1572359&RegID=3&LID=1)

13. डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक आकाश-MK-1S का परीक्षण किया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने परीक्षण रेंज, चांदीपुर, ओडिशा से आकाश-MK-1S मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

आकाश Mk1S क्या है?

आकाश Mk1S स्वदेशी साधक के साथ मौजूदा AKASH मिसाइल का उन्नयन है। AKASH Mk1S एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो उन्नत हवाई लक्ष्यों को बेअसर कर सकती है।

आकाश हथियार प्रणाली क्या है?

आकाश राजेंद्र नामक एक रडार के साथ चार मध्यम-सीमा की सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों का समूह है। आकाश प्रणाली में मिसाइलें रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं। मिसाइल में बहु-लक्षित कार्य की क्षमता है। रडार आने वाली वस्तुओं का पता लगाता है और इन वस्तुओं पर मिसाइलों को फ़ायर कर दिया जाता है। आने वाली वस्तुएं लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल और प्रक्षेपात्र हो सकती हैं। मिसाइल प्रणाली 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर, 30 किमी तक के लक्ष्य को गिरा सकती है। मिसाइल की आकाश प्रणाली उपयोग में है।

आकाश प्रणाली को एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत लॉन्च किया गया था। एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Programme, आईजीएमडीपी) मिसाइलों की श्रृंखला में व्यापक अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से चलाया गया एक कार्यक्रम है। इसे 1983 में उस समय की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। आईजीएमडीपी भारत द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वाकांक्षी मिसाइल विकास कार्यक्रम है।

(Source:http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1572701&RegID=3&LID=1)

Internal Security

1. Naxalite attack in gadichiroli- गढ़चिरौली में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, पुलिस के 15 कमांडो शहीद (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Internal Security)

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मंगलवार को नक्सली हमले में पुलिस के 15 जवान शहीद हो गए। हमले में बस ड्राइवर की भी मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार देर रात इसी इलाके में नक्सलियों ने रोड निर्माण में लगे 30 वाहनों को आग लगा दी थी। नक्सली हमला कुरखेड़ा से छह किमी दूर कोरची मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के जवान निजी बस से गढ़चिरौली की ओर जा रहे थे। यह इलाका महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर है।

शहीद जवान सी-60 फोर्स के कमांडो थे

शहीद हुए जवान पुलिस की सी-60 फोर्स के कमांडो थे। इस फोर्स में 60 जवान होते हैं। इसका गठन 1992 में गढ़चिरौली के तत्कालीन एसपी केपी रघुवंशी ने किया था। इस फोर्स के कमांडो नक्सल विरोधी अभियानों के लिए ही प्रशिक्षित किए जाते हैं। ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल ने कहा- हम इस हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रभावित इलाके में अभियान चलाया जा रहा है ताकि आगे और नुकसान ना हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।

नक्सलियों ने 30 वाहन जलाए, 10 करोड़ के नुकसान की आशंका

जानकारी के मुताबिक, नक्सलियों ने कुरखेडा में मिक्सर मशीन, जनरेटर और टैंकरों समेत 30 वाहनों में आग लगाई। इसके साथ ही नक्सलियों ने कुरखेडा-कोरची मार्ग पर पेड़ काटकर रास्ता बंद कर दिया और बैनर-पोस्टर लगा दिए।बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

यहां 11 अप्रैल को हुआ चुनाव

नक्सली लोकसभा चुनाव का विरोध कर रहे हैं। हालांकि, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 11 अप्रैल को गढ़चिरौली-चिमूर सीट के गढ़चिरौली में 72% वोटिंग हुई थी।

पिछले महीने छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हमला हुआ था

नक्सलियों ने 9 अप्रैल को दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट से हमला किया था। हमले में स्थानीय भाजपा विधायक भीमा मंडावी और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी सुरक्षा में तैनात चार जवान भी शहीद हो गए थे। हमला तब हुआ जब विधायक मंडावी चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे।

(Adapted from Bhaskar.com)

2. यह Huawei कंपनी के बारे में क्या है जो दुनिया भर के देशों को सुरक्षा चिंताओं का कारण बना रहा है? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Internal Security)

चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार उपकरण कंपनी Huawei से जुड़े विवाद ने इस महीने एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री की नौकरी का दावा किया। कंपनी को दुनिया भर में संदेह के साथ देखा जाता है।

ब्रिटेन में क्या हुआ था?

प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने रक्षा सचिव गेविन विलियमसन को Huawei से संबंधित एक शीर्ष गुप्त सरकारी बैठक के बारे में प्रेस को जानकारी लीक करने पर बर्खास्त कर दिया। विलियमसन ने जानकारी लीक करने से इनकार किया है। लीक हुई जानकारी पिछले महीने लंदन के टेलीग्राफ में प्रकाशित हुई थी,जिसमें बताया गया कि मे "ने अमेरिका और उसके कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को चेतावनी के बावजूद ब्रिटेन के नए 5G नेटवर्क के निर्माण में मदद करने के लिए एक चीनी टेलीकॉम दिग्गज को अनुमति दी थी कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।"

Huawei पर आधारित संदेह क्या हैं?

ये इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि यह एक इंजीनियर द्वारा स्थापित किया गया था, जो पहले पीएलए में काम कर चुका है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य भी है। यह भी कहा जाता है कि Huawei को इसके विकास में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राज्य का समर्थन मिला है।

यह माना जाता है कि यह उन देशों के लिए Huawei द्वारा चिन्हित किए गए सुरक्षा जोखिम पर है जो इसे संचालित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, ब्लूमबर्ग ने वोडाफोन के 2009 और 2011 के सुरक्षा ब्रीफिंग दस्तावेजों के हवाले से, जो कि Huawei उपकरण का उपयोग कर रहा था, की एक रिपोर्ट के अनुसार, वोडाफोन ने सॉफ्टवेयर में छिपे हुए बैकडाउन की पहचान की थी जो Huawei को इटली में वाहक के फिक्स्ड लाइन नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच दे सकता था। रिपोर्ट के अनुसार, वोडाफोन ने 2011 में Huawei को घर के राउटर में बैकडोर को हटाने के लिए कहा था और आश्वासन प्राप्त किया था कि मुद्दे ठीक किए गए थे, लेकिन आगे के परीक्षण से पता चला कि सुरक्षा में कमजोरियां बनी हुई हैं।

ब्रिटिश सांसद रीस-मोग द्वारा उल्लिखित अमेरिका की सलाह क्या थी?

अमेरिकी सरकार ने हुआवेई को देश के नेटवर्क से प्रतिबंधित कर दिया है और यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा को भी ऐसा करने की सलाह दी है। अमेरिका का दावा है कि चीनी सरकार और उसकी सेना के साथ Huawei के करीबी संबंध इसे राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम बनाते हैं।

और कहां से Huawei मुसीबत में है?

पिछले दिसंबर में, Huawei के मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वानझू को कनाडा के अधिकारियों ने अमेरिका के अनुरोध पर गिरफ्तार किया था, जिसके साथ उसकी प्रत्यर्पण संधि है। लगभग एक हफ्ते बाद, यह सामने आया कि न्यूयॉर्क जिला के पूर्वी जिले के लिए यूएस जिला कोर्ट द्वारा अगस्त 2018 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंट बैंकों को धोखा देने के लिए एक साजिश के आरोपों पर आधारित था, जिसने उन पैसों को मंजूरी दे दी थी जो Huawei के लिए होने का दावा करता था, लेकिन वास्तव में स्काईकॉम के लिए "अनौपचारिक सहायक" के रूप में वर्णित किया गया था, जिसने कथित तौर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को अमेरिकी उपकरण बेचने का प्रयास किया था।

दुनिया भर में प्रतिक्रिया

अन्य देशों में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 5जी नेटवर्क के रोलआउट में Huawei के उपकरणों के उपयोग को अवरुद्ध कर दिया है। अप्रैल 2018 में, अमेरिकी नियमों की घोषणा की गई थी, जिसने किसी भी कंपनी से खरीद करने वाली सरकारी कंपनियों को सुरक्षा के लिए खतरा माना था। जुलाई 2018 में, अमेरिका ने चीनी कंपनी ZTE पर प्रतिबंध के एक हिस्से के रूप में प्रतिबंध हटा दिया, जबकि Huawei उपकरण पर प्रतिबंध जारी है। अगस्त 2018 में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए Huawei और ZTE को 5G नेटवर्क के लिए दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित कर दिया। अपने नवंबर में, न्यूजीलैंड की सुरक्षा सेवाओं ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं पर एक स्थानीय कंपनी को मोबाइल नेटवर्क किट की आपूर्ति से Huawei को अवरुद्ध कर दिया था। यूके में, दूरसंचार सेवा प्रदाता बीटी ने पिछले साल पुष्टि की थी कि यह MI6से चिंताओं के बाद, अपने 4 जी नेटवर्क के प्रमुख क्षेत्रों से Huawei उपकरण निकाल रहा है।

इस विवाद में भारत कहां खड़ा है?

भारत में, Huawei के बारे में दूरसंचार ऑपरेटरों में भ्रम पैदा हो गया है कि वे 5G नेटवर्क पर स्विच करने पर क्या करें। Huawei नेटवर्क उपकरण का उपयोग वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल द्वारा कई सर्किलों में किया गया है, लेकिन चीनी कंपनी को अभी भी 5G परीक्षणों पर कोई अनुमति नहीं मिली है। Huawei और ZTE को शुरू में परीक्षणों में भाग लेने से रोक दिया गया था।

Huawei विश्व स्तर पर कितना बड़ा है?

आज, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता है, जो Apple से अधिक और केवल सैमसंग से पीछे है। अनुसंधान फर्म काउंटरपॉइंट के अनुसार, 2019 की पहली तिमाही में यह Apple से आगे निकल गया, जिसमें कहा गया कि Huawei ने 59.1 मिलियन स्मार्टफोन भेजे। सैमसंग ने 72.0 मिलियन यूनिट के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा।

भारत में Huawei

2000 में Huawei ने भारत में अपने पैर जमा लिए, दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ काम करके उन्हें नेटवर्क उपकरण मुहैया कराया। हालांकि इस खंड में एरिक्सन और नोकिया नेटवर्क जैसी अन्य कंपनियों के साथ भीड़ थी, लेकिन भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में होने वाले उछाल ने इसे Huawei को भी समायोजित करने में सक्षम बनाया। चीन के बाहर Huawei का पहला अनुसंधान और विकास केंद्र भारत में स्थापित किया गया था, जो अपने घरेलू मैदान के बाहर सबसे बड़ा है। भारत में नेटवर्क संचालन शुरू करने के दस साल बाद, Huawei ने 2010 में अपने स्मार्टफोन की पहली लाइन लॉन्च की। हालाँकि, इसके उपकरण, जो अब ऑनर ब्रांड के तहत बेचे जाते हैं, अपने चीनी समकक्षों जैसे कि Xiaomi, Oppo और Vivo की तुलना में कम बिक्री दर्ज की गई। 2018 की जनवरी-मार्च तिमाही में पहली बार भारतीय स्मार्टफोन बाजार में ब्रांड शीर्ष पांच रैंकिंग से नीचे गिर गया।

(Source: https://indianexpress.com/article/explained/simply-put-why-govts-are-wary-of-huawei-china-5726039/

Disaster Management

1. Cyclone Fani में 1 करोड़ 48 लाख हुए प्रभावित, 37 लोगों की गई जान (Relevant for GS Prelims and GS Mains Paper III; Disaster Management)

ओडिशा में फणि तूफान के गुजर जाने के पांच दिन बाद भी राज्य के कई प्रभावित इलाकों में बिजली, पानी और दूरसंचार व्यवस्था पूरी तरह ठप है। साथ ही लोगों के सामने भोजन और पीने पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इसे लेकर चारों ओर हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई है। इन सबके बीच ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता संगम महापात्रा ने बताया कि इस चक्रवात में 5.8 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि फणि चक्रवात से ओडिशा के 155 ब्लॉकों में 1 करोड़ 48 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, लगभग 5.8 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब तक 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। मंगलवार से राज्य में प्रभावित लोगों को राज्य सरकार की ओर से राहत सामग्री का वितरण शुरू कर दिया। राशन कार्ड धारी पीड़ितों को 20 हजार रुपया, 50 किलो चावल और प्लास्टिक का तिरपाल बांटा जा रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वयं मंगलवार को पुरी में इसकी शुरुआत की।

SOURCE: https://www.jagran.com/

2. सूरत त्रासदी के लिए जवाबदेही तय करें, और अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल को देशव्यापी अपडेट करें (Relevant for GS Mains Paper III; Disaster Management)

सूरत कोचिंग सेंटर में लगी आग

आग की घटना में 22 किशोरों की मौत हो गई है। आग से सीढ़ियां नष्ट होने के कारण इमारत में किशोर फंस गए। आग से बचने के लिए इमारत से कूदने के बाद चार की मौत हो गई।

अधिकारियों द्वारा कार्रवाई

पुलिस ने सूरत कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया है। सरथाना क्षेत्र में वाणिज्यिक तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के दो बिल्डर पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं (भारतीय दंड संहिता) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

भारत का खराब अग्नि सुरक्षा रिकॉर्ड

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2015 के दौरान सार्वजनिक और आवासीय दोनों भवनों में लगी आग में देश भर में 17,700 लोगों की मौत के बाद अग्नि सुरक्षा पर भारत का निराशाजनक रिकॉर्ड परिलक्षित होता है। समय-समय पर, हाई-प्रोफाइल मामले जैसे कि दिल्ली में उपहार सिनेमा धमाका, जिसने 1997 में 59 लोगों की जान ले ली, और 2004 में तमिलनाडु के कुंभकोणम स्कूल में आग लग गई जिसमें 94 बच्चों ने देश को झकझोर दिया। लेकिन ये भी सरकारों को आग सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं।

मौजूदा त्रासदी के लिए किसे दोषी ठहराया जाए?

ये युवा भारतीय अनियोजित शहरीकरण के नवीनतम शिकार हैं जिन्हें शहर की सरकारों ने पैदा किया है और जिन्हें अदालतें गंभीर दंड के बिना छोड़ देती हैं। सूरत की आग को एक दुर्घटना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिल्डर को जोखिमों पर नोटिस दिए जाने की सूचना है, लेकिन अग्निशमन विभाग द्वारा पीछा नहीं किया गया है। सिविक अधिकारियों ने अक्षम्य उदासीनता का प्रदर्शन किया है, क्योंकि पिछले साल के अंत में शहर के एक अन्य कोचिंग सेंटर में दो मौतें हुई थीं।

क्या किया जाए?

त्रासदी को सार्वजनिक भवनों की व्यापक समीक्षा के लिए नेतृत्व करना चाहिए था। कोचिंग सेंटर के वाणिज्यिक भवन के लिए आवास और शहरी नियोजन अधिकारियों की भूमिका में आने की अनुमति आपदा की वर्तमान जांच को स्वीकृत योजना से किसी भी विचलन में जाना चाहिए। कुछ अधिकारियों को निलंबित करने और भवन मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज करने से परे, मंजूरी और प्रवर्तन अधिकारियों का एक उदाहरण बनाने की आवश्यकता है। अटूट संदेश यह होना चाहिए कि भारतीय जवाबदेही की मांग करें।

आग जोखिम और सार्वजनिक देयता के खिलाफ सभी सार्वजनिक भवनों के लिए अनिवार्य बीमा को लागू करने से वास्तुकारों और बिल्डरों को सुरक्षा के सवाल पर संपर्क करने का तरीका बदल सकता है, चूंकि बीमाकर्ता को निर्माण योजनाओं के साथ जोखिम और अनुपालन में कमी करने की आवश्यकता होगी।

(Source:https://www.thehindu.com/opinion/editorial/fire-and-laissez-faire/article27256049.ece)

Modern History

1. मानवतावादी, नारीवादी: ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्यों मायने रखते हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Modern History)

ईश्वरचंद्र विद्यासागर

ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय के घर 26 सितंबर, 1820 को मिदनापुर जिले के बिरसिंह गाँव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

बंगाली नाटक के 19 वीं सदी के अग्रणी माइकल मधुसूदन दत्त ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को "एक प्राचीन ऋषि की प्रतिभा और ज्ञान, एक अंग्रेज की ऊर्जा और एक बंगाली मां के दिल" के रूप में वर्णित किया।

अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद, ईश्वरचंद्र कलकत्ता चले गए, जहाँ उन्होंने संस्कृत व्याकरण, साहित्य, वेदांत दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान और हिंदू कानून का अध्ययन किया और 21 वर्ष की आयु में विद्यासागर ने विज्ञान का महासागर की उपाधि प्राप्त की। निजी तौर पर, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और दर्शन का अध्ययन किया। जब वे मुश्किल से 30 वर्ष के थे, तब विद्यासागर को कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था।

द ओशन ऑफ लर्निंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक बच्चे के रूप में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की थी, "दया सागर" भी था - करुणा का महासागर - जो सचमुच गरीब और बेसहारा लोगों को देखकर रोता है, और कहा जाता है कि उसने अपना वेतन और छात्रवृत्ति उनके कल्याण पर खर्च किया है। लेकिन उनका सबसे स्थायी योगदान पारंपरिक उच्च जाति के हिंदू समाज के शिक्षाविद् और सुधारक के रूप में था। उनके सुधार का ध्यान महिलाओं पर था - उन्होंने अपना पूरा जीवन बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने और विधवा विवाह की शुरुआत करने के लिए प्रयास किया।

उनके बंगाली प्राइमर, बोर्नो पोरिचोय ने आधुनिक बंगाली वर्णमाला का पुनर्निर्माण किया, और 1891 में उनकी मृत्यु के 125 से अधिक वर्षों बाद, भाषा सीखने और लिखने के लिए लगभग हर बच्चे को इससे परिचित कराया जाता है।

महिलाओं के लिए सुधार

1850 में लिखे गए एक पत्र में, विद्यासागर ने सामाजिक, नैतिक और स्वच्छता के मुद्दों की ओर इशारा करते हुए 10 या उससे कम उम्र की लड़कियों से शादी करने की प्रथा पर जोरदार हमला किया और इसकी वकालत करने वाले धर्म शालाओं की वैधता को खारिज कर दिया। 1855 में, उन्होंने हिंदू विधवाओं के विवाह पर अपने दो प्रसिद्ध ट्रैक्स लिखे, युक्ति और तर्क के आधार पर यह दिखाते हुए कि पूरे स्मृति साहित्य (सूत्र और शास्त्र) में पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था। विधवा पुनर्विवाह के अभियान के साथ-साथ, विद्यासागर ने बहुविवाह के खिलाफ अभियान चलाया। 1870 के दशक में, विद्यासागर ने बहुविवाह की दो शानदार आलोचनाएं करते हुए सरकार को तर्क दिया कि चूंकि पवित्र ग्रंथों द्वारा बहुविवाह को मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए इसे कानून द्वारा दबाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

स्थायी प्रभाव

विधवा पुनर्विवाह पर विद्यासागर के पहले पर्चे की दो हज़ार प्रतियाँ एक हफ्ते में बेच दी गई थीं, और एक और 3,000 की पुनर्मुद्रण भी बेची गई थी। ये उस समय की अभूतपूर्व बिक्री के आंकड़े थे।

14 अक्टूबर, 1855 को, विद्यासागर ने भारत सरकार से याचिका दायर करते हुए कहा कि "हिंदू विधवाओं की शादी में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और ऐसे सभी विवाहों के मुद्दे को वैध घोषित करने के लिए एक कानून पारित करने की औचित्य पर विचार करें"।

16 जुलाई, 1856 को, हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम, जिसे अधिनियम XV के रूप में जाना जाता है,पारित किया गया था। विद्यासागर से प्रेरित होकर, कई साहित्यिक पुरुषों ने विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत करते हुए नाटक तैयार किए, खासकर बंगाल और अन्य जगहों पर। वास्तव में, हिंदू महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ शुरुआती और सबसे बुनियादी सुधारों का बीड़ा उस आदमी ने उठाया, जिसका पर्दाफाश मंगलवार को उसके द्वारा बनाए गए कॉलेज में हुए हमले में हुआ था।

Miscellaneous

1. Possible pugmarks of Yeti seen- भारतीय सेना को हिमालय में 32 इंच लंबे पगमार्क मिले, अनुमान- येति के निशान हो सकते हैं (Relevant for GS Prelims)

भारतीय सेना को हिमालय में 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े पदचिह्न मिले हैं। माना जा रहा है कि ये हिममानव या येति के हो सकते हैं, जिनका जिक्र पौराणिक कथाओं में किया जाता रहा है। सेना की ओर से बर्फ पर पदचिह्न की तस्वीरें सोमवार को ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई। आर्मी के पवर्तारोही दल को ये रहस्यमयी पदचिह्न 9 अप्रैल को मकालू बेस कैम्प के पास नजर आए थे। यह कैम्प 5250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पैरों के ये निशान मिलने की जगह नेपास के माकालू वरुण नेशनल पार्क के पास स्थित है।

सेना का कहना है कि टीम के लौटने पर पदचिह्न की तस्वीरों का निरीक्षण किया गया। तस्वीरें ट्विटर पर साझा की गई ताकि वैज्ञानिक तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा सके। दूसरी ओर, आर्मी के तस्वीरें पोस्ट करने के बाद येति के अस्तित्व को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। यूजर्स ने सवाल उठाए कि कहीं यह प्रैंक तो नहीं। सिर्फ पैरों के निशान ही क्यों शेयर किए? कुछ लोगों ने कहा कि शायद भारतीय सेना का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया।

येति को लेकर अलग-अलग दावे

हिमालय में येति की मौजूदगी को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि येति इंसान और वानर की तरह दिखते हैं, जो सामान्य मानव से काफी बड़े होते हैं। इन्हें हिमालय का असली निवासी माना जाता है। हालांकि, अभी तक येति की मौजूदगी के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं।

(Adapted from Bhaskar.com)

2. आम्रपाली ग्रुप ने फर्स्ट डिग्री क्राइम किया, धोखाधड़ी में शामिल प्रभावशाली लोगों पर केस चलेगा (Read only for understanding)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली ग्रुप पर तल्ख टिप्पिणयां कीं। अदालत ने कहा, 'आम्रपाली समूह ने घर खरीदने वाले हजारों लोगों से धोखाधड़ी कर 'फर्स्ट डिग्री क्राइम' किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धोखाधड़ी के पीछे कितने प्रभावशाली लोग हैं। उन्हें नामजद किया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी गड़बड़ नहीं करने के ग्रुप के दावे खारिज कर दिए। अदालत ने कहा कि ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स के लिए हमारा संदेश स्पष्ट है।

'हमें आम्रपाली के ऑडिटर्स का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए था'

1. जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब आम्रपाली की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट्स गीता लूथरा और गौरव भाटिया ने कहा, 'ग्रुप ने कोई गलती नहीं की है। 3,500 करोड़ रुपए को दूसरे कामों पर खर्च नहीं किया गया है, जैसा कि कोर्ट की ओर से नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने दावा किया है।'

2. बेंच ने कहा, 'वह कंपनी के संदिग्ध आचरण को देखते हुए 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को दूसरी जगह लगाए जाने के मामले में उसकी दलील विश्वास नहीं कर सकती। कंपनी ने घर खरीदने वालों, बैंकों और अधिकारियों समेत हर किसी के साथ धोखाधड़ी की। आपने फर्जीवाड़े की सभी हदें पार की दीं।'

3. अदालत ने कहा, 'आपने घर खरीदने वाले हजारों लोगों को ठगकर 'फर्स्ट डिग्री क्राइम' किया है। हमें फर्जीवाड़े को लेकर आम्रपाली के स्टैचटॉरी ऑडिटर्स का लाइसेंस बहुत पहले ही रद्द कर देना चाहिए था। हम ओपन कोर्ट में कह रहे हैं कि इस धोखाधड़ी के पीछे प्रभावशाली लोग हैं। हालांकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे कितने शक्तिशाली हैं। हम उन्हें नामजद करेंगे और उन पर मुकदमा चलाएंगे। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे।'

(Adapted from Bhaskar.com)

3. 3 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के, इन्होंने अपनी कंपनी का मुनाफा और मार्केट कैप बढ़ाया (Relevant for GS Prelims)

दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे ने पिछले शनिवार कंपनी की एजीएम में संकेत दिए कि भारतीय मूल के अजित जैन उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। बफे ने कहा कि ग्रेगरी एबल और अजित जैन भविष्य में शेयरहोल्डर के सवालों के जवाब देने के लिए उनके साथ मंच साझा करेंगे। पिछले साल दोनों को प्रमोट कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया था। अगर अजित जैन बर्कशायर हैथवे के सीईओ बनते हैं, तो वे भारतीय मूल के ऐसे चौथे व्यक्ति होंगे जो किसी नामी अमेरिकी कंपनी के प्रमुख बनेंगे। अभी सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई गूगल और शांतनु नारायण एडोब के सीईओ हैं।

अजित के सीईओ बनने की ज्यादा संभावना, क्योंकि बफे खुद उनकी तारीफ कर चुके

ओडिशा में जन्मे अजित जैन (67) की बर्कशायर हैथवे का चेयरमैन बनने की ज्यादा संभावना है। बफे (88) खुद कई मौकों पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। अजित 1986 में बर्कशायर हैथवे से जुड़े थे। 2008 में बफे ने अपनी चिट्ठी में खुलासा किया था कि उन्होंने अजित के माता-पिता को पत्र भेजकर पूछा था कि उनके घर में अजित जैसा कोई और होनहार भी हो तो उसे भेजें। इसके अलावा बफे ने एक बार कहा था कि मेरे मुकाबले अजित ने बर्कशायर हैथवे को ज्यादा फायदा पहुंचाया है। मैं वाकई अजित के प्रति एक भाई या बेटे जैसा अपनापन महसूस करता हूं। वहीं, 2017 में बफे ने कंपनी को लिखे एनुअल लेटर में कहा था कि अगर आपको कभी अजित के लिए मुझे हटाना भी पड़े तो जरा भी हिचकना नहीं।

3 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों में भारतीय मूल के ही सीईओ, शांतनु नारायण ने सबसे ज्यादा 436% मार्केट कैप बढ़ाई

सीईओ	कार्यकाल	मार्केट कैप	रेवेन्यू	प्रॉफिट
सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट	5 साल	214%	26%	-25%
स्टीव बॉल्मर,माइक्रोसॉफ्ट	14 साल	-48%	28%	134%
सुंदर पिचाई, गूगल	4 साल	82%	83%	88%
लैरी पेज, गूगल	4 साल	150%	97%	68%
शांतनु नारायण, एडोब	12 साल	436%	186%	260%
ब्रूस चीजेन, एडोब	7 साल	67%	186%	278%

माइक्रोसॉफ्ट: सत्या नडेला सीईओ बने तो 5 साल में कंपनी का मार्केट कैप 214% बढ़ा

फरवरी 2014 में स्टीव के इस्तीफे के बाद सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। उस वक्त कंपनी का मार्केट कैप 306 अरब डॉलर था। वर्तमान में मार्केट कैप 961 अरब डॉलर है। पिछले महीने ही माइक्रोसॉफ्ट 1 लाख करोड़ डॉलर मार्केट वैल्यू का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की चौथी कंपनी बनी थी। नडेला के पांच साल के कार्यकाल में मार्केट कैप 214% बढ़ा। इसी दौरान रेवेन्यू भी 26% बढ़कर 110.3 अरब डॉलर पहुंच गया। हालांकि, नडेला के कार्यकाल में कंपनी के मुनाफे में कमी देखी गई।

साल	रेवेन्यू	प्रॉफिट	मार्केट कैप
2000	22.9	9.4	590
2014	86	22	306
2018	110.3	16.5	961 (8 मई 2019)

(आंकड़े अरब डॉलर में/ सोर्स- कंपनी फाइलिंग)

अप्रैल 1975 में बनी माइक्रोसॉफ्ट में 2000 से लेकर 2014 तक स्टीव बॉल्मर सीईओ रहे। जब उन्होंने कंपनी की बागडोर संभाली तब मार्केट कैप 590 अरब डॉलर था। जब वे इस पद से हटे तो मार्केट कैप 306 अरब डॉलर रह गया। यानी स्टीव के 14 साल के कार्यकाल में माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप 48% तक गिर गया। हालांकि, इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई।

पिचाई के सीईओ बनने के बाद गूगल का रेवेन्यू 83% और मुनाफा 88% बढ़ा

1998 में शुरू हुई गूगल के पहले सीईओ लैरी पेज थे। उन्होंने 2001 में इस्तीफा दे दिया। 2001 से 2011 तक एरिक श्मिट सीईओ रहे। 2011 में लैरी पेज दोबारा सीईओ बने। उस वक्त कंपनी का मार्केट कैप 180 अरब डॉलर के आसपास था। रेवेन्यू 37.9 अरब डॉलर और मुनाफा 9.7 अरब डॉलर था। उन्होंने 2015 में इस्तीफा दिया और सुंदर पिचाई सीईओ बने। तब गूगल का मार्केट कैप 450 अरब डॉलर, रेवेन्यू 75 अरब डॉलर और मुनाफा 16.3 अरब डॉलर था। यानी, लैरी पेज के साढ़े चार साल के कार्यकाल में मार्केट कैप 150%, रेवेन्यू 97% और मुनाफा 68% बढ़ा।

कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 816 अरब डॉलर है। यानी सुंदर पिचाई के 4 साल के कार्यकाल में मार्केट कैप में 82% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि, कंपनी का 2018 में रेवेन्यू 136.8 अरब डॉलर और मुनाफा 30.7 अरब डॉलर रहा। इस हिसाब से 2015 की तुलना में रेवेन्यू 83% और मुनाफा 88% बढ़ा।

साल	रेवेन्यू	प्रॉफिट	मार्केट कैप
2011	37.9	9.7	180
2015	75	16.3	450
2018	136.8	30.7	816 (8 मई 2019)

(आंकड़े अरब डॉलर में/ सोर्स- कंपनी फाइलिंग)

शांतनु 2007 में एडोब के सीईओ बने

अमेरिकी कंपनी एडोब के 2000 से लेकर 2007 तक ब्रूस चीजेन सीईओ रहे। इस दौरान एडोब का मार्केट कैप 15 अरब डॉलर से बढ़कर 25 अरब डॉलर हुआ। यानी, 7 साल में मार्केट कैप में 67% की बढ़ोतरी हुई। नवंबर 2007 में शांतनु नारायण एडोब के सीईओ बने। 12 साल के कार्यकाल में कंपनी का मार्केट कैप 436% बढ़कर 134 अरब डॉलर पहुंच गया। अगर हर साल मार्केट कैप में आए औसत उछाल को देखें तो ब्रूस के कार्यकाल में मार्केट कैप 10%, जबकि नारायण के कार्यकाल में हर साल 37% बढ़ा।

साल	रेवेन्यू	प्रॉफिट	मार्केट कैप
2002	1.1	0.191	15
2007	3.1	0.723	25
2018	9	2.6	134 (8 मई 2019)

(आंकड़े अरब डॉलर में/ सोर्स- कंपनी फाइलिंग)

(Source: https://www.bhaskar.com**)**

4. योगेश चंदर देवेश्वर का निधन (Relevant for GS Prelims)

योगेश चंदर देवेश्वर (4 फरवरी 1947 - 11 मई 2019) एक भारतीय व्यापारी थे।

कैरियर प्राप्ति

वह आईटीसी लिमिटेड के सबसे लंबे समय तक(1996-2017) सेवा देने वाले अध्यक्ष थे। संजीव पुरी उनके उत्तराधिकारी बने। वह भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक भी थे, नेशनल फाउंडेशन फ़ॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सदस्य और नेशनल काउंसिल ऑफ़ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के गवर्निंग बॉडी के सदस्य थे।

प्रारंभिक जीवन

श्री देवेश्वर आईआईटी दिल्ली और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र थे। वह 1968 में आईटीसी से जुड़े।

1991 से 1994 के बीच, उन्हें सरकार द्वारा एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

आईटीसी में योगदान

उनके नेतृत्व में, आईटीसी, भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई, जो देश के सबसे बड़े पेपरबोर्ड और पैकेजिंग कंपनी और किसान-सशक्तीकरण में अपने व्यापक व्यवसायिक व्यवसाय के माध्यम से सक्रिय है। यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी होटल श्रृंखला भी है।

(Source:wikipedia.com)

5. पहला अपाचे हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से IAF को सौंप दिया गया (Relevant for GS Prelims)

पहला अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से 19 मई को अमेरिका के मेसा, एरिजोना में बोइंग उत्पादन सुविधा में भारतीय वायु सेना को सौंप दिया गया था। IAF ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार और मेसर्स बोइंग लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

अपाचे हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता

हेलीकॉप्टर को शामिल करना भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर के बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हेलीकॉप्टर को IAF की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है और पहाड़ी इलाकों में इसकी महत्वपूर्ण क्षमता होगी। हेलीकॉप्टरों में डेटा नेटवर्किंग के माध्यम से हथियार प्रणालियों से युद्ध के मैदान की तस्वीर को प्रसारित करने और प्राप्त करने की क्षमता है। इस प्रकार, हेलीकॉप्टर सटीक हमलों के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(Source: http://pib.nic.in/)

6. बेलुगा व्हेल क्या है? यह समाचारों में क्यों है? (Relevant for GS Prelims)

बेलुगा व्हेल

बेलुगा व्हेल के बारे में

बेलुगा व्हेल आमतौर पर ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस के आसपास बर्फीले पानी में रहती हैं। वे 6 मीटर तक बढ़ सकते हैं, और डॉल्फ़िन से संबंधित हैं।

उनके सैन्य उपयोग के बारे में

पिछले कुछ हफ्तों में, नॉर्वे से आर्कटिक में एक बेलुगा व्हेल तैराकी ने अटकलें लगाई हैं कि यह रूस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा एक जासूस है। यह पालतू है, मनुष्य को इसे पालतू बनाने की अनुमति देता है, और एक वीडियो से पता चलता है कि यह एक ऐसी महिला को फोन लौटाता है जो गलती से समुद्र में गिर गया था।

सेना में समुद्री स्तनधारी

अन्य समुद्री स्तनधारियों को सैन्य उपयोग के लिए जाना जाता है। एक डॉल्फिन पानी के नीचे की वस्तुओं की पहचान कर सकता है जो मानव गोताखोरों के लिए अदृश्य होगा। उन्होंने फारस की खाड़ी युद्ध और इराक युद्ध में खानों को साफ करने की भी मदद की है।

तो, क्या यह एक जासूस है?

जबकि रूस ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, लेकिन रूस में व्हेल को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है।

(Source: https://indianexpress.com/article/explained/can-a-beluga-whale-be-trained-as-a-military-spy-5726046/)

7. भारत की पहली पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो प्रणाली (Relevant for GS Prelims)

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोलाबा-बांद्रा-सीपेज़ मेट्रो रेल, जो भारत की पहली पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो प्रणाली है, के लगभग 33.5 किलोमीटर के मार्ग की आधी खुदाई को पूरा किया है। यह भारत की दूसरी अन्तर्जलीय मेट्रो सुरंग भी होगी जो मुंबई में मीठी नदी के नीचे से गुजरेगी।

यह सुरंग बनाने में मील पत्थर कैसे है?

यहां पर खतरा गहराई का नहीं है। यहां चुनौतियां हैं जो जल-निकाय के नीचे सुरंग बनाने के साथ आती हैं। एक निर्माणाधीन सुरंग खंड में कीचड़ और पानी घुसने की संभावना है। भारत में एक बड़ी पारगमन परियोजना के लिए एकमात्र अन्य अन्तर्जलीय सुरंग, कोलकाता में हुगली के नीचे दो साल पहले पूरी हुई।

चट्टानों के माध्यम से खुदाई करने वाली सुरंग बोरिंग मशीन का विशिष्ट चित्रण।

(Source: https://indianexpress.com/article/explained/tunnelling-under-the-mithi-how-mumbai-metro-is-meeting-the-challenge-5727871/)

8. भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में रुझान: लैंसेट अध्ययन (Relevant for GS Prelims)

द लांसेट ग्लोबल हेल्थ में एक नए अध्ययन में भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत को चिह्नित किया गया है, जो 2015 में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक था। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि अमीर और गरीब राज्यों के बीच बाल मृत्यु दर में बड़ी असमानता पाई गई है।

भारत में कुल बाल मृत्यु दर

जबकि भारत ने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच वार्षिक मृत्यु दर में 2000 में 2.5 मिलियन (प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 90.5) से 2015 में 1.2 मिलियन (2.5 मिलियन जीवित बच्चों में से, या 47.8 प्रति 1,000 में से) से कमी की है। यह अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा था।

राज्यों के बीच असमानता

राज्यों में, उच्चतम मृत्यु दर, असम में प्रति 1,000 पर 73.1, गोवा के 9.7 के सात गुना से अधिक थी। क्षेत्रों के बीच, मृत्यु दर 29.7 प्रति 1,000 (दक्षिण) के निम्न से 63.8 (पूर्वोत्तर) तक थी।

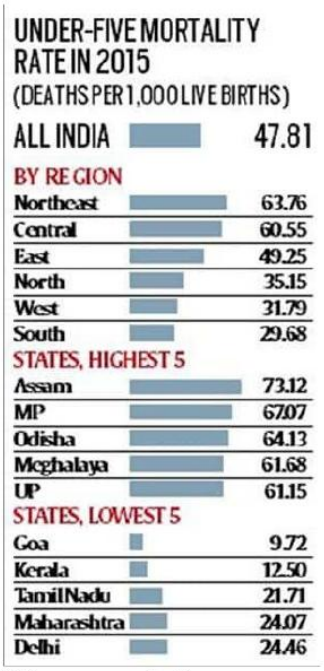

विभिन्न राज्यों में बाल मृत्यु दर

उच्च मृत्यु दर का कारण

2000 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को 2015 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को 1990 के आंकड़े के एक तिहाई तक कम करना था। भारत के लिए, इसका मतलब होगा कि प्रति 1,000 जीवित जन्मे बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 39 करना है। विश्लेषण में पाया गया कि हालांकि ज्यादातर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मौतें पहले से ही जटिलताओं के कारण हुईं, उच्च-मृत्यु दर वाले राज्यों में मृत्यु के कारणों के रूप में रोकथाम योग्य संक्रामक रोगों को प्रमुखता से दिखाया गया है।

(Source:https://indianexpress.com/article/explained/under-5-mortality-in-india-study-flags-disparity-among-states-5729952/)

9. SIMBEX-19 (Relevant for GS Prelims)

SIMBEX वार्षिक सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। यह पहली बार 1993 में आयोजित किया गया था। SIMBEX-19 हाल ही में आयोजित किया गया था। अभ्यास दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया था।

(Source:http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1572249&RegID=3&LID=1)

10. क्यों Huawei के साथ Google के व्यापार को निलंबित करने की खबर महत्वपूर्ण है (केवल समझने के लिए पढ़ें)

Google Huawei के साथ कुछ व्यापार को निलंबित कर रहा है, और यह चीनी कंपनी और उसके उप-ब्रांड, Honor द्वारा बनाए गए स्मार्टफोन पर एंड्रॉइड के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

Google ने क्या किया है?

रॉयटर्स के अनुसार, Google ने व्यवसाय को निलंबित कर दिया है कि "जिससे Huawei के साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी सेवाओं के हस्तांतरण की आवश्यकता है"। वास्तव में, Google ने Huawei के Android लाइसेंस को रद्द कर दिया है।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा एक व्यापार को ब्लैकलिस्ट में जोड़ने के बाद Google ने कार्रवाई की, जो अमेरिकी कंपनियों को सरकार से "स्पष्ट अनुमोदन" के बिना ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के साथ व्यापार करने से रोकती है।

लोग जिनके पास Huawei फोन है, उनका क्या होगा?

जब तक Huawei को "एंटिटी लिस्ट" से हटा नहीं दिया जाता है, एक अच्छा मौका है कि इसके फोन भविष्य में जीमेल, यूट्यूब और क्रोम जैसी एंड्रॉइड की मालिकाना सेवाओं और ऐप को चलाने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि एंड्रॉइड अभी के लिए काम करना जारी रखेगा, यह स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या होता है - जिसमें मौजूदा Huawei फोन कभी भी फिर से एंड्रॉइड अपडेट प्राप्त करेंगे। एंड्रॉइड में मासिक सुरक्षा अपडेट और वार्षिक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हैं। Huawei अभी भी एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से एंड्रॉइड का उपयोग कर सकता है, लेकिन मालिकाना सेवाओं को Google से वाणिज्यिक लाइसेंस के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भविष्य के Huawei फोन Google और Android सेवाओं के साथ नहीं आ सकते हैं।

Huawei ने स्थिति पर क्या कहा है?

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा: "Huawei सभी मौजूदा Huawei और Honor स्मार्टफोन और टैबलेट उत्पादों को सुरक्षा अपडेट और बिक्री के बाद सेवा प्रदान करना जारी रखेगा, जो कि बेची गई हैं और जो अभी भी वैश्विक स्तर पर स्टॉक में हैं।" यह पुष्टि नहीं करता कि क्या मौजूदा Huawei फोन को एंड्रॉइड के अगले संस्करण में अपडेट किया जाएगा, और क्या भविष्य के फोन ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे। Huawei फ़ोन, Android के शीर्ष पर, कंपनी का अपना OS EMUI भी चलाते हैं। यह अपने स्वयं के अनूठे उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और व्यक्तिगत ऐप के साथ आता है। यह एंड्रॉइड की दुनिया में एक आम दृष्टिकोण है - कंपनियां अक्सर अपने स्वयं के उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को एंड्रॉइड में जोड़ देती हैं, हालांकि कोर Google सेवाएं सभी उपकरणों का हिस्सा हैं।

Huawei कितना मजबूत है?

2019 की पहली तिमाही में, Huawei दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन गया। रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन (IDC) के नंबरों के अनुसार, स्मार्टफोन विक्रेताओं की सूची में केवल Samsung से पीछे, Huawei Apple से आगे है। कंपनी ने तिमाही में 50.3% की साल दर साल वृद्धि देखी, जिसमें 59.1 मिलियन यूनिट्स को भेज दिया गया।

11. 200 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाला जहाज (केवल समझने के लिए पढ़ें)

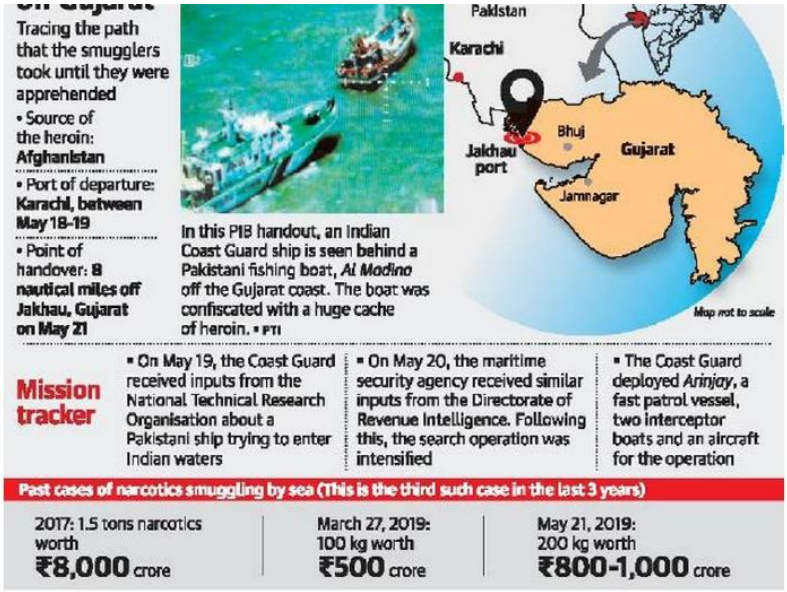

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने गुजरात के तट से एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने के जहाज से हेरोइन को जब्त किया, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में रु 800 और रु 1000 करोड़ के बीच होने का अनुमान है।

(Source:https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/pakistani-fishing-vessel-caught-after-hot-pursuit-200-kg-heroin-seized/article27201699.ece)

12. आईआईटी-मद्रास के पूर्व छात्र, एक पूर्व-Google, अमेज़ॅन कर्मचारी, को वॉलमार्ट के नए सीटीओ के रूप में नियुक्त किया गया (Relevant for GS Prelims)

सुरेश कुमार के बारे में

वॉलमार्ट ने कहा कि इसने IIT मद्रास के स्नातक और पूर्व कार्यकारी सुरेश कुमार को मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की है।

उन्हें क्यों नियुक्त किया गया है?

उनकी नियुक्ति तब हुई जब अमेज़न के साथ अधिक प्रभावी प्रतिस्पर्धा करने के लिए वॉलमार्ट अपने ई-कॉमर्स व्यवसाय में प्रमुख निवेश कर रहा है।

(Source:https://www.livemint.com/companies/news/iit-madras-alumni-an-ex-google-amazon-employee-appointed-new-cto-of-walmart-1559064770745.html)

13. भारतीय लेखिका एनी जैदी ने $100,000 वैश्विक पुस्तक पुरस्कार जीता)Relevant for GS Prelims)

भारतीय लेखक एनी जैदी को $100,000 नाइन डॉट्स पुरस्कार के 2019 विजेता के रूप में घोषित किया गया था। मुम्बई स्थित जैदी, एक स्वतंत्र लेखक, जिनके काम में रिपोर्ताज, निबंध, लघु कथाएँ, कविताएँ और नाटक शामिल हैं, उनके निबंध 'ब्रेड, सीमेंट, कैक्टस' के लिए जीते गए।

नौ डॉट्स पुरस्कार

नौ डॉट्स पुरस्कार रचनात्मक सोच के लिए एक पुरस्कार है जो समकालीन सामाजिक मुद्दों से निपटता है। प्रवेशकों को 3,000 शब्दों में एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा जाता है, जिसमें विजेता को अपने विचारों पर विस्तार करने वाली एक छोटी पुस्तक लिखने के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। पुरस्कार का उद्देश्य आधुनिक दुनिया के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए अभिनव सोच को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और संलग्न करना है। पुरस्कार का नाम नौ डॉट्स पहेली का संदर्भ देता है एक पार्श्व सोच पहेली जिसे केवल बॉक्स - के बाहर सोचकर हल किया जा सकता है।

पुरस्कार के लिए प्रविष्टियों को नौ डॉट्स पुरस्कार बोर्ड के 11 सदस्यों द्वारा गुमनाम रूप से आंका गया था जिसमें शिक्षाविद, पत्रकार और विचारक शामिल हैं। बोर्ड की अध्यक्षता कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज के साथी प्रोफेसर साइमन गोल्डहिल ने की है।

(Source:https://www.thehindu.com/books/books-authors/indian-writer-annie-zaidi-wins-100000-global-book-prize/article27282739.ece**)**

G.S.अकादमी (KAPOORTHALA ,CHANDRALOK TOWER ,ALIGANJ LUCKNOW) +919473893577
http://gsacademycivil.com http://testseries.gsacademycivil.com